Haryana Vidhan Sabha

Debates

20th February, 1970

Vol. 1 No. 6

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 20th February, 1970

	Page
Starred Questions and Answers	(6)1
Written Answers to Starred Question laid on the Table under Rule 45	(6)22
Unstarred Questions and Answers	(6)44
Message from the Governor re- Motion of Thanks	(6)65
Ruling by the Speaker	
Re-leave of absence from the Assembly Sitting for one day to a Member	(6)65
Call Attention Notices	(6)65
Papers laid on the Table	(6)66
Discussion on Demands for Supplementary Estimates (Second Instalment) 1969-70	(6)66
Obituary Reference	(6)96

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 20th February, 1970.

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector-1, Chandigarh, at 9.30 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ram Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Irrigation facilities to arid areas of Bhiwani and Loharu

***555. Major Amir Singh Chaudhry:** Will the Minister for Inigation and Power be pleased to state:-

(a) Whether Government has recently taken any decision to provide canal irrigation facilities to some arid areas of Bhiwani and Loharu Tehsil in Hissar District ; if so, the details of the salient points of the projects together with village-wise break-up of the Gross Acreage proposed to be commanded thereby ;

(b) The total estimated capital outlay on the said project, together with the annual recurring expenditure thereon and also income to be annually derived thereby;

(c) Whether work on the said project is already in progress, if so, the latest position relating to the achievement

made so far and the target date fixed for the completion thereof; and

(d) Whether there is any proposal under consideration of the Government to cover arid areas of Mohendergarh district also with canal irrigation; if so, full details of the various schemes and the time schedule for the implementation thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal): The requisite information is laid on the Table of the House.

Irrigation facilities to arid areas of Bhiwani and Loharu

a. The Jui Lift Irrigation Scheme is being executed for providing Irrigation facilities to some arid areas of Tehsils Bhiwani and Loharu of District Hissar.

The salient features of the project are:-

(i) Total discharge at Head	250 Cusecs.
(ii) Total length of channels (approx.)	107 miles
(iii) Number of lifts	7 No.
(iv) Gross area to be commanded	82060 acres
(v) Net culturable area	65600 acres.

List of the villages to be benefited is laid on the Table of the House (Annexure A) It is not possible to indicate the area-wise break up at this stage.

(b)

(i)	Total estimated cost of the Project	Rs. 367.32 Lacs.
(ii)	Anticipated annual working expenses	Rs. 20.48 lacs.
(iii)	Anticipated Annual Receipts at present water rates.	Rs. 5.45 lacs.
(iv)	The cost benefit ratio	Rs. 7.6 : 1 with 10 per cent nterest and 9.3 : 1 with 6 percent interest.

(c)

(i) Yes. The work was taken in hand in November, 1969.

(ii) 205.00 lacs c.ft. of earthwork has been done upto end of January, 1970.

(iii) Jui Feeder from R.D. 0. to 173400 (Tail) and Jui Canal from R.D. 0.50500 is planned to be completed upto

June 1970. the remaining protion of the Scheme is proposed to be completed in all respects by June, 1971.

(d) Yes. The Scheme being under investigation, details would be available after the investigations are completed.

ANNEXURE 'A'

List of villages to be commanded under Jui Lift Irrigation Scheme (As per project.)

1. Chainpura
2. Lohani
3. Asalwas Dubia
4. Asalwas Merhalta
5. Tatani
6. Kher Pura
7. Hantampura
8. Legha Hetuan
9. Nakta
10. Golagarh
11. Patharwali
12. Nangla

13. Basna
14. Jui Khurd
15. Jui Kalan
16. Dhangarh
17. Kairu
18. Chanda
19. Dhabdhan
20. Bijana
21. Karal
22. Khariabas
23. Indiwali
24. Ladianwali
25. Deorala
26. Gopalwas
27. Surpura Khurd
28. Surpura Kalan
29. Bahel
30. Obra
31. Patwan
32. Saheryar

33. Noonsar

34. Hariawas

35. Kasni Kalan

36. Mandholi

37. Serla

38. Gakal Pura

39. Bardoo Chaina

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या मिनिस्टर महोदय यह बतलायेंग कि आया यह पलो इरीगेशन होगा या लिफ्ट इरीगेशन होगा और अगर दोनों का हो तो वह कितना कितना होगा ?

श्री के.एल. पोसवालः 35 मील तक जो फीडर बने हैं वह फलो होगा और उसके बाद लिफ्ट इरीगेशन होगा।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या मंत्री महोदय यह बतलायेगे कि बगैर लिफ्ट के तिना एरिया ईगेट होगा और कितना लिफ्ट के साथ होगा ?

श्री के.एल. पोसवालः अभी चकबन्दी नहीं हुई है इसलिए कह नहीं सकता।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः हर एक प्राजैक्ट का स्पीकर साहब, एक फिजिबिलिटी प्लान बनता है जिसमें सब कुछ दर्ज होता है।

Mr. Speaker: I am sure, if it is there in the project the hon. Member will get the information.

श्री मंगल सैनः इस स्कीम से लौस कितना होगा ?

श्री के.एल. पोसवालः मैं लौस से मतलब नहीं समझा, स्पीकर साहब ?

श्री अध्यक्षः इनका मतलब यह है कि जो पैसे किए जा रहे हैं क्या पेईंग प्राजोजीशन है ?

श्री के.एल. पोसवालः कोई भी प्राजैक्ट पेईंग नहीं होता। देखना यह होता है कि नेशन को कितना फायदा होता है।

श्री मंगल सैनः इसमें जो आपने स्कीमें बनाई है, क्या भोलागढ़ शामिल है ?

श्री के.एल. पोसवालः है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः जो प्राजैक्ट लिफ्ट की है, उसकी हाईट कितनी होगी ? क्या बतलाने की तकलीफ करेंगा आप ?

श्री के.एल. पोसवालः यह टैकनीकल सी बात है।

(At this stage Major Amir Singh rose in his seat.)

श्री मंगल सैनः इनको इन बातों का पता नहीं है, क्यों पूछे जा रहे हैं आप। If it is a technical matter, the hon. Minister must have known it.

Mr. Speaker: The hon. Member Major Amir Singh, will get the answer.

मेजर अमीर सिंह चौधरीः जनाब इसमे हाईट होती है।

श्री अध्यक्षः यह टैक्नीकल बात है, इन्हें याद नहीं।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः क्या वजीर साहब बतलाऐंगे कि इसमें दादरी तहसील का एरिया क्यों नही शामिल किया गया ?

श्री के.एल. पोसवालः अभी यह फर्स्ट फेज है इसको जहां तक बढ़ा सकेंगे बढ़ायेंगे। यह 12 लाख के करीब ऐसा एरिया है जिसमें पानी नहीं है।

श्री बंसी लालः जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वह दूसरी स्कीम के तहत आएगा और वह स्कीम अगले साल शुरू होगी।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः कोई बात नहीं। मैं तो इससे खुश हूं कि मेरी ससुराल में नहरी पानी जा रहा है। (हंसी) लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपका सोर्स क्या होगा, इस नहर के पानी लेने का ?

श्री के.एल. पोसवालः जमुना से लेंगे।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः यह नहर पैरीनियल है या नान पैनिनियल ?

श्री के.एल. पोसवालः नान पेरीनियल।

श्री मंगल सैनः यह शिकायत आई है स्पीकर साहब, कि भिवानी तहसील में पानी ले जाने के लिए रोहतक जिले का पानी काट कर ले जाया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः यह नान–परिनियल है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः इस नहर के अन्दर पुलों की ऊंचाई में augmentation की गुंजायश रख रहें हैं कि नहीं ?

श्री के.एल. पोसवालः हां, गुंजायश रखी जा रही है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः जनाब इन्होंने दादरी लिफ्ट स्कीम के बारे में जवाब दिया है:–

"Yes. The scheme being under investigation, details would be available after the investigation are completed."

श्री बंसी लालः मैंने यही अर्ज किया कि यह स्कीम बन रही है उसमें सतनाली और महेन्द्रगढ़ आएगा।

श्री के.एल. पोसवालः वह दादरी लिफ्ट स्कीम आलरेडी चालू हो चुकी थी लेकिन उनकी टैक्नीकल मंजूरी नहीं आई। ड्रेन

नंम्बर 8 से पानी लेना था मगर उसमें पानी नहीं है। वह स्कीम अभी टैक्नीकल मंजूरी के लिए गई है, अगर मंजूर कर दी गई तो उसे भी शुरू करूंगा।

श्री अध्यक्षः मुझे अफसोस यह है कि शकुन्तला जी ने कुछ नहीं कहा, हालांकि इनका इलाका भी इतना ही बैकवर्ड है।

श्रीमति शकुन्तलाः स्पीकर साहब, इनको पूछो तो हाउस में तो बतलाते नहीं कहते हैं कि घर पर आओ (हंसी)। हकीकत यह है कि यह सुनने के लिए तैयार नहीं।

Mr. Speaker: I suggest, that this should always be the mood of the House.

मेजर अमीर सिंह चौधरीः स्पीकर साहब, लेडी मैम्बर ने बड़ा अहम प्वायंट उठाया है, मुझे तो, कोई बात नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब बेशक कोठी में बुला लें या दफतर में बुला लें मुझे तो किसी किस्म का डर नहीं, लेकिन लेडी मैम्बर को यहां पर ही बता दिया करें।

श्री बंसी लालः मैंने स्पीकर साहब न ही कभी उनको अपने घर पर बुलाया है और न ही अपने दफतर में बुलाया है।

Mr. Speaker: The Hon. Lady Member has the permission to see the Chief Minister in the office whenever she wants.

श्रीमति शकुन्तलाः स्पीकर साहब कल जब सवाल पूछा था तो पासेवाल साहब ने कहा था कि आप मेरे आफिस में आ जाना और आज इन्होंने कहा है कि मेरी कोठी पर आ जाना। स्पीकर साहब यह क्या बात हुई, यह तो हमें बदनाम करना चाहते हैं। (हंसी)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब मैंने तो अपने बटेऊ को अपने घर पर बुलाया हैं। (हंसी)।

श्री दया कृष्णः स्पीकर साहब मेजर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे तो डर नहीं लेडी मैम्बर को डर होगा। क्या मेजर साहब बतायेंगे कि उनको क्या डर है ? (हंसी)

मेजर अमीर सिंह चौधरीः That was not the question at all. मेरा तो जो मुख्य मंत्री साहब के साथ ताल्लुक है वह किसी का शायद नहीं हो सकता।

Mr. Speaker: Next question.

Sh. Daya Krishan: Supplementary Sir.

Mr. Speaker: Not now.

Supply of Tube-well water

***557. Dr. Malik Chand Gambhir:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state whether the water of the Tube-wells, installed on or near the banks of Yamuna

Canal, is supplied to the nearby fields; if so, the quantum of such water being supplied to the said fields and the rate at which it is being supplied?

Irrigation and Power Minister (Sh. K.L. Poswal): Yes. The water is supplied to owners of the nearby field, on application from 15th July, to 30th September only. The total quantity of water supplied from these tube wells on the basis of electricity consumed during the past two years is on an average 32000 units per year. The water is supplied at the rate of Rs. 0.25 per unit of electricity consumed for running the tube wells.

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः वजीर साहिब ने बताया है कि 15 जुलाई से लेकर 30 सितम्बर तक आस पास के खेातों वाले किसानों को देते है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बाकी के महीने होते हैं उनमें उन्हें पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री के.एल. पोसवालः बात यह है कि यह औगमेंटेशन ट्यूबवैल हैं इनसे उस वक्त पानी लिया जाता है जिस वक्त नहर में पानी की कमी होती है। जब नहर में पानी ज्यादा होता है और इनका पानी उसमें डालने की जरूरत नहीं होती उस वक्त हम किसानों को दे देते हैं।

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः जिन तीन महीनों में आप पानी देते है। उन दिनों में तो वैसे ही पानी काफी होता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि जिन दिनों में पानीक की कमी होती है उन दिनों में उनको पानी क्यों नहीं दिया जाता।

श्री के.एल. पोसवालः मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह औगमैटेशन ट्यूबवैलज हैं और वहां पर पानी का लैवल चूंकि काफी ऊंचा है इसलिए किसान थोड़े से पैसे खर्च करके अपने ट्यूबवैल लगा सकते है। यह ट्यूबवैल तो उनके लिए लगाए हैं जिन के खेतों तक टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता।

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः जहां तक, जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता जैस कि आपने फरमाया है उनको अगर पहले पानी न मिल रहा हो तो क्या आप उनकों पानी देतने के लिए तैयार होंगे ?

श्री के.एल. पोसवालः अगर कोई ऐसा केस है तो उनको दिया जाएगा।

श्री मंगल सैनः क्या आपके सिंचाई विभाग के पास उस इलाके के जमींदारों ने कभी यह मांग की है कि नवम्बर से लेकर फरवरी तक भी हमें पानी दिया जायें ?

Sh. K.L. Poswal: Not to my knowledge.

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः स्पीकर साहिब अभी डाक्टर मंगल सैन जी के सवाल के जवाब मैं श्री पोसवाल साहिब ने कहा है कि मेरे नालेज में नहीं है कि कभी वहां के किसानों ने पानी के लिए मांग की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो दफा मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहिब को डैपुटेशन लेकर मिला और एपलिकेशन्ज

भी दी कि हमें पानी दिया जाये लेकिन उसके बाद कोई विचार नहीं हुआ।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): वह मुझे मिले होंगे और मैंने एप्लिकेशन्ज जो उन्होंने दी होंगी महकमें को डील करने के लिए भेज दी होंगी।

Mr. Speaker: You may like to go into it.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब आनरेबल मैम्बर कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर साहिब को मिला था और चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मिले होंगे। मैंने अभी सवाल किया था कि क्या आप को कभी कोई डैपुटेशन मिला और आपको उन्होंने कोई दरखास्त दी ..... । (विघ्न)

Mr. Speaker: He merely said 'Not to my knowledge'.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब जब कोई सवाल आता है तो डिपार्टमेंट कंसर्न्ड इनको सारी बैकग्राऊंड से इक्विप करता है। इसलिए इनको पता होना चाहिए था कि इनको कोई एप्लिकेशन मिली या नहीं मिली ?

Mr. Speaker: It appears that it was not brought to his notice. He will, however, look into it. He has agreed to.

चौधरी लाल सिंह: मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस इलाके से यह नहर निकलती है, जो कि

जमुना को पार करती है, उस इलाके के जमींदारों को क्यों नहीं पानी दिया जाता ?

श्री के.एल. पोसवालः जिस इलाके के लिए मैम्बर साहब पूछ रहे हैं वहां पर जमीन नहर के लैवल से ऊंची है लेकिन जहां जहां भी पानी पहुंच सकेगा हम कोशिश करेंगे पानी देने की।

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहब मैं सवाल पूछने से पहले निवेदन करना चाहता हूं कि क्वैश्चन आवर में सरकार या हां में जवाब दे सकती है या न में और या समय मांग सकती है। कभी आए होंगे या भेज दी होंगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि इसके बारे में आप को अपनी रूलिंग देनी चाहिए, इस वक्त मैं इसके साथ ही अपना सप्लिमेंटरी सवाल भी पूछ लेना चाहता हूं।

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जहां जहां नहर ाके औगमैन्ट (पानी का बढ़ावा) करने के लिए ट्यूबवैल लगाए हुए हैं उनके साथ साथ वहीं के लोगों की पानी की मांग को पूरा करने के लिए सरकार एक एक और ट्यूबवैल लगाने के लिए तैयार है कि नहीं क्योंकि उस पर तो कुछ लाईन वगैरा का खर्चा नहीं होगा ?

श्री के.एल. पोसवालः मैं इस बात को एग्जामिन करवा सकता हूं, इस वक्त औफहैंड कुछ नहीं कह सकता।

Mr. Speaker: It is apparent that it is a sound suggestion.

Sh. K.L. Poswal: It is a good suggestion.

(At this stage Ch. Ranbir Singh rose in his seat).

Mr. Speaker: You earlier refered that a Minister can only say "yes" or "no" in reply to a question. I cannot find any rule of that nature.

श्री बंसी लालः चौधरी साहब ने एतराज किया है कि मैने यह कहा है कि वह मिले होगे और मैने उनकी एपलिकेशन्ज भी आगे भेज दी होगी। यह मैने इसलिए कहा है कि महकमा नहर की बहुत सी एपलिकेशन्ज आती रहती है ओर हरेक को याद नही रखा जा सकता इसके इलावा महकमा नहर की बहुत सी एपलिकेशन्ज ऐसी होती है जो कि जूडिशियल नेचर की होती है जिनके ऊपर कि मै अपनी तरफ से काई ऐकशन नही ले सकता और वह एक्स.ई.एन. या एस.ई. करे भेजनी पड़ती है। चौधरी साहिब तो खुद इस बात को जानते है।

Mr. Speaker: I think, his question was different. I cannot find any rule which says that the Government is obliged to say 'yes' or 'no'. But, you can enlighten me about it.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय इस सिलसिले में मै आपसे आपके चैम्बर में आ कर बात करूंगा। इस वक्त मै सप्लिमेंटरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि आया महकमा नहर को यह सुझाव सरकार की तरफ से पहले भी

दिया गया था कि जहां पर डायरैक्ट टयूबवैल्ज लगहे हुए है उनके साथ साथ शैलों टयूबवैल लगा दिए जायें ताकि वहां के लोगों की मांग पूरी की जा सके और वाटर लैबल भी नीचे जा सके।

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहिब शैलों टयूबवैलज् का केस माईनर इरीगेशन में आता है और वह एग्रीकल्चर वाले डील करते है।

Mr. Speaker: But that was with you till recently.

श्री के.एल. पोसवालः नही, जी, वह उनके पास ही है।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय की जानकारी के लिये अर्ज कर दूं कि मेरे पास काफी समय तक यह सिंचाई ओर बिजली विभाग रहा है और मुझे पता है कि यह काम भी सिंचाई मंत्री के पास ही रहा है हमेशा और ड्रैनेज का भी यह पार्ट है क्योकि वाटर टेबल को नीचा करने के लिये जहां सरफेस ड्रेनेज है वहां शैलों टयूबवैल्ज भी उसका ही पार्ट होता है। गर अब यह महकमा उनके पास नही है तो दूसरी साथी से पता करके क्या वह जानकारी लेकर जानकारी देने की कृपा करेगे?

श्री के.एस.पोसवालः मुझे नोटस दे दे, मै जरूर पता करके बता दूंगा।

Mr. Speaker: It is go of the welfare of the people. We will try to get, Ch. Sahib, in the next few days.

चाञ्चैधरी लाल सिंहः मै वजीर साहब से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह गुड़गांव में लिफ्ट इरीगेशन से पानी दिया जा सकता है ो क्या उस तरह हमारे यहां भी दिया जा सकता है या नही और क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है?

श्री के.एल. पोसवालः यहां यह स्कीम कामयाब नही हो सकेगी। नारायणगढ़ में एक स्कीम बनाई है कि 200 के करीब वहां टयूबवैल्ज लगाये जोयं और 40 के करीब लग चुके है बाकी काम चालू है।

श्री अध्यक्षः यह ठीक है कि चौधरी लाल सिंह का हलका निहायत गरीब है। इसलिए उसका कुछ न कुछ इन्तजाम होना चाहिए।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब इसमें कोई शक नही कि सरकार वहां पर काफी ध्यान दे रही है और काम कर रही है। लेकिन चलते बैल को ज्यादा चोभ लगती है। (हंसी) तो मै अर्ज करता हूं कि यहां पर इन्होने टयूबवैल लगाने का एरिया बनाया हुआ है। मै जाननता चहाता हूं कि अगर उस एरिया से बाहर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो क्या सरकार वहां भी लगाने के लिये तैयार है या वहां एरिया में ही लगायेगी?

श्री के.एल. पोसवालः यह भी देख लेगे अगर वह एरिया से बाहर है और वहां पानी अवलेलेबल है तो वहां पर भी कन्सिडर कर लेगे।

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मंत्री महोदय जैसा कि उन्होने पहले कहां कि वहां खेती की जमीन ऊंची है उस जवाब को ध्यान में रखते हुए बतायेगे कि जमुना नहर का कौनसा हिस्सा ऐसा है जाहां पर साथ की जमीन ऊंची है वहां खुदाई की नहर है और वहां नीची है वहां बंधई की नहर है? क्या वह बतायेगे कि कौन कौन हजारे में खुदाई की नहर है जिसका वह कि जिक्र कर रहे है?

श्री के.एल. पोसवालः इस सवाल से तो यह सप्लीमेंटरी एराईज होता नही है क्योंकि यह तो टयूबवैल्ज के बारें में पूछा गया है।

चौधरी रणबीर सिंहः मै इसकी जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि जो डायरैक्ट टयूबवैल्ज है उनका मतलब यहा हाता है कि उनका पानी पहले एक छोटे से पक्के चैनल में डलता है और फिर नहर में डलता है जितनी वह नही है यह सारी कीसारी बंधी की लहर है खुदाई की नही हैं अगर खुदाई का कही हजार, पांच सौ गच का टोआ हो तो वह बता दें। तो मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो उन्होने जवाब दिया है वह इस नाते दरूस्त है या नही अगर दरूस्त नही है तो पहले वाला जा जवाब है उसको दरूस्त करें?

श्री के.एल. पोसवालः मै दरूस्ती करने के लिये तैयार हूं अगर कही गलती हो लेकिन इसमें तो बात सीधी यह पूछी गई है

कि टयूबवैल्ज कितने है। हम डायरैक्ट टयूबवैल्ज उनकों कहते है जिन से डायरैक्टली फील्डज में पानी देते है और दूसरे अगमैटेशन टयूबवैल्ज जै जिन से नहर में पानी डालते है जो आप पूछना चाहते है और पूद रहे ळै उसके लिय नोटस दे दें बता देंगे।

चौधरी रणबीर सिंहः मै मंत्री महोदय को बता सकता हूं लेकिन मै निवेदन करता हूं कि रूल्ज के मुताबिक और सदस्य के नाते पूछ ही सकता हूं। तो मै पूछना ही चाहता हूं कि जैसा कि उन्होने बताया उसके मुतागिक वह एक ही ऐसे टयूबवल का नम्बर बता दे जो उस नहर में सीधा पड़ता हो। जैसे मैने पहले भी निवेदन किया जिनको डायरैक्ट टयूबवैल कहते हैउनके लिये एक पक्का चैनल बना होता है उसमें उसका पानी डालते है अैर फिर उस चैनल का पानी नहर में पड़ता है। वह चैनल खुदाई का नही है अगर कही हजार पांच सौ गज खुदई का है ते वहा बता दे वरना पहले वाला जो जवाब है उसमे दरूस्ती कर दे या समय मांग ले बाद मे ंपता करके बता देना।

मलिक सतराम दास बतराः क्या इस तरह के और टयूबवैल लगाने का सरकार का कोई इरादा है अैर अगर है तो कितने लगाये जयेगे?

श्री के.एल पोसवालः हमारा 128 टयूबवैल लगाने का इरादा है जिनमें से 30 के करीब लग चुके है।

श्री सत्य नारायण सिगोलः कोई साल डेढ़ साल से जींद से नहर जमन गरबी से जो पानी मिलता था उसमें एक चौथाई की कमी हो चुकी है अेर अब जूई स्कीम के बाद जींद सबडिवीजन में और भी ज्यादा पानी की कमी हो जायेगी। मूलक फाल और मुआना फाल का बहुत ज्यादा पानी जमअीन में है क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाने के लिये तैयार है कि वहां पर शैलों टयूबवैल लगर कर और जूई स्कीम से जींद सबडिवीजन को आगे पानी दिया जाये?

श्री बंसी लालः अगर इस तरह का पानी जींद में वहां अबेलेबल हो तो सरकार बड़ी खुशी के साथ टयूबैल्ज लगायेगी लेकिन जैसा मैम्बर साहब ने कहा कि जूई स्कीम के बाद जींद में पानी की कमी हो जायेगी और यह कि पहले भी वहां पानी कम दिया जा रहा है यह बेबुनियाद अलजाम है जितना पानी है वह उसी तरह मिलता है। जूई स्कीम का भी वहां पर कोई असर नही होना है क्योंकि वह बरसाती पानी होगा।

(Sh. Satya Narian Syngol rose to speak)

Mr. Speaker: The Chief Minister has said that the quantum of water for various areas will remain the same and rainy water will be supplied for this scheme.

श्री सत्य नारायण सिगोलः क्या मंत्री महोदय इस बात की इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार है कि जो मेरियां अब से दो

महीने पहले जिस साईज की थी उनका अब दो महीने के बाद कितना साईज रह गया है जींद से स्फीदों सब–डिवीजन में?

श्री के.एस.पोसवालः मुझे कोई एतराज नही इन्कवायरी करवा लेगे।

श्री बंसी लालः इन्कवायरी करा लेगे अगर कोई सपैसिफिक कम्पलेंट आयेगी तो। पिछले दो तीन महीने से कई जगह राता को छापे मारने के लिये टीम भेजी गई जांच के लिये क्योंकि शिकायत थी कि टेल तक पानी नही पहुंचता है। उसका असर यह हुआ कि टेल तक पानी पहुंचने लगा अैर सुधार हुआ। इसके लिये मैम्ब्र साहब को सपैसिफिक मोरियों के नम्बर देने होगे ताकि इन्कवायरी करके बता सकें।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः इन्होने अभी फरमाया है कि रेड कराये गये और मोरियों ठीक कराई गई। इसका मतलब है कि मोरियां पहले गलत थी जो बाद में ठीक हुई। तो क्या मुलाजमों के खिलाफ सरकार कोई ऐक्षन लेगी जिन्होने ऐसा किया है?

श्री अध्यक्षः आप सब जानते है कि यह मोरिया कम और फालतू होती ही रहती है।

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः मै वजीर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि गाज से 15/20 साल पहले हमारे हां पानी का स्तर काफी ऊंचा था ओर उस वक्त सेम की शिकायत थी जिस के कारण टयूबवैल लगाये गये और लोगों ने भी अपने

टयूबवैल्ज लगा लिये। अब पानी का लैवल नीचा चला गया है अैर लोगों को लगाये शैलों टयूबवैल्ज फेल हो गये है और इसकी शिकायते आ रही है। तो क्या सरकार उनको अपने डीप टयूबवैल्ज से पानी देगी?

Sh. K.L. Poswal: We will consider it.

Mr. Speaker: Let me just continue my remarks on the Question regarding a decrease and increase in water, it is not the faulf of the Government. In many cased, th efault lies elsewhere.

श्री दया कृष्णः स्पीकर साहिब, मेरी गुजारिश यह है कि क्या मिनिस्टर साहिब इस बात पर जांच करवाने के लिए तैयार है कि डिस्ट्रिक्ट जींद में पहले की निस्बत बहुत कम पानी है और लोग बहत तंग है?क्या इस तंगी को ध्यान में रखते हुए पहले से ज्यादा पानी मुहैयाय करने के लिये सरकार कोशिश कर रही है?

श्री के.एस. पोसवालः जी हां, कोशिश कर रहे है।

Mr. Speaker: I think, you will agree with me that after reparis and desilting in the Western Jamuna Canal, such a complaint should not be prevalent now.

श्री दया कृष्णः स्पीकर साहिब, पानी में जो कमी हुई है वह डी–सिल्टिग की वजह से नही हुइ। यह ठीक है कि हम बेहद तंग है, ानी की कमी की वजूहात का हतें पता लगना चाहिए।

Mr. Speaker: I also move out and I know for certain that there has been an increase in the supply of water during the last few months.

श्री दया कृष्णः स्पीकर साहिब, जींद डिस्ट्रिक्ट में बेहद तंगी होनी के वजह से लोग सरकार को बदनाम करते है इस कमी की इन्क्वायरी करें और कोशिश करके ज्यादा पानी बढ़ाना चाहिए?

श्री बंसी लालः स्पीकर साहिब, असल में पिछले साल पानी पीछे से ही कम आया है, जींद में ही नही, सभी जगह यह शिकायत थी कि पानी कम मिला है, इसकी फरदन इन्क्वायरी करने की कोई आवश्कता नही है क्योंकि जितना पानी हिसाब के मुताबिक जाना चाहिए था वह जाता रहा।

Mr. Speaker: Well, I can say that I have received in assurance, or say that I have been told, that there is now queite an adequate supply of water. And, it is because of desilting and probably due to arrangements of more water from some source that the position has improved. That is all I can say.

श्री बंसी लालः अगर हमें ज्यादा पानी मिल गया तो जींद के लिए सरकार जरूर पानी का इन्तजाम करेगी।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न टयूबवैल्ज के बारें में था लेकिन इसमें नहर भी आ गई, मोघे भी गये इसलिए अगर आप इजाजत दें तो मै एक सवाल नहर के बारें में कर दूं?

श्री अध्यक्षः अब तो आपकों इजाजत देनी ही पड़ेगी, आप पूछ सकते है।

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि डी–सिल्टिग से पहले वैस्टर्न जमुना कैनाल की कपैसीटी कितनी थी। दरिया जमुना से हरियाणा को जो पानी मिलता है उस कपैसीटी से ज्यादा पानी किन किन महीनों में था या किन किन महीनों में होता है?

श्री बंसी लालः इस वक्त कुछ कहा नही जा सकता, इसकों ऐन्जामिन करके देखेगे।

Mr. Speaker: We will try to get the answer for the hon. Member after 4/5 days. We now come to the next question-640 for which an extension has been souht upto tenth March.

Voice: The session is only up to 4th March.

Mr. Speaker: I will discuss this matter with the Leader of the House and see if we can get the answer during the current session.

Sh. Daya Krishan: We must get the answer, Sir, during the present session.

Mr. Speaker: I cannot assure you at the moment, but I shall try.

Cases Against Gazetted an Non-Gazetted Officers

***640 Sh. Daya Krishan:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) The number of disciplinary cases initiated and decided form 1st January, 1969 to 31st December, 1969 against gazetted and non-gazetted officers, separately;

(b) Number of gazetted and non-gazetted officers punished during the period referred officers, separately;

(c) The steps, if any, the Government proposes to take to reduce corruption in the Sate?

Chief Minster (Sh. Bansi Lal):

(a) (i) Cases initiated:

Gazetted	118
Non-Gazetted	3,987

(ii) Cases Decided:

Gazetted	56
Non-Gazetted	3,100

(b)

Gazetted	56
Non Gazetted	2,235

(c) With a view to reducing corruption in the state the Government has further strengthened the Vigilance Department and increased the staff under it. The Vigilance Department has been placed under a Senior Police Officer of

the rank of D.I.G. The field units have been set up in the Districts who will also collect intelligence about corrupt officers. Raids will be conducted to catch the corrupt officers red handed.

Farmers owing less that five standard acres of land

***659. Sh. Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state the total number of land ownes in the state, distrucwise, who own less than five standard acres of land?

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): वांच्छित सूचना इस विभाग में उपलबध नही है। सूना एकत्रित करने में जा`समय और परिश्रम लगेगा उससे कोई विशेश लाभ नही होगा क्योंकि ये आंकडऋे समय समय पर बदलते रहते है।

श्री रणबीर सिंहः स्पीकर साहिब, वित्त मंत्री महोंदया ने अपने जवाब में लिखा है–''वांच्छित सूचना इस विभाग में उपलब्ध नही है'' जब कि हरियाणा स्टेट ने 5 एकड़ से कम जमीन वालों पर से लैड रैवेन्यू माफ किया है।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः कोई माफ नही किया है।

श्री रणधीर सिंहः अगर नही माफ किया है तो मै पूछना चाहता हूं कि समाज वाद लाने के लिए, जिन जमीदारों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उन पर से लैड रैवेन्यू माफ करना चाहिए और जिन के पास पांच एकड़ से कम जमीन है वह अन

इकनोमिकल हो गइ है इसलिए सरकार के पास इसकी इन्फर्मेशन होनी चाहिए।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः स्पीकर साहिब, मैने जाती तौर पर इस बात की कोशिश की है कि इस सवाल की इन्फर्मेशन प्राप्त की जाय और हमने सैसस कमिश्नर को लिखा था लेकिन इसमें बहुत बेरिएशन्ज है। 1966 में सर्वे हुआ था, 1967 में भी हुआ था और उसके बाद अब फिर इन्फर्मेशन मंगवाई है लेकिन इसमें बहुत बेरिएशन्ज है क्योंकि कोई गिफ्ट में जमीन दे देता है, कोई बेच देता है, कोई खरीद लेता है, इसलिए 5 स्टैडर्ड एकड़ की सूचना उपलब्ध करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लिख रहे है ताकि अगले साल इन्फर्मेशन आ जाये।

Mr. Speaker: I feel that this information will serve very useful purpose for deciding certain policy in this matter.

Smt. Om Prabha Jain: We will write to the Census Commissioner, Government of India, in the connection. But, we do not know whether they will supply the requisite information.

Mr. Speaker: But, you have you own staff. They should be able to help you in this matter.

श्रीमती ओमप्रभा जैनः अगर आज सैसस करें तो छः महीने के बाद वेरिएशन हो जाती है। अगर कोशिश करके फिगर इकट्ठी भी की जाएं तो छः महीने के बाद बदल जाती है।

Mr. Speaker: But, I thing the information is very good and will help you in many things.

मेजर अमीर सिह चौधरीः स्पीकर साहब, हर एक गांव में पटवारी है, वे दिल्ली से तो नही आयेगे, पटवारी सारा काम कर सकते है।

श्री बंसली लालः पटवारी इसमें क्या कर सकता है, एक आदमी के पास पांच एकड़ जमीन है अैर कल को वह कुछ जमीन बेच देता है या खरीद लेता है तो इन्फर्मेशन ठीक नही हो सकती।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साााााहब, आपने उनकी बात का विश्लेशण करते हुए कहा कि यह काम हो सकता है और फिनांस मिनिस्टर महोदया ने भी अश्योरेंस दी है लेकिन मुख्य महोदय कहते है कि यह नही हो सकता.....

श्री अध्यक्षः मै समझता हूं, जो चौधरी अमीर सिंह ने फरमाया, इससे हो सकता है लेकिन यह जरूर है कि इसमें वेरिएशन्ज बहुत है, खासतौर पर उस वक्त जब कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है। जैसा कि आपने बताया है। अगर यह इन्फेशन इक्ट्ठी हो जाये तो हम सबके लिए अच्छी है, खासतौर पर गवर्नमैंट के लिय ज्यादा फायदेमन्द हो सकती है।

श्रीमती ओमप्रभा जैनः मैने कहा था कि 1966 में सर्वे हुआ था और 1967 में भी सर्वे हुआ था। स्पीकर साहब, फिगर्ज हाउस को देने में मुझे कोई एतराज नही है मगर इसमें एक बात

है कि ये तो सूचना मांगते है स्टैडर्ड एकड़ज में, मगर मेरे पास औडिनरी एकड़ज में है।

श्री अध्यक्षः आप औडिनरी एकड़ज में ही दे दीजिए।

श्रीमती ओमप्रभा जैनः बहुत अच्छा जी। सूचनार इस प्रकार है–

	एकड़
हिसार	1,72,637
रोहतक	2,08,473
गुड़गांव	3,71,638
करनाल	91,764
अम्बाला	1,10,908
महेन्द्रगढ़	1,80,957
जींद	95,404

यह इन्फर्मेशन हमने डी.सीज. से कुलेक्ट की है लेकिन मै कहूंगी कि इसे अनुमानित ही माना जाय।

Mr. Speaker: I think this is very fair. But what we should take about it is that in most cases, they are joint families.

श्री रणबीर सिंहः क्या वित्त मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जिनके पास पांच स्टैडर्ड एकड़ से कम भूमि है उनकी मालगुजारी माफ की जायेगी?

श्रीमती ओम प्रभा जैनः जी नही, ऐसा कोई विचार अभी नही है।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या वित्त मंत्री महोदया यह बताने की तकलीफ करेगी कि जिन लोगों के पास ांच स्टैडर्ड एकड़ भूमि भी नही है उनका गुजारा कैसे होता है और पांच स्टैण्डर्ड एकड़ इकनौमिक होल्डिंग है या नही?

श्रीमती ओम प्रभा जैनः यह तो जनाब मैटर आफ ओपोनियन है।

Mr. Speaker: I agree, it is a question of opinion.

Shrimati Chandravati: No. Sir, ii is not a matter of opinion. It is a question of fact wheter or not five acres are economic holdings.

श्री बंसी लालः स्पीकर साहिब, यह तो एमप्लयामेंट और अन–एमप्यामेंट की बातचीत में आ गई हैं इसका लैण्ड होलिडंग्ज से क्या ताल्लुक है?

Mr. Speaker: Let us be balanced in this matter. Five acres of land in suitable place-very well irrigated will be an economic holding. On the other hand five acress in your

(Shrimati Chandravati's) constituency or in the consitituency of Shrimat Shakuntla Jee cannot called an economic holding.

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरा मतलब तो यही है कि जो इकानोमिक होल्डिग्ज नही है, उनकों सरकार एक्सट्रा एमप्यामेंन्ट देने का कोई विचार कर रही है। या नही? It is the duty of the Government to provide work and atleast the prime needs of life i.e. a house and two meals etc.

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, यह सप्लीमेंन्टरी इस सवाल में से पैदा ही नही होता।

Shrimat Chandravati: Certainly it does arise, Sir.

Mr. Speaker: Really, it is a suggestion rather than a supplementary.

श्री बंसी लालः मेरे ख्याल से यह सजैशन भी नही है। अन–एमप्यामेंट का सवाल परसों यहां आया था और हमने उस पर काफी वाद–विवाद किया था। इसलिए, स्पीकर साहब, एक तो यह सवाल इसमें से पैदा नही होता और दूसरे कोई सजैशन क्वैश्चन अवर के दौरान नही आ सकती।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस तरह से तो हम एक बड़े नाजूक जंक्चर पर आ गए है। आप तो फरमा रहे है कि यह एक प्रकार की सजेशन है मगर मुख्य मंत्री जी कहते है कि सजेशन भी नही है। स्पीकर साहब, मेरी बहिन चन्द्रावती जी ने बड़ा रेलैवेन्ट और टू दी प्वायंट सवाल पूछा है कि क्या पांच

स्टैण्डर्ड एकड़ की होलिडग इकनौमिक होल्डिग है या नही? क्या इससे लोगों का गुजारा हो सकता है या नही?

Mr. Speaker: You know the limit of holding has been fixed at 30 acres. Obviously it is considred to the an economic holding.

श्री मंगल सैनः वह तो कहे। आप उनके रैसक्यू पर क्यों आते है?

संसदीय सचिव (चौधरी गोवर्धन दास चौहान): स्पीकर साहब, चन्द्रावती जी ने यहा तो पूछा कि पांच एकड़ भूमि वालों का गुजारा कैसे होता है? परन्तु मै उनसे जानना चाहता हूं कि देहात में जिनके पास पांच एकड़ भी नही है उनका गुजारा कैसे होता है?

श्रीमती चन्द्रावतीः आप सरकार में है, आप बताये कैसे होता है? यह आपकी डयूटी है?

श्री अध्यक्षः चौधरी गोवर्धन दास जी आप तो उनके प्वायंट को ही सपोर्ट कर रहे है। यह ही तो उन्होने पूछा है? (विध्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, क्या पालियामेन्टरी सैक्रेटरी सवाल पूछ सकते है?

श्रीमती ओम प्रभा जैनः स्पीकर साहब, गुजारा हाता है या नही होतौ, यह कहना तो बड़ा मुश्किल है मगर इतना मै जरूर

कहना चाहती हूंकि जहां कही भी हम काम करना चाहते है या कर रहे है, जैसे जूई कैनाल बन रही है या दूसरे काम है वहां हमें लेबर भी नही मिलती। राजस्थान और दूसरी जगहों से लेंबर मगवानी पड़ती है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, आप मेंरे इस सवाल का जवाव दिलवा दीजिए कि आया 5 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि इकनौमिक होल्डिग है या नही है?

श्री बंसी लालः चेर की रूलिग पहले आ चुकी है कि यह मैटर आफ ओपोनियन है।

Mr. Speaker: We have heard a very high placed dignitary saying that even three acress may be enough. So, is is really a question of opinion. In some places like Japan three acress may b an economic holding for on family whereas in Rajashthan-Barmer thirty acres may not be an economic holding.

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक मुझे मालूम है यह सजैशन तो नही है मगर एलिसिटिग आफ इन्फर्मेशन है। आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने आडिनरी पांव एकड़ की सूचना दी है, स्टैण्डर्ड एकड़ज की इनके पास है नही। अब यह सदन वित्त मंत्री महोदया से यह जानना चाहता है कि पांच एकड़ की ऐसी भूमि को जिसकी न तो टयूबवैल से, न नहर से और न तालाब से सिंचाई होती है, क्या यह सरकार इकनौमिक होल्डिंग मानती या नही और साथ ही साथ यह जाननता चाहता हूं कि क्या

इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन का होना सरकार को अपना काम काज चलाने के लिए जरूरी है या नही।

श्रीमती ओमप्रभा जैनः स्पीकर साहब, अब इसका क्या जवाब दिया जाय?

Mr. Speaker: Let us not go into it. I think this will very from state to state and it is a good thing for Government to consider this matter sometime and find out as to how much lnd they consider to an economic holdig. As you know it varies form five to eleven acres, it is 6 ¼ acres in Uttar Pradesh and 8 acres in Rajasthan. So it varies from state to State as th what is an economic or uneconomi holding, and I think, in view of what we have been saying from various platforms that will have to be thought of and a decision has to be taken.

श्रीमती लेखवती जैनः स्पीकर साहब, मै तो अपनी वित्त मंत्री साहिबा से इतना ही पूछना चाहती हूं कि जिन जमींदारों के पासं पांच एकड़ से कम बारानी जमीनहै, जहां पर कुछ पैदा नही होता, वहां हमारी सरकार क्या टयूबवैल आदि लगाने की कोशिश करेगी या कर रही है कि उनकों पानी की सहूलिय मिलने से उनकी जमीन ठीक हो जाए?

श्रीमती ओमप्रभा जैनः इरीगेशन मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे चुके है।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब सवाल तो बड़ा रेलैवन्ट था लेकिन सरकार तो कहती है कि इसके जवाब की आवश्कता

नही है। सरकार स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट पर इतना पैसा खर्च करती है। और आनरेबल फाईनेन्स मिनिस्टर साहिबा उसकी इन्चार्ज है और प्लानिंग डिपार्टमेंट की भी इन्चार्ज है। इसलिए यह सवाल उनके डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। यहा कोई रेविन्यू डिपार्टमेंट का सवाल नही है। उनकों जवाब देना चाहिए।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः अध्यक्ष महोदय, यह इन्फमेशन मै दे चुकी हूं।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब फाईनेन्स मिनिस्टर साहिबा प्लानिंग और स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज है तो क्या पांच एकड़ जमीन से किसी भी एक फैमिली का गुजारा हो सकता है अगर नही हो सकता तो उसके लिए तजावीज की है?

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब लीडर आफ दी अपोजीशन ने कहां कि फाईनेंस मिनिस्टर साहिबा स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और प्लांनिग की भी इन्जार्च है इसलिए यह बताया जाये की पांच एकड़ क्या इकनौमिक होती है। इस बात का पता लगाना तो बड़ा कठिन है क्योंकि किसी गांव की जमीन में टयूबवैल है किसी की बंजर है दोनों जमीनों की बरबर आमदमी नही हो सकती।

Rao Birender Singh: May I ask the hon. Minister incharge of Revenue how many kinds of lands are there in a village?

श्रीमती ओम प्रभा जैनः यह सवाल कैसे रेलैवेंट हो सकता है कुछ जमीन चाही होती है कुछ नहरी होती है–––

Rao Birender Singh: Of course, this is a very relevant question.

श्रीमती ओम प्रभा जैनः सब किस्म की जमीनें होती है।

Mr. Speaker: I think, it will be difficult to answer awkward question.

श्रीमती ओम प्रभा जैनः जमीन तो सब किस्म की होती है चाही भी होती है, बंजर भी होती है और नहरी भी होती है।

राव बीरेन्द्र सिंहः गलत इन्फर्मेशन दे रही है। ये जमीन की किस्में नही होती है।

Mr. Speaker: This is exactly why I said 'You have asked an awkward question'.

चौधरी रणबीर सिंहः क्या वित्त मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट की और से जो खेती के बारें में सर्वे की किताब छपी है उसके मुताबिक कितने एकड़ जमीन चाहे वह नहरी हो या बंजर हो इकनौमिक होती है और कितने एकड़ अनइकनौमिक समझी जाती है?

श्रीमती ओम प्रभा जैनः यह इन्फर्मेशन पूरी इस समय मेरे पास नही है। यदि आनरेबल मेम्बर पूरी इनफर्मेशन चाहते है तो बाद में देख कर बतला दी जायेगी।

श्री रणधीर सिहः जिन किसानों के पास पांच स्टैडर्ड एकड़ जमीन है, क्या उन किसानों को और सरप्लस जमीन में से देगी?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

Mr. Speaker: We go to the next question. Chaudhry Chand Ram.

Action of Evacuee unallotted land to Harijans

***689 Ch. Chand Ram:** Will the Minister for Finance be pleased to State-

(a) Whether Government has issued any instructions to the effect that the evancuee unallotted land meant for restricted auction be auctioned openly, if the Harijans do not come forward to bid a second time; and

(b) Whether the instalments paid by the Harijans auction purchasers are forefeited, on their failure to pay instalments of auction sales for any reasons?

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): (a) Yes, if the bid offered is not reasonable in spite fo two succesive attempts.

(b) Yes, if the auction purchasers fail to pay two successive instalments of purchase price with interest at the rate of 6 per cent.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब मेरी एक अर्ज है कि यह जो मेर क्वैश्चन है इसका गवर्नमेंट की ओर से जो जवाब आया है वह मुझ अभी मिला है और रोजना ही जब हम हाउस में दाखिल होते है तभी जवाब की कापी दी जाती है। जब विधान सभ के आदमियों से पूछा जाता है तो उनका यही उत्तर होता है कि गवर्नमेंट की ओर से अभी जवाद आया है। इसलिए उनके जवाब हमें कुछ समय पहले मिलने चाहिए।

Mr. Speaker: If you remember, during the last session, I had given a ruling that the copies al all replis would be available with my Deputy Secretary half an hour before the session starts, So, If you had gone there at 9 a.m. and did not get the replies, you could certainly mention this.

चौधरी चांद रामः जैसा कि आपने कहा है कि आधा घण्टा पहले ल लें अगर वहां से कैलैक्ट करने की डयूटी हमारी ही है तो हम ले वरना दफ्तर वालों को हमारे रेजीडेन्स पर भेजना चाहिए। यदि हमारी ही यह जिम्मेदारी है तो हम कुलैक्ट कर लिया करेगे लेकिन भेजना तो दफ्तर वालो को चाहिए।

Mr. Speaker: This has been discussed before. It is just not possible to send you the replies a day earlier.

चौधरी चांद रामः पहले भी तो ऐसा ही होता रहा है।

श्री अध्यक्षः आप अताइये पहले कब ऐसा होता रहा है?

चौधरी चांद रामः पहले पंजाब में यह कनवैन्शन रही है। कम से कम 24 घंटे पहले हमें रिफ्लाई मिलते रहे है। इस विषय में आप पंजाब असेम्बली से भी वेरीफायी कर लें।

मुख्य मंत्री (श्री बंसील लाल): स्पीकर साहब पालियामैंट में ऐसी कनवैन्शन है कि कोई स्टेटमैंट हो तो वह आनरेबल मैम्बर की सीट पर रख देते है। जो सवालों के जवाब होते है वे कवैश्चन आवर के बाद आनरबेल मेम्बर को दे दिये जाते है। यानी क्वैश्चन आवर में जवाब इन राइटिग में नही मिलते है, बादमें मिलते है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य सभा अज़ैर पालियामैंट का यहां हवाला दिया है परन्तु मै चौधरी चांद राम जी की कनटैन्षन को सपोर्ट करता हूं। हमें जो जवाब दिये जाते है उस समय दिये जाते है जब हम हाजिरी लगा रहे होते है।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय मै तो यही कहूंगा कि यह जवाब तभी दिये जाये जब कवैश्चन–अवर खत्म हो जाये वरना फिर तो यह एक डिस्कशन बन जाती है। Then it does not remain a question.

चौधरी चांद रामः फिर सप्लिमैन्टरी कैसे हो सकते है?

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब मै तो यही रिक्वैस्ट करूंगा कि जो पालियामैंट में कनवैन्शन है उसी को फालों किया जाये।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय पहले भी तो हमेशा हमें मिलते रहे है।

श्री अध्यक्षः कितने पहले मिलते रहे है?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब मै कह रहा था कि हमारे पर पालियामैंट की कनवैन्शन न लादी जाये। यदि हमारे हाउस की पहले यह प्रैक्टिस न हो तो पालियामैंट की कनवैन्शन को फालों किया जाये। मै भी 13–14 साल से असैम्बली का मैम्बर रहा हूं। हमें हमेशा पहले जवाब मिलते रहे है।

श्री अध्यक्षः कितने समय पहले मिलते रहे है?

श्री मंगल सैनः यही 24 घंटे पहले मिल गये या दो घन्टे पहले मिल गये। स्पीकर साहब रिटन जवाब देने का तो यही मतलब है कि हमें भी कुछ मालूम हो जाये और हम उसमें से सप्लीमैटरी पूछ सके। अगर कोरी और बहकाने वाली ही बात है तो दूसरी बात है। जवाब तो हमें हमेशा पहले ही मिलते रहे है परन्तु हमारे मुख्य मंत्री सहब पालियामैंट का हवाला भी दे रहे है। स्पीकर साहब यह तो बात जंची नही। हम सवाल भी न करें और गोलियों के बारें में जूडिशियल इन्क्वायरी भी न कराएं और

सवालों का जवाब भी पहले न दें। स्पीकर साहब इतनी ज्यादती तो नही होनी चाहिए।

Mr. Speaker: I will read our something to you about the decision taken in Parliament. The matter was considered a number of times and it was decided that the importance of the Question Hour would disappear if printed answers were districbuted beforehand.

Our Rule 55 Only says—

"Anwers to questions which Minister propsoe to give in the House shall not be relased for publicaton untill the answers have actually been given in the floor of the House or laid on the table."

Now, the point is, it is House that has decided. I am quite sure that there is no question of these answers being given 24 hours earlier or even a day earlier. I am only expressing my personal views. A member when he puts a question, he is natureally concerned about it. He knows every thing about is but asks tht question from the Minister concerned for certain reasons. For example, Major Amir Singh puts questions. His idea is to get certain assurances etc. from the Ministers. So he is well in picture as to what he wants out of qustion. The Minister comes, gets up and gives reply. He knows exactly what he wants to ask resonable supplementaries is not valid. However, I don't mind if the house wants it. If you want 6 hours, two hours or 24 hours it is for you all to decide.

श्री मंगल सैनः एक मिनट सर।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब आनरेबल मैम्बर का यह कहना कि सवाल का जवाब 24 घण्टे पहले उनकों मिले तो यह सवाल नही रह जाता यह तो डिबेट बन जाती है। अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो उसकी कापी पहले मिल जाती है। आनरबेल मैम्बर का यह फर्ज होता है है कि पूरी तरह त्यार होकर आए। मेरी सबमिशन यह है कि सवाल के जवाब की कापी मिनिस्टर से जवाब मिलने के बाद ही मैम्बर को मिलनी चाहिए और यह कापी उसी मैम्बर को मिलती है। जिसने सवाल पूछा है। दूसरे को नही।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। एक मिनट आप सुन ले।

Mr. Speaker: I think we will start supplementaries on this question on Monday.

श्री मंगल सैनः आपने एक बात की कि मेजर साहब सवाल करते है तो कुछ ऐसोरेन्स लेने के लिए करते है। आपके सामने एक क्वैशचन आया कि रिवाड़ी में कितने राउन्ड चले, दादरी में कितने, नानौल में कितने राउन्ड चले। तो उन्होने कहा कि इट इज नोट इन पब्लिक इन्टरेस्ट और मैजीस्टीरयल इन्क्वायरी हो रही है। हम यह जानना चाहते है कि दादरी में एस.उी.एम. ने आर्डर नही दिया तो आर्डर किसने दिया? मेरा सबमीशन यह है है कि मेम्बर से यह आशा करना कि वह तैयार होकर आए यह कैसे हो सकता है। हम फाईल में कैसे जा सकते है। आप फाईल दिखाना नही चाहते। जो इन्फर्मेशन आप इवेड करते है या कंसील

करते है हम उसकों बाहर निकालते की कोशिश करते है। तो मेरी सबमिशन यह है कि क्वैशचन आवर से पहले जवाब मिलना चाहिए। यह हमार वेलिड राइट है यह हमारा प्रिवीलेज हैं इससे हमें वंचित नही करना चाहिए।

Mr. Speaker: You can see ten year ahead. You know all the answers practically. (Laughter)

राब बीरेन्द्र सिंहः नाट नैसैसरली! अर्ज यह है कि क्वैशचन आवर बड़ा इम्पारटेंट होता है और इसमें हाउस की मर्जी क्या है। मैजोरिटी की मर्जी क्या है या गवर्नमैंट की मर्जी कया है इससे हमें कोई सरोकार नही है। इस हाउस की यह प्रैकिटस है, कन्वैशन है और क्वैशनज के मामले में हमें प्रोटैक्शन मिलनी चाहिए। पंजाब अैरउसके बाद ऐसी हजारेां मिसालें है जबकि स्पीकर ने यह देखा कि क्वैशचन का जवाब इन टाइम नही मिला तो उसे पोस्पोन कर दिया अगले दिन के लि। सप्लीमेंटरी होल्ड ओवर कर दी नेक्सट डे के लिए। इस लिए मै दरखास्त करूंगा कि यह प्रैक्टिस बड़ी हैल्दी है और इसकों कायम रखा जाए।

श्री बंसी लालः मै डिफर करता हूं आनरेबल मैम्बर की इस बात से कि क्वैशचन का जवाब 24 घण्टे से पहले मिलना चाहिए।

Mr. Speaker: At the moment i can assure you that I shall foloow the practice wht we have been doing, i.e., half an hour before. But if the Leader of the House or other ask me to

go into it again as the Leader of the Oppositio has done, I am prepared to find it our from other state Legislatures. But I assure you that I hsall certainly maintain the practices that we have been following in Punjab and here.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मेरी एक प्यांयट आफ आर्डर है। कल टीचर्ज के डीयरनेस अलाउंस के बारें में श्रीमती ओम प्रभा जैन ने कुछ जवाब दिया और वह यह था कि कोठारी कमीशन ने यह कहा कि डीयरनेस अलाउंस मर्ज करने के बाद मजीद डीयरनेस अलाउंस देने की जरूरत नही है। मै कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में से एक एक्ट्रेक्ट पढ़ना चाहता हूं (विध्न)। May is read, Sir?

Mr. Speaker: Yes;

Ch. Chand Ram: Sir, I am reading out an extract from the Report of the Education Commission, 1964-66, which is—

"The above rates of pay for school teachers are at the current price level and include the existing dearness allowance. Suitable increase.....

Sir, the word used here is suitable'.

"Suitable incrase will, however, have to be made for rise in prices from time to time. For this purpose there should be parity in dearness allowances, i.e. dearness allowance in any given year should be the same as it is paid to Government servants drawing the same salary.

श्रीमती ओम प्रभा जैनः जो इन्होने पहला सन्टैंस पढ़ा, यही बात मैने कही। इन्होने कहा इनकलूसिव आफ दी प्रैजेन्ट डीयरनैस अलाउंस। पहले यह ग्रेड 1 दिसम्बर, 1967 को दिए और 1 दिसम्बर 1967 से जब दिए गए तो उस समय सिर्फ 1 नवम्बर 1966 को जो डीयरनेस अलाउंस था वही हमने इन्कलूसिव रखा है। बाद में जिना डी.ए. बढ़ा है वह टीचर्ज को बराबर दिया जा रहा है।

Mr. Speaker: This is a point of information.

Smt. Om Prabha Jain: He has confirmed what I have just said.

Mr. Speaker: We can sort out this later.

Ch. Chand Ram: May I request for half an hour discussion on this?

Mr. Speaker: You may make a request. We will certainly consider it.

Ch. Chand Ram: This arises out of a question and any matter which arises out of certain question, cna be discussed by half an hour discussion.

Mr. Speaker: If under the rules you are entitled to it, we can consider it.

श्रीमती ओम प्रभा जैनः स्पीकर साहिब, जब ग्रांटस पर बहस होगी तब ये बोल सकते है।

Mr. Speaker: Naturally before deciding that I would consider what you have said.

(Ch. Chand Ram rose to speak)

You can ask for that. We will consider it.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE UNDER RULE 45

Construction of Sunderpur-Titoli-Kharawali Road

***668. Chaudhry Ranbir Singh:** Will the Minister for Agruculture and Labour be pleased to state:-

(a) Whether the Sunderpur-Titoli, Titoli-Kharwali roads lie in the Rohtak Market Committee area;

(b) The funds sanctioned and deposited with the **P.W.D.** for construction of the above roads;

(c) The breadth of the Zita Parishad road;

(d) Whether it is a fact that the Zila Parishad passed a resolution for handing over the roads to the State Government;

(e) The breadth of the road available for construction of the said roads;

(f) The steps if any, proposed to be taken by the Government to take the entire breadth in possession; and

(g) The period within which the work is likely to be commenced together with the time by which the work is likely to be completed?

Minister for Agriculture and Labour (Chaudhry Ram Singh): (a) Yes.

(b) Rs. 221000 have been deposited by the Market Committee, Rohtak for the construction of six roads in this area including this road.

(c) The original width of this Zila Parishad road was 33' except Kilometer 6 where it was 44 feet.

(d) Yes.

(e) Land available on the spot for road construction is above 20 feet in most of the length but in certain reached it is 30 feet.

(f) Assistance of Civil authorities Rohtak is being sought to take possession of the full land width.

(g) Earth work has been taken in hand on 13th Feburary, 1970 against a cash deposit of Rs. 80000 made by the beneficiaries recently. The work of construction of metalling the road is likely to be completed by 1970-71 if full funds are deposited by the Marktet Committee with **P.W.D.**

Punitive Police posted in the State

***705. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) The names of the places, if any, where punitive police has been posted in the Haryana state during 1970; and

(b) The names of places where from fine or expenditure has been realized in connection with the said punitive Police together with the amount thereof realized in each case?

Chief Minister (Shri Bansi Lal): (a) Nil.

(b) Question does not arise.

Expenditure on maintenance and desilting of Jamuna Canal

***673. Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year wise expenditure, if any, incurred on the maintenance and desilting of Jamuna Canal during the last ten years together with the expenditure, if any, proposed to be incurred thereon during the current year?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal): The requisite information is laid on the Table of the House.

Information regarding maintenance and desilting of Western Jamuna Canal.

The year-wise expenditure incurred on maintenance and desilting of Westgern Jumuna Canal during the last 10 years is given below:-

Serial No.	Year	Amount
1	1959-60	1047483.00
2	1960-61	1946466.00
3	1961-62	1175728.00
4	1962-63	1237065.00
5	1963-64	1935726.00
6	1964-65	1761561.00
7	1965-66	1860364.00
8	1966-67	1425633.00
9	1967-68	1949794.00
10	1968-69	2070971.00

During the current year, a sum of rupees 50 lacs is proposed to be spent over and above the normal expenditure, in connection with the desilting and reconditioning of channels of W.J.C. System under a Crash Programmer.

Expendicture Incurred on Dadri Lift Scheme

***554. Major Amir Singh Chaudhry:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) Whether any expenditure has been incurred on works connected with Dadri lift, Scheme, if so, total amount thereof so far incurred alongwith the amount, if any, which still remains in arrears to be paid in respect of the land already occupied under aforesaid feeder-canal works; and

(b) The time schedule for the completion of the said scheme?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal): (a) An expenditure of Rs. 1424217 has so far been incurred on this scheme. Compensation amounting to Rs. 8.46 lacs is due to be paid in respect of the land already occupied.

(b) The scheme is being reviewed in the Department. It is not possible to give any time schedule at this stage because the technical details are being worked out.

Payment of Wages/Bonus depositedwith Labour Commissioner

***600. Dr. Malik Chand Gambhir:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) Whether the bonus and wages, deposited with the Labour Commissioner, are being paid back to the persons concerned on their demand; if not, the reasons there for; and

(b) Whether any employees of Shri Gopal Paper Mills, Yamuna Nagar who have since left their, Jobs, have applied to the Labour Commissioner, Haryana (Chandigarh) for

getting their bonus and wages; if so, whether the same has been paid and if not, the rreasons therefor?

कृषि तथा श्रम मंत्री (चौधरी रण सिंह): (क) नहीं। जो पैसा बोनस तथा वेतन का श्रम आयुक्त हरियाणा के पास लेबर वैलफेयर फन्ड एक्ट के अधीन प्राप्त हुआ है वह श्रमिकों को नहीं दिया गया। इसका कारण यह है कि बोर्ड नहीं बना था और यह राशि बोर्ड की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती।

(ख) हां। अब बोर्ड की स्थापना हो गई हैं और ऐसे सवालों पर शीघ्र कार्यवाही होगी।

Satta (Dara) In Cities and Towns

***641. Shri Daya Krishan:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) Whether it is in the notice of the Government that Statta (Dara) goes on in many cities and towns of the state;

(b) The number of Satta (Dara) cases challaned by police from 1st January, 1969 to 31st December, 1969, and

(c) The manner in which the Government propose to effectively check this offence?

Chief Minister (Shri Bansi Lal): (a) Yes.

(b) 369

(c) Strict vigil is being maintained over the activities of known satta gamblers.

Teachers placed under supension

***660. Shri Randhir Singh:** Will the Minister for Health and Development be pleased to state the total number of teachers suspended in the state district-wise during the period from September, 1969 to December, 1969 together with the charges levelled in each case?

Health and Development Minister (Chaudhri Khurshed Ahmed): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT OF TEACHERS PLACED UNDER SUPENSION DURING THE PERIOD FROM 1ST. SEPTEMBER, 1969 TO 31ST. DECEMBER, 1969.

Sr. No.	Name, designation and place of posting	Charges
1. Rohtak District (Men Teacher)		
1	Sarvshri-Baljit Singh, G.P.S.	Sisana
2	Om Parkash Manjal	Left the school before closing time.

3	Daya Nand (PTI)	Left the school before closing time.
4	Puran Mal	Left the school before closing time.
5	Mahavir Parshad	Left the school before closing time.
6	Partap Singh	Left the school before closing time.
7	Ram Karan	Left the school before closing time.
8	Sajjan Singh	Left the school before closing time.
9	Raghbir singh	Left the school before closing time.
10	Bhim Singh	Left the school before closing time.
11	Om Parkash	Left the school before closing time.
12	Rattan Singh	Left the school before closing time.
13	Radha Kirshan	Left the school before closing time.
14	Birbal	Left the school before

		closing time.
15	Kishan Dayal	Left the school before closing time.
16	Gobind Ram, G.P.S.,	Rohtak
Did not mark leave in the attendance register in respect of two teachers who were on leave on the 3rd and 4th October, 1969.		
17	Hoshiar Singh, G.P.S. Ghana Khurd	Moral misconduct.
18	Chhaju Ram, G.P.S., Kaundli	Did not another teacher as absent.
19	Abhey Ram, G.P.S., Bhuri	Moral misconduct.
20	Prabhu Dayal, G.H.S., Mandhauthi	Beating of a lady
21	Satnam Singh, G.P.S., Hasangarh	Theft of Keys of school safe.
(Lady Teachers)		
22	Smt. Yashwant Kaur, G.P.S., Kaundli	A bsence from duty
23	Smt. Nand Kaur, G.H.S., Sisana	Ditto
24	Smt. Satya Devi, G.H.S.,	Ditto

	Sisana	
25	Shakuntla Devi, G.H.S. Silana (now at G.P.S., Nigana)	Misconduct.
2. Ambala District (Men Teachers)		
26	Ranjodh Shing, G.P.S., Barauna	Left the school Before closing time.
27	Dina Nath, G.P.S., Baruna	Ditto
28	Khill Ram, G.P.S., Baruna	Ditto
29	Kahar Singh, Rasulpur	Ditto
30	Balbir Singh, G.H.S. Suran	Absence from school.
31	Gian Singh (S.V.) G.H.S. Kot Kalsia	(i) Direct approach to C.M. (ii) Interference in the G.G.M.S. Barwala. (iii) Getting his home address changed in his S. Book. (iv) Lodging false complaints

		against officer. (v) Not being popular at Barwala.
32	Shiv Kumar Shastri G.M.S. Hamidpur	He is alleged to have been involved in moral misconduct.
33	Balwant Singh Ditto (Lady teacher)	Ditto
34	Smt. Padma Wati G.P.S., Panchkula	Did not mark another teacher on leave in the attendance register.
35	Smt. Santosh G.P.S., Dhurkhra	Absent from duty.
36	Smt. Sukhchain Lata G.P.S., Haveli	Closed the school before time.
37	Smt. Phul Wati G.P.S., Maveli.	Ditto
38	Smt. Subhash Kumari, G.P.S., Rasulpur	Absence from duty.

39	Smt. Shanta Bakshi, G.P.S., Mianpur	Complaint against her that she does not come to school.
Karnal District (Men Teachers)		
40	Chhabi Parkash, G.M.S. Harigarh Bhorakh	He used unparliamentary language against C.M. while criticizing the policy of Government, regarding transfers of teachers.
41	Swarup Singh, G.M.S. Harigarh Bhorakh	He brought a deputation to P.S.E. in favour of Shri Chhabi Parkash, Teacher.
42	Baij Nath, G.H.S. Pabnawa	He approached P.S.E. for his transfer through political pressure.
43	Ram Dia, G.P.S., Samani	Absence from school and complaints from Panchayat.

44	Ish Kumar, G.P.S., Ajrawar	Absence from school.
45	Yudhister Lal, G.P.S., Hatlana	On account of arrest by police.
46	Nand Kishore, G.P.S., Tatiana	He closed the school before closing time on 8th October, 1969
47	Chander Datt, G.H.S. Jhansa	Misbehaviour towards Headmaster
48	Mangal Singh, G.P.S., Dhanouri	Arrested by police inconneetion with embezzlement of milk powder.
49	Surjit Singh, G.P.S., Bir Methana	Took part in Election
(Lady Teachers)		
50	Smt. Sudesh Sharma, G.M.S., Pipli	Absence from school on 7th Oct. 1969.
51	Smt. Darshan Gupta, G.M.S., Pipli	Ditto
52	Smt. Chander Kanta,	She wasattending to her child during

	G.P.S., Gharaunda	school and was causing hinderance in the discharge of her duties.
4. Gurgaon District (Men Teachers)		
53	Nawal Singh, G.P.S., Behlapa	Absence from school
54	Ramesh Chand, G.P.S., Behlapa	Ditto
55	Tek Chand, G.G.H.S. Badshahpur	He kept the leave application of another teacher with mala fide intention.
56	Ramesh Chander, G.H.S.S., Gurgaon	Absence from duty.
57	Bhim Singh, G.P.S., Rattipur	Moral Turpitude.
58	Mam Chand, G.P.S., Kalsada, Bhagroli Jogi	Moral turpitude.
5. Mohindergarh District (Men Teachers)		
59	Jai kishan, G.H.S., Sihma (P.T.I)	Misconduct, doubtful character and absence from

		duty
60	Sudershan Kumar, G.P.S., Mai	Absence from duty.
61	Daya Ram, G.P.S., Rampura	Ditto
62	Hari Ram, G.P.S., Malaudi	Absence from duty and creating indiscipline.
63	Amar Singh, G.M.S., Lad	Erasing of school records.
64	Dharam Pal, G.M.S. Lad	Ditto
65	Budh Ram, G.P.S., Datoli	Absence from duty
66	Randhir Singh (P.T.I.), G.M.S., Lookhi	Beating of school clerk.
67	Mohan Lal, G.M.S., Rewara	Misappropriation.
68	Yadavendra Singh, G.P.S., Dhani Bhatota	Misconduct.
(Lady Teacher)		
69	Smt. Dhanpati, (P.T.I.), G.G.H.S. Mohindergarh Misconduct.	
6. Jind District (Men Teacher)		

70	Sh. Kishori Lal, G.M.S. Kharal	Embezzlement of Government money.
7. Hissar District (Men Teachers)		
71	Sajjan Kumar, G.M.S., Luhari Jattu	Drinking in school premises and absence from school.
72	Budh Ram, G.M.S., Jamalpur Seikhan	Dereliction in duties.
73	Shri Lal, G.M.S., Sahu	Ditto
(Lady Teachers)		
74	Smt. Krishna Kumari, G.P.S., Rattia	Arrested by police under section 25, 54 and 59 I.P.C.
75	Smt. Tripti Devi, G.G.M.S. Samiana	Dereliction in duties and beating the school peon (woman).

Aerial Spraying on Sugarcane Crops

***690. Chaudhri Chand Ram:** Will the Minister for Agriculture and Labor be pleased to state:-

(a) The amount spent on the Aerial Spraying on the sugarcane crops together with the name of the agency to whom this works was allotted;

(b) Whether in view of the scattered area of sugarcane crops the Directorate had suggested Spraying by fixed winged planes and not otherwise; and

(c) The areas benefited as a result of aerial spraying?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ram Singh): (a) (i) Rs. 437820

(ii) The work was allotted to the following agencies:-

1. M/s Agricultural Aviation Private Ltd., Bombay.

2. M/s Mathur Aviation Private Ltd., New Delhi.

3. M/s Khemka Aviation Ltd., New Delhi.

(b) Sugarcane area in the sugar factory zone at Rohtak and Panipat over which aerial spray was done was of such contiguous blocks as to render the operations by fixed-winged aircrafts effective.

(c) 50141 acres in Rohtak and Panipat Factory zones.

Construction of Maina-Pehrawar Jhajjar Rohtak Road in District Rohtak

***669. Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Mininster for Agriculture and Labour he pleased to state:-

(a) Whether Maina Pehrawar road from Jhajjar Rohtak road lies in the Rohtak Market Committee area;

(b) The funds available with the Marketing Committee for construction of roads;

(c) The funds earmarked for this road;

(d) Whether administrative approval for the construction of the said road has been issued; and

(e) The date on which the work is likely to be taken up together with the period within which it is likely to be completed?

Minister for Agriculuture and Labour (Chaudhri Ran Singh): (a) Yes.

(b) Rs. 625000.

(c) Nil.

(d) No.

(e) Does not arise.

Decision regarding Chandigarh and Bhakra Complex

***706. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Chief Minister had accepted the Prime Minister as an arbitrator on the Chandigarh issue?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस विषय पर भारत सरकार द्वारा वर्तमान मुख्य मंत्री को कोई निर्देश नहीं किया गया था।

Water Works in the State

***674. Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) The number of cities in the State where arrangements of water works exists;

(b) The number of water works out of those mentioned in part (a) above which supply water throughout the day together with the number of those which supply water during the morning and evening hours only;

(c) Whether there are any cities or towns where in some parts the water supply is maintained throughout the day while in other parts the water is supplied in morning and evening hours only.

Minister of Agriculture and Labour (Chaudhri Ran Singh): (a) 42 towns/cities.

(b) (i) Water is not supplied throughout the day in any city/town in the state.

(ii) Water is being supplied to all towns/cities. Mentioned in part (a) above for limited hours in the morning and evening.

(c) Yes.

Post reserved for Emergency Commisioned Officers

***566. Major Amir Singh Chaudhry:** Will the chief Minister be pleased to state:-

(a) Particulars of the posts, which were got advertised through Haryana Public Service Commission, as 'Reserved for E.C.O.'s during the period from 1st April, 1968 to 31st December, 1969, along with the details relating to the number of vacancies, designation of posts and pay scales in each case;

(b) Particular of the posts out of (a) above which were filled from amongst E.C.O.'s together with their names, ranks, and home addresses in each case; and

(c) The particulars of posts for which no E.C.O. applied along with the manner in which such posts where filled up.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): जो सूचना इस प्रश्न में मांगी गई है, उसके भाग (ए), (बी) तथा (सी) का उतर तदानुसार विस्तृत विवरण (ए), (बी) तथा (सी) के रूप में विधान सभा की मेज पर प्रस्तुत है।

STATEMENT

Sr. No.	Name of the Deptt.	Particulars of the posts, which were got adevertised through Haryana Public Service Commission as "Reserved for E.C.Os." during the period from 1st April, 1968 to 31st Dec., 1969, along with the details relating to the number of vacancies designation of posts and pay scales in each case (a)	Particulars of the posts out of (a) above, which were filled from amongst E.C.Os. together with their names, ranks and home addresses in each case (b)	The Particulars of posts for which no E.C.O. officer applied along with the manner in which such posts were filled up (c)
1	2	3	4	5

		Disignation of posts with pay scals	No. of vacancies advertised	No. of posts reserved for E.C.Os.		
		(i)	(ii)	(iii)		
1	Employment	Assistant Employment officer (Vocational Guidance) Rs 25-25-450/25-550	1	1	Nil	No-body has been recommended by the commission so far. The post is lying vacant
2	Irrigation	H.S.E. Class I (Jr. Scale) Rs 375-30-525/40-925	4	2	Nil	The recommendations of the Commission have not been received so far

3	Labour	Factory Inspector Rs. 250-25-550/25-750	5	2	Nil	No. E.C.O. has been recommended by the commission. The posts are being re-advertised.
		Legal Assistant Rs 150-10-200/10-300	1	1	Nil	Due to non-availability of E.C.O. the post has been filled up by the person recommended by the commission.
4	Technical Education	Head of Deptt. Civil Engineering.	1	1	Nil	Post filled in on the recommendation

		Rs. 700-1250.				s of the Commission, as no E.C.O. was available.
		Senior Lecturer Auto-Engineering. Rs. 700-1250	1	1	Nil	Ditto
		Superintendent Workshop, Rs 400-1100	1	1	Nil	Recommendations of the Commission are still awaited
		Lecturer in Auto Eng. Rs. 400-1100	1	1	Nil	Post filled in on the recomendations of the Commission, as no E.C.O. was available

		Jr. Lecturers in Science Rs. 300-600	3	1	Nil	Recommendations of the Commission are still awaited
		Drawing Instructors: Rs 225-500				
		Civil Eng.	2	2	Nil	The posts were filled in on the recommendations of the commission No. E.C.O. was recommended
		Electrical Eng.	2	1	Nil	Ditto
		Mechanical Eng.	5	3	Nil	Ditto
		Demonstrators:				

		Rs. 225-500				
		Civil Eng.	4	1	Nil	Ditto
		Electrical Eng.	5	2	Nil	Ditto
		Mechanical Eng.	6	4	Nil	Ditto
5	Economic and Statistical Advisor	Tech. Assistant Rs. 300-600	23	7	Nil	The commission has advertised these posts. the posts are lying vacant
		District Statistical officers/Research officers Rs. 350-800	4	1	Nil	Ditto
6	Milk Commissioner	Apprentice Eng. Rs. 350 fixed. After Training	4	1	Nil	No. E.C.O. applied for this post, so these

		pay Scale Rs. 400-1100				were filled up from others on the recommendations of the commission
		Investigators Rs. 200-450	4	1	One E.C.O. applied for this post. His particulars are given below:-	
					Capt. Manmohan Kumar Rajyana son of Late Shri Baljiv Sarup Rajyana,	

					Jind (Haryana)	
7	Language Department	Statistician; Rs. 300-600	1	1	Nil	These posts were reserved for Ex-Servicemen. No E.C.O./Ex-servicemen applied for these were filled in from other candidates
		Translator Rs. 225-500	4	2	Nil	
		Proof Reader Rs. 160-400	3	1	Nil	
		Copy Holders Rs. 80-120	5	2	Nil	

		Clerk Rs. 110-225	4	2	Nil	
8	Police Deptt.	Inspector/Band Master Rs. 300-550	1	1	Nil	No recommendation of the Commission has been received so far.
						This post has been filled up by Ex-serviceman on temporary basis for a period of 6 months. His name is Nb. Subedar Jiwan Ram H.NO. 117, Ward No. 9 Kacha Tank,

						Nahan, (H.P.)
		Prosecuting-Sub- Ins. Rs. 25-450 Plus Rs. 30 Special pay	4	1	Nil	No. E.C.O. applied for the posts of P.S.I. So these were filled up on the recommendations of the Commission from others.
		Assistant Sub-Ins. Rs. 160-200	2	1	Nil	One post of A.S.I. has been filled up by Ex-Serviceman. His name is Shri Sukh lal Singh, R/O Village Morwala, P.O. Bhagwi, Mohindiergarh.

9	Jail Deptt.	Deputy Superintendent Rs. 300-600	1	1	Capt. R.K. Verma, R/o Ghanauli Gate, Chhachhraul i, Ambala	
		Asstt. Supdt. Jail/Welfare officer Rs. 200-450	3	2	Nil	These posts have been advertised by the commission no interview has been, held so far
10	Fisheries Deptt.	Fisheries Deptt officer (Class II) Rs. 350-900	2	1	Nil	This post has not been filled so far.
11	Public Relations	Song and Drama officer Rs. 250-550	1	1	Nil	Commission has not recommended any candidate

						so this post is lying vancant.
12	Industrial Training Deptt.	Lecturer in Drawing and Designs Rs. 350-850	1	1	Nil	No. E.C.O. applied for this post. the post has been filled in on the recommendation of the commission.
		Principal, I.T.I./Assistant Director, Rs. 350-900	8	4	Nil	Date of interview has not been fixed by the Commission so far.
13	P.W.D. Public Health Branch	Assistant Eng. Rs. 400-1100	12	6	Capt. Sushil Kumar Mutreja, 118 Model Town.	The commission has recommended 7 candidates for

					Ambala	the post of Assistant eng. out of which 4 conditates are E.C.Os.
					Capt. Raj Kumar Dilbagi H. No. 850/B/6, Partap Mohalla, Rohtak	
					Capt. Jagdish Chander Nangia, 194, Delhi Road, Meerut	

					Capt. S.P. Bedi, 46/21, patel nagar, New Delhi-8	
14	Industries	Assistant Director/Distt. Ind. Officer/Stores Ins. Officers Rs. 350-900	1	1	Capt. Jaipal Singh Sangwan, Vill. Nuran Kheran P.O. Butana, Rohtak	
		Geo-Hydrologist, Rs. 400-950	1	1	Nil	Date of interview has not been fixed by the commission so far.
		Mining officers Rs. 250-650	3	1	Nil	Ditto

		Assistant Geologist, Rs. 400-1100	1	1	Nil	Ditto
		Assistant Mining Eng. Rs. 350-900	1	1	Nil	Due to non-availability of E.C.O. the post has been filled in on the recommentdation of the commission
		Inspector of Boilers Rs. 350-800	1	1	Nil	The date of interview has not been fixed by the commission so far.
15	Excise and Taxation	Execise Ins. Rs. 150-10-300	10	3	Nil	The date of interview has not been fixed

						by the commission. The posts are lying vacant
16	Health Deptt.	Assistant Professors Rs. 750-1200	12	6	Nil	The Commission did not recommend any E.C.O.
		Senior Lect., Rs. 450-950	5	2	Nil	The following posts have, however, been filled up on the recommendations of the commission
		Lecturers Rs. 400-900	13	6	Nil	
		Lect., (Pharmacy) Rs.	3	1	Nil	Assistant Professors ..

		325-600				6
						Senior Lect. .. 2
		Demonstrators (Pharmacy) Rs. 250-500	4	2	Nil	Lecturer (Pharmacy) 1
						Demonstrators (Pharmacy) .. 3
17	Animal Husbandry	Officer In-charge (Semen collocting Centres, Karnal, Gurgaon). Rs. 350-900	2	1	Nil	Date of interview has not been fixed by the commission so far, However, the departmental officials have been appointed

						temporarily on these posts to carry on the work. they will be replaced as and when the candidates are recommended by the commission.
		Veterinary Assistant Surgeon, Rs. 300-550	45	13	Nil	Nine posts of Veterinary assistant surgeons were reserved for E.C.Os. in 1968. As no E.C.O. applied for these posts. the same have been filled in

						from others on the recommendations of the commission
						Four posts were reserved for E.C.Os. in 1969. The date for interview has not been fixed by the commission
17-A	Treasury and Accounts Organisation	Treasury Officer, Rs. 350-900	1	1	Capt. Rajender Nath H.NO. 1543, SEC. 7-C, Chandigarh	

18	Commissioner Ambala Division	'A'- Class Naib-Tehsildar Rs. 250-500	2	2	Capt. Keshab Ram Yadav, Village Naya Gaon, P.O. Rewari, District Gurgaon Ex-Hav. Hari Singh, Village Chahar wala Tehsil Sirsa. Hissar	The posts have been filled in on the recommendations of the commission
19	Home Guards and Civil Defence	Coy. Commanders Rs. 300-700	7	2	Capt. Hoshiar Singh Yadav. Village Niveda Fatehpur, District	

					Gurgaon	
					Major S.K. Yadav, V. & P.O. Pali, District Gurgaon	
					Capt. B.K. Batra, Village Ujina, tehsil. Nub, District Gurgaon	
					Capt. H.R. Kohar, Village Malcha, Tehsil Sonepat, Rohtak	

					Capt. Amar Singh, Village Bhondi, District and Tehsil Gurgaon	
20	Transport Deptt.	Motor Vehicle Insp. Rs. 200-350	1	1	Nil	These posts have been filled in on temporary basis through departmental promotions.
		Works Manager Rs. 350-550	4	1	Nil	These posts have been filled in on temporary basis through departmental promotions.

21	Food and Supplies	District food and Supplies Controller, Rs. 350-900	1	1	Nil	This post has been filled in on ad-hocbasis by departmental promotion. The post has not been advertised so far.
22	Education	Maths. Master, Rs. 220-400	270	70	Nil	Due to non-availability of E.C.O. the posts have been filled in from other categories of condidates, through commission.
		Science Master Rs. 220-400	135	41	Capt. Virender Singh	Remaining posts have been filled in through

					Mankotia, Kangra (HP)	commission
		social Studies Master Rs. 220-400	145	37	Nil	Recommendations of the commission are still awaited
		Science Mistresses, Rs. 220-400	115	32	Nil	The commission did not recommended any E.C.O. The posts have been filled in by other candidates through commission
		Maths. Mistresses. Rs. 220-400	105	30	Nil	Ditto

		Lect. (Physics) (Men) Rs. 300-600	19	4	Nil	The Commission did not recommend any E.C.O. The posts have been filled in by other candidates through commission
		Lect. Chem. (Men) Rs. 300-600	26	5	Nil	Ditto
		Lect. Chem (Women) Rs. 300-600	19	4	Nil	Ditto
		Lect. Physics (Women) Rs. 300-600	18	4	Nil	Ditto

		Lect. Maths. (Women) Rs. 300-600	8	2	Nil	Ditto
		Lect. (Non-gazetted) College Cadre Rs. 300-600	55	18	Nil	Ditto
		District Education Officer Rs. 700-1200	4	1	Nil	Ditto
		Principal, H.E.S. II Rs. 400-800	9	3	Nil	Recommendations are still
		Technical Lect. Rs. 350-900	7	3	Nil	Only one E.C.O. applied for this post, who was not selected. the posts have

						therefore been filled in from other candidates through the Commission.
		Sr. Lectures Rs. 400-800	5	1	Nil	Due to Non-availability of E.C.O the posts have been filled in from other candidates through commission.
23	P.W.D. B. & R.	Asstt. Engineer (Civil) Rs. 400-1100	46	23	Capt. S.C. Girotra, Delhi	Through Commission
					Capt. Ved Paul, U.P. Capt. Nand	

					Kishore Khanna, Delhi	
					Capt. Madan Lal Narula, Karnal	
					Capt. Surrinder Kumar Chopra, Ferozepur	
					Capt. Ish Chander Dewan, Delhi	
					Capt. Arjun Singh Parmar, Kangra	

					Major K.S. Sharma and Shri C.L. Garg are to be posted as Assistant Enginners after being released from the Army	
		Asstt. Engineer (Elec) Rs. 400-1100	4	2	One one of these two posts Shri T.P. Markanda is to be posted after being released from the	The commission did not recommend any E.C.O. for the other post

					Army	
		Asstt. Engineer (Mech) Rs. 400-1100	4	2	Nil	The commission did not recommend any E.C.O.
24	Tourism	Asstt. Director Tourism Rs. 350-950	1	1	Capt. J.C. Kapoor, 96, Model Town, Karnal	
25	Development and Panchayat	Block Development and Panchayat officer Rs. 300-700	14	8	Capt. S.S. Ahiawat, V. Gochhi, Distt. Rohtak has been appointed on temporary basis	The remaining posts hae been filled in through departmental promotions
26	Co-operative	Sr. Auditor Rs.	1	1	Nil	The post has

	Societies	220-500 for Non S.A.S. and Rs. 300-600 for S.A.S.				been advertised. The date of interview has not been fixed so far. The post is lying vacant.
27	Legal Remembrancer, Haryana	Asstt. District Attorney Rs. 350-900	2	1	Capt. Joginder Singh Rathi, V.P.O. Sankol, Tehsil Jhajar, Rohtak	These posts have been filled in through the Commission Besides this 4 additionsal posts have been filled in through the commission
28	Agriculture	Asstt. Agri. Engineer Rs. 350-900	4	1	Nil	The commission has not recommended any candidate

		Field Officer (Statistics) Rs. 350-900	1	1	Nil	Ditto
		Asstt. Cane Development officer Rs. 350-900	1	1	Nil	Ditto
		Asstt. Soil Conservation officer Rs. 350-900	4	1	Nil	Ditto
		Seed Development officer Rs. 350-900	3	1	Nil	Ditto
		Draftsman (Civil) Rs. 150-300	5	1	Nil	4 posts have been filled in through Commission.

						No. E.C.O. has been appointed one post has been abolished
		Draftsman (Mech) Rs. 150-300	3	1	Nil	The commission has not recommended any candidate
		Tracer Rs. 110-225	14	4	Nil	9 Posts have been filled in through commission.
		Statistical Computer Rs. 110-225	4	1	Nil	No. E.C.O. has been appointed the commission has not recommended any candidate
		Jeep Driver Rs.	40	13	Nil	27 posts have

		110-160				been filled in on the recommendation of the Commission.
						Out of them 13 Ex-Servicemen have been appointed
		Graders Rs. 100-160	10	3	Nil	7 posts have been filled in through commission. No. E.C.O. has been appointed.
		Stenographer (Jr.) Rs. 120-250	12	4	Nil	The commission has not yet recommended any candidate.

		Steno-typist Rs. 110-225 plus Rs. 25/-as Special Pay	45	14	Nil	Ditto
		Clerks Rs. 110-225	83	25	Nil	32 posts have been filled in through commission. No. E.C.O. has been appointed.

***601. dr. Malik Chand Gambhir:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) Whether the value of the Bhatia Nagar Colony (Custodian property) of Yamuna Nagar has been assessed, if so, details thereofp; and

(b) The total area of the colony together with the number of the inhabited houses therein?

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): (a) Bhatia Nagar Colony has not yet been formally transferred to the State Government by the Government of India. Negotiations for transferring the remaining urban acquired evacuee property are at advanced stage and the deed is likely to by finalized shortly. The assessment of the value of the colony will be finalized after the State Government has taken over the colony from Government of India.

(b) The area of the land is 4 bighas and 19 biswas on which 65 persons have made an encroachment and constructed houses thereon.

Villages without Primary Health Centres in the State

***661. Shri Randhir Singh:** Will the Minister for Health and Development be plased to state whether there are any village in the State which have population of more than twelve housand but are without any Primary Health Centres; if so, total number thereof?

Minister for Health and Development (Chaudhri Khurshed Ahmed): According to 1961 Census there is no village in Haryana State which has more than twelve thousand population. There was two villages, namely, Pabra and Barwala in the state, the population of which is 11738 and 10723, respectively. Medical facilities in both these villages are available.

Construction of Village Link Roads

***691. Chaudhry Chand Ram:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) Whether any villagers deposited their share for the construction of a village link road from Radaur to Kharkali iin Radaur Block of Thanesar Tehsil, if so, the date of deposit of such amount together with the amount deposited with the P.W.D.;

(b) The period within which this village link road is likely to be taken up for construction;

(c) Whether the road from Mustafabad to Gajlana is likely to be metalled, if so, the period within which this road is likely to be metalled; and

(d) Whether the Radaur Jathlana road is also likely to be taken up for construction; if so, the time schedule thereof?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ram Singh): (a) Yes. A sum of Rs. 20000 was deposited by the villagers in cash on 26th March, 1968.

(b-c-d). These roads have not been included in the Fourth Five-Year Plan due to paucity of funds.

Construction of Sukhpura-Ladhaut Road in Rohtak District

***670. Chaudhry Ranbir Singh:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) Whether administrative sanction for the construction of Sukhpura Ladhaut Road of Rohtak District has been issued from cane cess fund; and

(b) Whether work on the road has been started. if not the reasons therefor, together with the period within which the work is likely to be stated and completed?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): (a) Yes. (b) Not yet, The administrative approval for the work has been accorded on 6th Feb., 1970 and the work is being taken in hand shortly. It is likely to be completed in 3 years subject to the availability of funds.

Decision about Chandigarh

***707. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state whether he took into confidence any leader of

the "Ppposition" at the time of taking decision about Chandigarh, if so, the name of such leader?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): हरियाणा सरकार चण्डीगढ़ का कोई फैसला करने के लिए कम्पीटैन्ट नहीं है। किसी राज्य की सीमाएं बदलना केन्द्रीय सरकार के अधीन है। इसलिए यह सवाल असैम्बली में नहीं पूछा जा सकता। हरियाणा सरकार के इस इशू पर फैसला करने का सवाल पैदा नहीं होता।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Agricultural Loans

300. Major Amir Singh Chaudhry: Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) The total amount of agricultural loans advanced by the state Government during the last ten years, in the areas now forming part of the State of Haryana;

(b) The total amounts of said loans still outstanding even after the expiry of the period prescribed for the recovery thereof; and

(c) The steps, if any, the Government proposes to take to expedite the recovery of the outstanding loans?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): (a) Rs. 219703100.

(b) Rs. 25821700.

(c) Steps are already being taken by the Deputy Commissioners concerned to recover the outstanding amounts of loan as provided under aw.

Distrubution of Application Forms for obtaining Agriclutural Machinery

***306. Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state whether any arrangement has been made to distribute application forms for obtaining, under hire purchases system the Diesel Pumps/Elecrtic Motors of other Agricultural Machinery through Haryana Agro-Industries Corporation at any place in Rohtak district, if not, the arrangements, if any, now proposed to be made by the Governement in this behalf?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): No. The Corporation, however, proposes to set up a Base Workshop at Rohtak and operational Centres at selected places in the district wherefrom arrangements for supply of these forms would be made.

Manufacture and Distribution of Dises. Harrow

307. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state whether the manufacture of discs. harrow have been organised by the Haryana Agro-Industries Corporation; if not, the steps, if any, the Governement proposes to take to distrubute the imported

discs at reasonable price to the mechanised cultivators of the State?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): The Agro-Industries Corporation has not started the manufacturing of the discs. harrow at present, It has, however, made arrangments regarding the utilisation and distribution of 20250 imported discs as allotted to the Corporation by the state Trading Corporation with a view to ensure early availability of discs harrow to the farmers in the state at reasonable prices.

Percentage of Kharaba recorded in village Bohar of District Rohtak

308. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any, recorded in the Flood affected areas of village Bohar in district Rohatak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing Kaloi Constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) If the reply is in theaffirmative, action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) The amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): (ए) 10 प्रतिशत

(बी) नहीं।

(सी) नहीं।

(डी) फिर भी मामला विचारधीन है।

(ई) शून्य।

Percentage of Kharaba recorded in village Kesrenti in District Rohtak

***309. Chaudhry Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any recorded in the flood affected area of village Kasrenti in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended remission of land revenue and Abiana during Kharif, 1969 for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing the Kaloi constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abina referred to in Part (b) above if the reply is in the affirmaive, action, if any, taken by the Government in this behalf, and

(d) The amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood-affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): (ए) 16 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) हां। मामला विचारधीन है।

(डी) शून्य।

Percentage of Kharaba recorded in village Paksma in District Rohtak

***310 Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected area of village paksma in District Rohtak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak recommended remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing Kaloi constituency, represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) If the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) The amount of cash relief if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): (ए) 53 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचारधीन है।

(ई) रूपये 2300

Percentage of Kharaba recorded in village Baliana in District Rohtak

***311. Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected area of village Baliana in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak recommended remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing Kaloi constituency, represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (a) above;

(d) If the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) The amount of cash relief if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): (ए) 53 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचारधीन है।

(ई) रूपये 2800

Percentage of Kharaba recorded in village Kaloi Khas and Kaloi Dopana in District Rohtak

***312. Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected area of village Kaloi Khas and Dopana in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak recommended remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing Kaloi constituency, represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) If the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) The amount of cash relief if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): (ए) किलोई खास 56 प्रतिशत, किलाई डोपाना 51 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचारधीन है।

(ई) किलोई खास रूपये 1700, किलाई डोपाना रू.

Percentage of Kharaba recorded in village Ladhaut Beyanpur in District Rohtak

***313. Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected area of village Ladhaut Beyanpur in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak recommended remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing Kaloi constituency, represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) If the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) The amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): (ए) 63 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचारधीन है।

(ई) रूपये 1120

Percentage of Kharaba recorded in village Dhamar in District Rohtak

***314. Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected area of village Dhamar in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak recommended remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing Kaloi constituency, represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) If the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) The amount of cash relief if any, sanctioned and disbursed to the flood-affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): (ए) 53 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचारधीन है।

(ई) रूपये 900

Percentage of Kharaba recorded in village Makrauli Kalan and Makrauli Khurd of District Rohtak

***315. Chaudhri Ranbir Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) The percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected area of village Makrauli Kalan and Makrauli Khrud of district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) Whether the Deputy Commissioner, Rohtak recommended remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) Whether the member representing Kaloi constituency, represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) If the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) The amount of cash relief if any, sanctioned and disbursed to the flood-affected people of the village referred to in part (a) above?

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): (ए) मकरोली कलां 18 प्रतिशत, मकरोली खुर्द 22 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचारधीन है।

(ई) मकरोली कलां रूपये 1125, मकरोली खुर्द रूपये 700

Areas irrigated in Village Bhalaut

316. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Bhalaut of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Bhalaut of

Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C.CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bhalaut	1500-R	289	328	287	514	447	363	195	180
	Do	5816-R	457	..	..	..	..	430	224	461
	Do	6850-R	133	103	114	186	130	132	135	113
	Do	10999-L	749	260	239	435	450	541	472	459
2	Asan, Minor	950-R	607	..	..	..	444	349	442	373
	Ditto	7350-L	234	70	63	11	100	84	90	96
	Ditto	8812-L	146	79	84	99	150	145	..	150
	Ditto	9060-R	602	280	286	503	459	441	441	371
	Ditto	12500-	436	339	223	400	334	292	279	236

		R								
	Ditto	14073-L	10	4	5	11	13	4	13	14
	Ditto	15625-R	682	261	230	460	526	406	524	882
	Ditto	19225	330	187	173	266	280	302	297	283

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Baliana Village

317. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Baliana of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Baliana of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C. CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70, upto January 1970
1	Bhalaut	11596-R	852	560	396	660	502	503	507	683
	Do	13618-L	184	121	128	161	147	137	202	212
	Do	17930-I	558	442	323	524	435	343	416	502
	Do	20799-R	807	270	187	291	238	185	269	230
2	Kheri Sadh Minor	4867-L	368	270	187	291	238	185	269	230
	Ditto	17396-L	275	151	126	175	412	337	136	746
	Ditto	24289-L	266	118	125	155	92	113	109	8

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check

measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Village Paksma

318. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Paksma of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Pakasma of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C.CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bhalaut	17930-L	466	344	166	387	302	250	378	276
	Do	29416-L	652	364	285	513	441	426	475	402

	Do	30130-L	427	299	182	230	296	298	263	252
2	Asan Minor	19225-R	271	..	12	137	141	136	138	137
	Ditto	21628-R	873	535	305	405	219	222	213	462
	Ditto	28530-T.R.	372	183	127	136	113	104	147	125

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Village Kasrenti

319. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Kasrenti of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Kasrenti of

Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C. CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bhalaut	30130-L	191	102	85	79	76	72	82	68
2	Asan Minor	28500-T.I.	258	122	124	101	52	88	101	48

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Dhamar Village

320. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in

the revenue estate of village Dhamar of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Dhamar of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C.CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bhalaut Sub-Branch	111200-L	95	..	..	..	..	..	..	29
	Ditto	114100-R	452	..	..	..	..	..	..	95
2	Rithal Disty	66066-L	98	29	39	37	35	35	22	..
	Rithal Disty	69418-L	52	39	21	30	30	24	20	..
	Ditto	75048-T.C.	43	10	14	21	21	9	..	..

3	Kahni Disty	67487-R	485	266	243	363	351	336	385	408
	Ditto	74380-R	404	155	304	313	323	257	262	163
4	Makrauli Minor	2510-R	281	219	170	245	230	195	196	160
	Ditto	8000-R	279	234	215	265	247	223	248	176
	Ditto	10500-L	575	375	293	453	446	369	365	399
	Ditto	12300-R	98	48	23	30	23	24	16	19
	Ditto	6200-L	304	316	294	286	248	207	249	340
5	Rithal Disty	64375-TC	98	..	..	..	..	..	..	15

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Jasia Village

321. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the

respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Jasia of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Jasia of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C.CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Rohtak	82727-L	788	355	333	496	442	456	417	385
	Do	84932-L	657	318	298	434	356	279	249	270
	Do	90676-L	162	28	10	41	15	29	28	20
2	Makrauli Minor	2500-R	1490	444	511	914	836	655	852	894

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check

measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Makrauli Kalan and Makrauli Khurd Villages

322. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Makrauli Kalan and Makrauli Khurd of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Makrauli Kalan and Makrauli Khurd of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C.CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
Village Makrauli Khurd										
1	Boher	3500-R	297	183	140	210	193	176	207	201

	Makrauli Minor	23500-L	446	234	226	297	290	232	221	281
	Ditto	26200-TR	323	93	138	147	124	202	51	95
	Village Makrauli Kalan									
1	Makrauli	13500-R	720	270	336	460	485	370	463	433
	Do	13500-L	875	508	385	379	528	478	546	740
	Do	22300-R	1030	270	332	494	469	385	395	462
	Do	23500-L	318	217	195	247	218	203	182	184

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Ladhaut Bhayanpur Village

323. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas

irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Ladhaut Bhayanpur of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Ladhaut Bhayanpur of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C.CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bhalaut Sub-Branch	114100-R	418	..	..	..	..	..	..	215
2	Kahni Disty	75678-TC	638	137	295	345	352	347	375	169
3	Bohar Disty	3500-R	606	522	438	458	560	420	539	536
4	Bhalaut Disty	1500-R	57	21	1	2	2	..	8	4
5	B.S.B.	122629-	129	94	76	80	67	71	60	64

		R								
6	Bohar Minor	3500-R	135	..	104	116	127	116	142	169
	Ditto	4335-R	1336	756	555	795	979	713	1004	710

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Kanheli Village

324. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Kanheli of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Kanheli of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr.	Name	R.D. of	O.OA.	1963-	1964-	1965-	1966-	1967-	1968-	1969-

No.	of Disty.	O/let		64	65	66	67	68	69	70,upto January 1970
1	Bohar Mr.	24082-L	101	..	202	202	202	202	202	202
2	J.S. Branch	345-R	496	96	141	278	211	157	144	173
	Ditto	3000-R	555	140	234	310	327	180	318	322
	Ditto	1246-L	92	29	34	47	35	19	28	78

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Pahrawar Village

325. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Pahrawar of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-

64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Pahrawar of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	O.O.A.	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Dulehra	500-L	747	656	579	672	690	662	680	831
	Do	8520-R	602	..	..	..	536	518	605	306
2	Kheri Sadh Mr.	31212-R	283	143	113	170	127	192	176	154

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Maina and Simli Villages

326. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the

respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Maina and Simli of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Maina and Simli of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	C.CA	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
Maina 1	Jhajjar Sub. Br.	5418-L	362	168	203	238	275	257	433	291
	Ditto	1246-L	670	340	386	478	470	403	573	388
	Ditto	3040-R	30	22	13	15	16	7	7	7
	Ditto	9450-R	35	19	25	22	22	23	15	23
	jhajjar Sub-Branch	9700-L	291	172	192	196	217	191	238	266

	Ditto	16865-L	136	112	157	163	118	120	99	132
	Ditto	18080-L	446	234	280	280	267	301	232	297
Simli 2	Ditto	1246-L	227	148	194	164	153	115	182	90
	Ditto	18080-L	267	127	148	157	156	142	175	169
	Ditto	31700-L	355	121	152	153	166	162	220	199

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Karauntha Village

327. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Karauntha and Karaur of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-

64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Karauntha and Karaur of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	O.O.A.	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Ismaila Disty.	38500-R	389	251	240	174	129	174	169	82
2	J.S.B.	31700-L	1143	589	776	776	650	731	702	728
3	Do	36800-L	140	121	152	148	139	156	131	156
4	Barahana Mr.	3200-L	83	86	120	114	144	186	122	130
5	Ditto	10000-L	948	450	632	637	651	689	606	633
	(Karaur)									
1	Ismaila	39165-R	315	190	170	213	157	174	268	169
	Do	54007-R	368	310	284	282	231	220	297	84

2	Kheri Sadh Mr.	34005-TC	88	43	48	44	36	93	96	..
3	Dulehra Disty.	14900-R	280	..	..	..	242	160	318	249
	Ditto	16750-L	39	..	..	..	29	50	..	44

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Bohar and Garhi Bohar Villages

328. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Bohar and Garhi Bohar of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Bohar and Garhi Bohar of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	O.O.A.	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bohar Disty.	4735-R	1316	717	561	1078	1122	1011	1204	1181
	Ditto	15704-R	316	156	176	350	315	302	374	314
	Ditto	18200-L	966	505	496	862	849	719	549	635
	Ditto	21200-R	338	203	194	289	314	242	536	389
	Ditto	21418-L	473	313	267	398	421	358	615	556

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Nunand and Kheri Sadh Villages

329. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Nanand and Kheri Sadh of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Nanand and Kheri Sadh of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	O.O.A.	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bhalaut Disty.	23120-R	456	264	303	327	290	160	428	273
	Ditto	26916-R	529	254	305	328	312	199	384	309
	Ditto	30780-R	300	198	197	206	187	214	267	217
	Ditto	30130-	169	125	124	162	1354	108	147	140

		L								
	Ditto	33315-R	8	..	..	1	..	..	..	
2	Kheri Sadh Minor	6695-L	818	525	445	815	758	777	820	925
	Ditto	11970-L	526	213	206	407	412	409	437	428
	Ditto	17396-L	673	259	305	356	191	257	448	380
	Ditto	21268-R	273	..	112	212	231	234	273	341
	Ditto	21624-R	136	158	98	177	179	158	162	183
	Ditto	24289-L	569	268	186	267	292	241	257	196
	Ditto	27000-L	441	286	311	422	127	229	178	106
	Ditto	25900-L	217	124	107	162	143	142	197	298

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check

measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Kaloi Khas and Kaloi Dopanan Villages

330. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Kaloi Khas and Kaloi Dopanan of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Kaloi Khas and Kaloi Dopanan of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	O.O.A.	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Bhalaut Sub Br.	111200-I	33	..	..	..	..	..	..	3

	Ditto	120100-L	1508	742	779	956	781	684	858	724
	Ditto	122679-R	114	59	54	66	58	41	53	122
2	Bhalaut Disty	308-L	251	185	89	154	133	108	178	185
	Ditto	1500-R	55	20	10	12	18	19	22	14
3	Asan Mr.	7350-L	232	128	81	128	133	73	105	162
4	Rithal Disty	64375-TC	52	..	..	..	..	..	..	24
	Ditto	66066-L	52	25	27	40	32	5	7	..
	Ditto	75043-TC	33	..	..	..	..	..	..	..
5	Kaloi Mr.	9290-R	765	358	388	311	381	210	289	249
	Ditto	17055-TR	235	84	56	78	55	63	93	88
6	Bhalaut Sub Br.	111290-L	1650	..	..	..	..	..	240	793
	Ditto	114100-R	39	..	..	..	..	..	..	..

7	Rithal Disty.	66066-L	114	46	33	95	58	63	..	..
	Ditto	643375-TC	114	..	..	..	..	..	18	83
	Ditto	69418-L	922	278	277	359	373	215	50	..
	Ditto	75043-TC	732	351	208	58	391	238	178	..
8	Kaloi Mr.	9300-R	521	225	248	255	277	173	209	171
	Ditto	9300-L	540	135	137	181	244	1301	162	142
	Ditto	17055-TR	197	124	124	124	118	88	150	97
	Ditto	17055-TL	89	47	49	60	68	69	65	41
9	Rurkee Mr.	6531-R	98	..	11	37	50	29	76	31
		11385-R	79	72	59	75	32	13	19	47

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Areas irrigated in Village Roorkee

331. Chaudhry Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distrubutaries in the revenue estate of village Roorkee of Tehsil and District Rohtak?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur): Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the renveue estate of village Roorkee of Tehsil and District Rohtak are indicated in the encolsed statment:-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Disty.	R.D. of O/let	O.O.A.	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70,upto January 1970
1	Rurkee Mr.	11385-R	343	118	134	162	190	160	225	116

	Ditto	15014-I	491	350	300	290	353	262	312	174
	Ditto	18050-TL	492	258	231	247	207	122	206	149
	Ditto	18050-TR	544	268	241	258	227	169	26	133
2	Kaloi Mr.	17055-TL	596	225	201	186	321	176	327	195
3	Asan Minor	8812-L	181	171	160	183	184	140	125	118
	Ditto	14073-L	457	314	266	311	227	186	271	201
	Ditto	15625-R	8	..	..	..	..	3	4	3
	Ditto	19160-L	261	179	141	181	242	187	163	113
	Ditto	19255-R	84	64	51	63	52	52	52	49

Note:- Figures of irrigation for the year 1969-70 (Up to Janary, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

Tractor Service Station

337. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) Whether any service stations have been organised by Haryana Agro-Industires Corporation for the benefit of Agriculturists who have obtained tractors through the Corporation;

(b) Whether the Haryana Agro-Industries corporation proposes to stat any new service stations for the aforesaid purpose; if so, the names of staitons where such service stations are proposed to be opened;

(c) Whether any service station has been opened in Rohtak District

(d) If the reply to part (c) above be in the negative whether the Government proposes to open any service station at Rohtak now, if not he reasons therefor?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): (a) Yes. Three service stations have been set up by the corporation at Nilokheri, Panipat and Hissar.

(b) Yes. The scheme for full coverage of the State is under preparation. The Corporation proposes to set up base workshops so as to cover all the District Headquarters with opertional centres at other places in the districts.

(c) No.

(d) Yes. The Corporation proposes to open service station at Rohtak in the near future.

Import of Dises of Tractors

338. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minsiter for Agriculture and Labour be pleased to state:-

(a) The number of discs, if any, imported by the Haryana Agro-Industries Corporation through the state Trading Corporation of India since May, 1968;

(b) The names of persons to whom the discs have been distributed; and

(c) Whether it is a fact that the entire lot has been taken possession of by any one firm and the same has been sold at open market rates?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): (a) Agro-Industries Corporation have been allotted a total of 20250 dises out of the improted discs by the State Trading Corporation. Out of these 15000 dises are to be distrubuted among the fabricators out of which 1000 would be reserved for replacement of dises of genuine farmers possessing tractors.

(b) These discs have not yet been distributed.

(c) No.

Manufacture of Dises Harrows and Dise Ploughs

399. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state the number of

discs imported since May, 1968 through the State Trading Corporation of India by Haryana Agro-industries Corporation for manufacture of disc harrows and disc ploughs for distribution amongst the tractor-owners?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): Agro-Industries Corporation have been allowed by the state Trading Corporation 15000 discs for distribution among the approved fabricators in the state. In addition to this, the Agro-Industries Corporation have been given 5250 discs for the manufacture of implements under their own programme. The Agro-Industries Corporation have decided that out of 15000 discs 1000 discs would be reserved for replacement of discs of genuine farmers having tractors.

Persons arrested in the State on 29th, 30th and 31st January, 1970 and thereafter

347. Shri Mangal Sein: Will the Chief Minister be Pleased to state:-

(a) The number and names of persons arrested on the 29th, 30th and 31st January, 1970, and thereafter to date in the state; and

(b) The different secctions under which the persons referred to in part (a) above were arrested by the Government?

Chief Minister (Shri Bansi Lal): (a) 1327 persons were arrested. It will not be commensurate with the labour involved to prepare lengthy lists giving their names, etc.

(b) A statement is attached.

Statement showing the number of arrests made tehsil-wise under various Sections of Law on and after 29th January, 1970 during the Agitation on Chandigarh Issue.

District	Tehsil	Arrests made under section 188 I.P.C. for definance of law imposed u/s 144 Cr. P.C.	Arrests under Preventive sections 107/151 Cr. P.C.	Arrests under substantive sections
1	2	3	4	5
Jind	Jind	69	90	87
	Narwana	41	38	21
	Safidon	..	13	..
Gurgaon	Rewari	..	27	49
	Gurgaon	..	9	20
	Ballabagarh	6	..	..
	Ferozepur Jhirka	..	..	14
Hissar	Hissar	24	14	103

	Hansi	..	..	24
	Sirsa	6	6	13
	Bhiwani	..	2	4
Rohtak	Rohtak	..	91	17
	Jhajjar	..	5	..
	Sonepat	..	5	113
	Gohana	..	..	5
Ambala	Ambala	..	1	4
	Jagadhri	..	14	53
	Naraingarh	..	..	3
Narnaul	Narnaul	..	..	6
	Dadri	..	..	16
Karnal	Kaithal	38	1	..
	Panipat	13	5	..
	Karnal	13	..	52
	Thanesar	..	192	..
	Total	210	513	604

MESSAGE FROM THE GOVERNOR Re.

Motion of Thanks

Mr. Speaker: I have received a message from the Governor which reads as follows:-

"I beg to acknowledge receipt, with thanks of your demi-official letter No. HVS-LA-4/70/3990, dated the 19th Feb., 1970 forwarding a copy of the motion of thanks passed by Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on the 18th Feb., please convey to the Members of the Haryana Vidhan Sabha my thanks and appreciation for their kind thought in accepting the motion."

RULING BY THE SPEAKER REGARDING LEAVEE OF ABSENCE FROM THE ASSEMBLY SITTING FOR ONE DAY TO A MEMBER

Yesterday Chaudhry Sarup Singh, M.L.A. applied to me to grant leave of absence from the Assembly sitting for the 19th Feb, 1970as he was unable to move from bed. Sub-rule (10 of rule 59 of the Rules of Procedure and conduct of Business of this House provides that if a member finds at any time that he would be unable to attend the sittings of the Assembly for a perod of sixty consecutive days as computed in the manner provided in Atticle 190 (4) of the constitution he shall apply for permission of the Assembly.

According to the provision of clause (4) of Article 190 of the constitution if for a period of sixty days a member of a House of the Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings there of, the House may declare his seat vacant; provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period

during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

As the application was only for a day's absence and it did not require the permission of the Assembly for such an absence it was not necessary to bring it before the House. Though the House has already taken a decision on it, I feel that it is the sense of the House that it should not form a precedent for future.

Shri S.P. Jaiswal: Sir, if the application for leave has not to be made to the House for a perod less than sixty days, may I know whether it is necessary to make an application to anyone at all?

Mr. Speaker: You may discuss this matter with me in the Chamber, please.

Shri Daya Krishan: There is no question of getting any permission for such a leave nor has it ever been taken.

Mr. Speaker: Yes, I have already said this.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker: The matter in regard to Call attention Notice No. 8 by Shri Malik Chand Gambhir has been referred to the Government for ascertaining the facts. I will give my decision thereon on receipt of information from the Government.

Call Atention Notice No. 10 given by Shri Randhir Singh M.L.A. regarding the absence of any provision about the allotment of quarters to Dais. Health Inspectors and Sanitary

Inspectors working in the Family Planning Scheme, is disallowed, as this is not a matter of recent occurrence, rather it is a matter of continuing nature. Therefore, the matter is not so urgent or of urgent public importance and the hon. Member may please raise discussion on this matter durng the discussion on the Budget.

Call Attention Notice No. 11 given by Shri Mangal Sein, M.L.A., regariding the restless-ness amongst the traders on account of the treatment of Haryana Government is disallowed, as the matter is not of urgent nature, and may be raised during the Budget discussion.

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Sir, I beg to lay on the Table the Appropriation Accounts of the Haryana Government for the year 1968-69 and Aduit Report, 1970.

Sir, I also beg to lay on the Table the Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1968-69

DISCUSSION ON DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) 1969-70

1. Discussion on the Estimates of the expenditure charged on the revenues of the State

Mr. Speaker: If any hon. Member wants to raise discussion on the Estimates of the Expenditure charged on the revenues of the State, he may do so.

(No member rose to speak)

2. Discussion and Voting of the Demands for Supplementary Grants.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain): Sir, I suggest that all the Demands may be deemed to have been read and moved and discussed together.

VOICES: Yes, Yes.

Mr. Speaker: All right, all the Demands for Grants appearing on the Order Paper will be deemad to have been read and moved.

The hon. Members can raise discussion on the Demands but, while speaking, they will have to indicate the Demand No. on which they wish to rais discussion.

Demand No. 1

That a supplementary sum not exceeding Rs. 230831 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 9-Land Revenue.

Demand No. 3

That a supplementary sum not exceeding Rs. 147780 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 11-Taxes on Vehicles.

Demand No. 6

That a supplementary sum not exceeding Rs. 19770 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 14-Stamps.

Demand No. 8

That a supplementary sum not exceeding Rs. 216220 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 18-Parliament, State/Union Territory Legislatures.

Demand No. 9

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 19-General Administration.

Demand No. 10

That a supplementary sum not exceeding Rs. 168007 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 21-Administration of Justice.

Demand No. 19

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 31-Agriculture.

Demand No. 20

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 33-Animal Husbandry.

Demand No. 25

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3846510 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 39-Miscellaneous, Social and Developmental Organisations.

Demand No. 26

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1625190 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 42-Multipurpose River Schemes.

Demand No. 27

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16304010 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 43 and 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial and Non-Commercial)

Demand No. 29

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 50-Public Works.

Demand No. 30

That a supplementary sum not exceeding Rs. 288590 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of Charges on Public Works Department Buildings, and Roads Establishment.

Demand No. 32

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4150280 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 57-Road and Water Transport Schemes.

Demand No. 33

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7200000 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 64-Famine Relief.

Demand No. 36

That a supplementary sum not exceeding Rs. 709795 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 68-Stationery and Printing.

Demand No. 37

That a supplementary sum not exceeding Rs. 400000 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 70-Forests.

Demand No. 38

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5398650 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 71-Miscellaneous.

Demand No. 39

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1350 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 76 Other Miscellaneous Compensation and Assgnments.

Demand No. 45

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16198970 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 99-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Umbankment and Drainage Works (Commercial).

Demand No. 46

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 103- Capital Outlay on Public Works.

Demand No. 51

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defary the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of Loans and Advances by the State Government.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आज फाइनैन्स मिनिस्टर महोदया हमसे सन् 1969–70 का यह सप्लीमैन्टरी एस्टीमेंट पास करवाना चाहती हैं।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह करोड़ो रूपये का बजट मंत्री महोदया हमसे इसलिये पास करवाना चाहती हैं इन्होंने जो बजट पेश किया था उस बजट में यह खर्च शामिल नहीं किया गया था। उस समय ये इस खर्च का अन्दाजा या अनुमान नहीं लगा सकते थे जबकि यह खर्च उसमें शामिल होना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आने एप्लीमैन्टरी एस्टीमेट पढ़ा होगा, मैंने भी आदि से अन्त तक बड़े गौर से इसे पढ़ा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार का रवैया बन गया है, एक आदत सी बन गयी है एक प्रैक्टिस हो गयी है, एक लत पड़ गयी है इसको कि पहले नाजायज तौर पर मुलाजिमों को

परेशान करेंगे, उनको सस्पैन्ड करेंगे रिवर्ट करेंगे और जब वह कोर्ट आफ ला में जायेगा, न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगा दफा 80 का नोटिस देगा तो भी यह कुछ नहीं करेंगे। मुकद्मा कोर्ट में चला जायेगा तो भी परवाह नहीं करेंगे, जब एकस् पार्टी डिसीजन हो जायेगा तब सरकार बस्ता लिये भागी भागी फिरेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सरकार इतनी नैगलीजैन्सी इतनी इनएफैशियैन्सी इतनी इररिसपोंसिबिलिटी से काम करती है कि पहले किसी भी गवर्नमैंट ने ऐसा नहीं किया होगा। मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि कृपया पृष्ठ नं. 15 पर ध्यान दीजिये। इसमें इन्होंने क्या किया ? एक सब इन्सपैक्टर आफ पुलिस को रिवर्ट कर दिया और उसने जब मुकद्मा हाई कोर्ट में मूव किया तो कोर्ट ने उसको रीइनस्टेट कर दिया और रीइनस्टेट होने के बाद जब उसने पैसा मांगा तो हाईकोर्ट में दोबारा गये बिना इन्होंने उसे पैसा नहीं दिया और बाद में इन्होंने 4783 रूपये एक नया पैसा कान पकड़ कर, तौबा करके दिया।

वित मंत्रीः यह तो 1959 की बात है (विघ्न)।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः अगर आप की सरकार का कोई लफ्ज आ जायेगा तो क्या आप मन्जूर करेंगे ? (विघ्न)..... उसके बाद 1964 की बात बताता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का खून किया जा रहा है। और आगे चलिये! यहां पर ही मामला शान्त नहीं हो सका। इन्हीं के एक टैसेशन आफिसर जिला रोहतक ने एक अकाउन्टैन्ट

की अप्वायटमैंट के बारे में रिट फाइल की। इसी प्रकार से करनाल के एक सब–एजुकेशन आफिसर और पंचायत आफिसर ने एक मुकद्मा दायर किया और डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसकी तारीख 12 फरवरी, 1969 थी। यह मौजूदा सरकार यानि उस सरकार की बात है जिसे कि आप बड़ी नेक और बड़ी अच्छी सरकार कहते हैं। यह चण्डीगढ के मामले में जनता का अपमान कराने वाली और मैदान छोड़कर भागने वाली सरकार की बात है (विघ्न)।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर यह गुप्ता जी बैठे रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। हां जी, नेकी राम जी, नेकी तो आपके हिस्से, बदी हमारे हिस्से। मगर याद रखिए जैसे नाम होते है, वैसे काम नहीं हुआ करते। आम तौर पर देखा गया है कि रोड़ी मल जी फेक्ट होते हैं सूरदास हमने नेत्रहीन देखें। हो सकता है नेकी राम जी नेक काम करना तो चाहते हों परन्तु कई मजबूरियां हो जाती है। खैर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस केस के बारे मैं वह कहते हैं कि हम पर अदलत ने दण्ड इसलिये लगा दिया कि यह केस ट्रान्जिट में था और उन बस्तों के जिस में फाईलें थीं, एक महकमें से दूसरे महकमें के अन्दर जाने से ये वकील को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सके कि जाकर पेश हो। इसे नैगलिजैन्सी नहीं कहा जाए तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ही बातयें कि क्या एफिसिएन्सी कहा जाएं ?

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने हर काम में कमाल किया है। एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी बना दी है। बहाना यह बनाया जा

रहा है कि निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बनारसी दास जी गुप्ता का निर्माण बड़ी द्रुत गति से हो रहा है बड़ा फास्टली हो रहा है। हमें तो चौदह साल हो गये, गाड़ी नहीं खरीद सके लेकिन ये फिर भी ले आए। अच्छी बात है, मैं इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने गाड़ी खरीद ली है, हम तो कभी भी नहीं खरीद सकते। (वित मंत्री की ओर से विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह तो अपने संयम के कारण से आप भी कर लेते। आप भी डाक्टरों की सलाह मान लेते, दो और तीन के बाद बस कर देते। हम तो इस रास्ते पर चले नहीं और सारे का सारा माल अन्दर ही है (हंसी) तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ी टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बना दी है। यह बात ठीक नहीं है, इसे ठीक करना चाहिए। इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये फरमाते हैं कि 288590 रूपये इनको चाहिये। काम बताते हैं कि एडीशनल एक्सपैडीचर करना है, 6 डिवीजन और 2 सर्कल नये बना दिये गये हैं, एडीशनल वर्क का लोड बढ़ गया है और यह फरमा रहे हैं कि हमने पंचकूला अम्बाला से जोड़ना हैं, चंडीगढ़ से जोड़ना है आदि। हमें पहले ही पता था कि इस मैदान में ये पिटेंगे क्योंकि नीयत साफ नहीं हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी यह सारे डिवीजन क्रीएट करने की ? मौजूदा सैट आप से ही गुजारा किया जा सकता था। हमें सादगी का प्रयोग करना चाहिए था लेकिन नहीं साहब, आखिर इन्होंने तो कुद दम भरने

वालों को प्रामोट करना था, जॉब देनी थी, जगह बनानी थी, टैम्पोरेरी हैण्ड रखने थे। मेरे एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से कोई एस.डी.ओ. की पोस्ट नहीं निकाली है। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनको लाखों रूपया सैन्टर से मिला है, इन्जीनियरों की बेकारी को कम्पेंनसेट करने के लिये, स्टाईफन्ड के रूप में दिया गया है, मगर वह सारा रूपया अब अपने ही लोगों पर खर्च किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे आपति इस बात की है, ऐतराज इस बात का है, कि ये इतना खर्च करने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे। आप सड़कें बनाईये, बहुत अच्छी बात हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 22 साल में जो सड़कें बनानी चाहिये थी, जिनके बारे में आपने जनता से बारम्बार वायदे किए थे, और वोट लिए थे, यह कहकर कि आपकी सड़कें बनवायेंगे कच्ची सड़के पक्की बनवा देंगे, परन्तु आज तक उन्हें आप नहीं बना सके। अब भी अगर आपने बनानी शुरू कर दी हैं तो फजूल खर्ची न करें। उतना ही खर्च करना चाहिए जो वाजिब हो।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार नारे तो बड़े लगाती है, लेकिन काम इसके न होने के बराबर है। अब देखिये, खुरशीद साहिबा के जिम्मे बहन जी ने काम लगा दिया और आप चील गई। इनका महकमा तो है ही नहीं, इसके बीच में, वरना उस पर भी अर्ज कर देता। खैर मैं निवेदन करना चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा कि पृष्ट 35 पर आप लिखते हैं कि 72 लाख उनको

चाहिए फैमिन रिलीफ के काम के लिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप इनसे पूछिए कि रोहतक पर आप क्यों कहर ढ़ा रहे हैं, क्यों अमनपसन्द लोगों को आप बिना कसूर पकड़ रहे हैं ? हरियाणा के लिए, वहां की कुरबानी, प्यार और तपस्या का किस लिए ध्यान नहीं रखते हो ? हरियाणा की आबरू के लिए राज्य सभा की सीट ठुकराने वाले, चौधरी रिजक राम को अभिनन्दन समारोह में क्यों गिरफ्तार कर रहे हो ? डिपटी स्पीकर साहिबा, जिस रोहतक जिले की हरियाणा के लिए इतनी कुर्बानियां हैं, उस रोहतक जिले में यदि आप कभी किसी समारोह में भाग लेने के लिए मुख्य मंत्री जी के निमन्त्रण पर या वैसे ही कभी गई हों तो भिवानी से रोहतक और रोहतक से दिल्ली जाते वक्त आने देखा होगा कि समाल और सांपला के बीच में कितना पानी खड़ा है। हजारों एकड़ पानी जो है, वह हजारों एकड़ धरती को डुबोयं हुए हैं। हालांकि श्री राम धारी गौड को इन्होंने ट्यूबवैल कारपोरेशन का चेयरमैन भी बना दिया, इन्हेांने हमारे जिले को यह तो जरूर रिश्वत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसका कल्याण नहीं हो सका। मुझे तो बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि उसको यह रिमूव इसलिये नहीं करते कि इससे वहां के लोगों को अच्छी आमदनी होगी। उन लोगों को यह तकलीफ में रखना चाहते हैं क्योंकि वे मिजाज में इनके साथ मिलते नहीं है। रोहतक जिले की यह खसलत है, कि वे जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि ये हमें बहुत न सताएं बहुत परेशान न करें। रोहतक जिले

की खुदार जनता अगर कहीं बिल्कुल बेकाबू हो गई तो अच्छा नहीं होगा और आज जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं, वे भी कहेंगे कि अच्छा जी टाटा, हमारी भी जय राम जी की।

डिप्टी स्पीकर साहिबा यह मामाल यहां ही खत्म नहीं होता। इन्हेांने अपनी बहादुरी के बड़े गुण गाए हैं। कहते हैं कि हमने जो कमाल किया है, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम मान लेते इनके कमाल को अगर वाकई उसमें कुछ सच्चाई होती। आप देखिए, सफा नं. 36 इस में ये दो लाख खर्चा हम से मन्जूर करवाना चाहते हैं। यही नहीं इसके अलावा 2100 रूपये और भी मन्जूर करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि क्योंकि चण्डीगढ की सरकार के छापेखाने ने मुद्रणालय ने, प्रिंटिग प्रैस ने, हमारा सब कुछ छापने से इन्कार कर दिया है, इसलिये हमे बाहर से छपवाना पड़ता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्टेट गवर्नमैंट अपना छापाखाना खेल सकती है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। फिर छपवाई भी हरियाणा में नहीं करवाना चाहते, ये तो देहली में छपवाने की इजाजत ले रहे हैं, जहां पर मंत्री महोदयों को राजी करने वाले और तसल्ली देने वाले लोग हैं, जिनपर इनकी कृपा दृष्टि हैं इसके अलावा और देखिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, पृष्ठ 37 के पार्ट 'ए' में फरमाया गया है कि साहिब डायरैक्टर जनरल आफ स्पलाईज एन्ड डिसपोजल, जो टैक्सट बुक के लिये आमतोर पर कागजात दिया करते थे वे इस बार हमें कागज नहीं दे सकें। अंग्रेजी में लिखते है किः—

"Unfortunately, however, this quota has not been received with the result that paper required for the text books is to be purchased from the mills at higher rates."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देखिये इस सरकार की एफीशिएंसी। हमें रूपया इसलिए ज्यादा देना पड़ रहा है, हरियाणा की जनता का जो कीमती पैसा है वह इसलिये बरबाद करना पड़ रहा है कि जहां से इनको कागज मिलना चाहिये था, वहां से नहीं मिला। इनकी गफलत की वजह से हमें नुक्सान हो गया, वरना टैन्डर काल कर सकते थे और कोई तरीका अपना सकते थे ताकि प्रोपर रेट्स पर इनको कागजात मिल जाते। यहीं पर सब्र नहीं हुआ, डिप्टभ स्पीकर साहिबा, बी पार्ट में कहते हैं कि साहब क्योंकि टैक्सट बुक्स की जरूरत थी और नई नई किताबें इस समय इन्ट्रोडयूस की गई हैं इसलिये हाई रेट्स पर हमें कागज लेने पड़े। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकार ने फजूलखर्चियां कितने कमाल की की हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर आप इस बजट को और गौर से पढ़ेंगे तो आपको इस सरकार की इस तरह की और कमाल की बातें मिलेंगी। कल इसी तरह की एक बात को एक मंत्री महोदय छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कल ट्रान्सपोर्ट मंत्री कह रहे थे कि रोड ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण की बात का जवाब मैं सदन में नहीं दे सकता क्योंकि ऐसे ट्रिब्यूनल के पास मामला काबले गौर है जो क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी गाडियां नहीं चलनी चाहिए। यह ठीक है कि सरकार अपने हाथ में

यह उद्योग ले मगर हैल्दी डैमोक्रेसी में कम्पिटीशन बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार के हाथ में ट्रांसपोर्ट के मामलें में मानोपली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इंडिविजुवल के हाथ में किसी उद्योग की मानोपली ठीक नहीं। मैं पोलिटिकली प्राइवेट बस आप्रेटर्स के बहुत हक में नहीं क्योंकि अधिकतर इनका रवैया यह होता है कि जो सरकार बरसरे इकतदार होती है उसकी के साथ ये होते हैं, मगर मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको ब्राइटनैस प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जवाब दिया कि कई जगह के रूट्स का नोटीफिकेश्ज्ञन कर दिया है और कई जगह के अभी रहते हैं, तो इसके पीछे डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक ही बात है। इन्होंने जहां देखा कि फलां जगह हाथ लगाने से इनकी गद्दी को खतरा है तो उस जगह की लाइन छोड़ दी और जहां देखा कि जहां का रूट लेकर उनकी गद्दी रह सकती है उसे ले लिया। मेरे जिले के साथ तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, खासतौर पर सौतेली मां का सलूक किया गया है।

मैने एक सवाल पूछा था उसके जवाब में मुख्य मंत्री जी ने कहां था कि हम तो कर्मचारियों को छांट छांट कर लेगे। जनाब जो लोग 10 साल से गाड़ियों पर काम कर रहे है और क्लीनर, कंडक्टर और ड्राइवर रहे है, और जिन्होने अपनी मेहनत से मालिकों की नजरों में अच्छा काम साबित करके तरक्किया ली है, जब उनके लिए मैने पूछा कि ऐसे कर्मचारियों को आप

नैशनलाइजेशन करने के बाद अपने पास लेगे तो कहते है कि हम तो यह देखेंगे कि कौन से अच्छे है, कौन से नही। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, असली बात यह है कि जिन लोगों की सिफारिश आ जाएगी और एम.एल.ए. साहबान जो इनके साथ है यह रिकमड करेंगे तो वह लोग तो अच्छे हो जाऐं और जो सिफारिश के बिना होगे वे कितनी ही मेहनती और ईमादार हो वे रह जाएंगे। यह इन्होने पहले से ही स्कीम बना ली हैं जनाब नौकरियों में जो यह फेवरिटिज्म चलती है। उसकों इस्तेमाल करके इस लोकतंत्र का गला दबाया जाता है। मुझे मालूम है कि नेशनजाइज करते वक्त यह लोगों को इकुवल अपौरचुनिटी से महरूम करेगे। मै निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि रोडवेज को और प्राइवेट लोगो के बराबर कम्पिटीशन में आने का मौका दें, ताकि यह पताा चल सकें कि अगर दो गाड़ियां सड़क पर से गुजर रही है और एक औरत बच्चा लिए बस के इन्तजार में खड़ी है तो उसे बिठाने के लिए किसी गाड़ी रूकती है, किसकी नही। डिप्टी स्पीकर साहिबा हमें ऐसा करना नही चाहिए कि सारी इंडस्ट्री सरकार के हाथ में चली जाए। पीछे से मेरे मित्र विज साहब बच्चो के लिए गाड़ियों रोकन के आर्डर की बात उठाई है वह भी मै कह देना चाहता हूं–

उपाध्यक्षः आप स्वयं ही बोलिए! दूसरों की बातें आप मत कहें।

श्री मंगल सैनः जनाब, जो कुछ इन्होने कहा यह सत्य है कि बच्चों के लिए गाड़ियां खड़ी नही करते अैर वह स्कूल जाने के लिए खड़े रह जाते है और फिर सत्य बात के ग्रहण करने के लिए तो सत्यर्थप्रकाश में भी कहा है कि सत्य को ग्रहण करो और असत्य का त्याग करो। इसलिए मैं कहूंगा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि इन बच्चों का ख्याल किया जाए, क्योंकि आज की बनने वाली नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो उस पर जो प्रासाद कल के दिन बनेगा वह क्या बनेगा ? इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो सरकार की नैशनलाइजैशन की पालिसी है इसको सदन कंडम करें।

यहां एक और मद है जिसमें यह कहा गया कि सर्विसिज के सिलसिले में पब्लिक सर्विस कमीशन का खर्चा बढ़ गया है इसलिए उसके लिए 12700 रूपया दो। जनाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बाडी है, जिस तरह की जुडीशियरी होती है। लेकिन जनाब इनकी इंस्ट्रक्शन चेयरमैन को जाती हैं कि हमार आदमी ले लो और अगर वह नहीं लेते तो बैड ब्लड क्रिएट हो जाता है और सबौरडिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड बना देते हैं तथा वहां से अपना काम चला लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं और उनके बच्चों को भी यह मौका मिलना चाहिए कि वह बगैर सिफारिश के मैरिट पर सर्विसिज में आ सकें। सिर्फ जगजीवन राम को ही प्रैजीडैंट बनाना जरूरी नहीं है और भी लोग हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए। यह कहां का इन्साफ हुआ कि जो भी एस.एस.

बोर्ड बनेगा उसमें मुख्य मंत्री जी की लिस्ट जाएगी और वही लोग भर्ती किए जाएंगे।

जनाब बिजली बोर्ड में तीन लोग नौकरी देने वाले हैं। तीनों ही डिस्ग्रंटल्ड लोग हैं और वहां अब भी एक गुडगांव के डी. सी. जो रिटायर होने वाल हैं, उनको मैम्बर बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने टी.सी. अच्छी की है .....

श्री बनारसी दास गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप स्वयं ही देख लें। इनकी तो यह आदत है कि अगर पालिटिकल आदमी लो तो इन्हें ऐतराज होता है और आफिसर्ज लो तो भी इन्हें एतराज होता है .....

श्री मंगल सैनः यह कैसे कहते हैं आप ? मैं जनाब अदब से कहना चाहता हूं कि जो आदमी अच्छा होता है उसके लिए हम अच्छा भी कहते हैं। श्री दरबारी लाल गुप्ता इंटैग्रिटी के आदमी हैं He is a man of intergrity. There is no doubt about it. मैं उनकी तारीफ करता हूं:–

वह कांग्रेसी हैं लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी बड़ी योग्यता हैं। ऐक्डेमिक कवालिफिकेशन उनकी क्या है यह तो मैं नहीं जानता लेकिन वह काबिल जरूर हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं किस किस महकमें का चर्चा करूं, इन्होंने सूबे में ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं जिन को बताते हुए भी शर्म आती है।

उपाध्यक्षाः आप जरा ब्रीफ करें।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मैं इररैलेवेन्ट बोलूंगा तो आप रोक देना।

उपाध्यक्षाः इररेलेंवेंट तो आप सारा दिन बोलते रहें तब भी नहीं हो सकते।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा फिर आप जितना समय कहेंगे उतना ही बोल कर बैठ जाऊंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारी सामजवादी सरकार ने बम्बई के अन्दर 25 मंजले भवन में बैठ कर और इनको बड़े बड़े शानदार होटलों में ठहरा कर यह निर्णय किया कि हम पिछड़े लोगों को अपलिफ्ट करेंगे और मैं आपको बताऊं कि हरियाणा की सरकार गरीबों के भले के लिए एक रेस्ट हाउस में एअर कंडीशन लगा रही है।

सूबेदार प्रभु सिंहः आप आग लगवा कर उसको फुकवा दें।

श्री मंगल सैनः प्रभु सिंह जी मैं यह नहीं चाहता कि उसको आग लगवा कर फुंकवाया जाए लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप के भाइयों को और भतीजों को रहने के लिए घर दिए जाएं और उनको भी जीवन बिताने के लिए कुछ सुविधाएं मिलें वरना यह समाजवाद नहीं है कि एक बिरला गया और दूसरा बिरला पैदा हो गया, अव्वल तो बिरला जाता नहीं इनसे क्योंकि वह तो 50 लाख रूपया देता है इन को।

श्री बनारसी दास गुप्ताः बिरले पर तो आप की दया है।

श्री मंगल सैनः इस बात को तो सब जानते हैं कि भिवानी में जब मजदूरों की हड़ताल चल रही थी तो बिरला की पीठ पर श्री बनारसी दास और बंसी लाल ही खड़े हुए थे और मजदूरों को शिकस्त दिलवाई थी। खैर इस बात को मैं यहां पर ही छोड़ता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब सरकार ने कला केन्द्र खोलने शुरू कर दिए है। हरियाणा में कला केन्द्र का निर्माण होगा। पेज 41 पर जरा मुलाहिजा फरमाएं श्री बनारसी दास जी, इसमें लिखा हैः—

"Government decided to set up Haryana Kala Sangham for the promotion of Art and Culture in the State ....."

वहां पर लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। यहां पर पानी के बिना लोग तड़प रहे हैं। महेन्द्रगढ़ रिवाड़ी, और झज्जर की तहसील के लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं नसीब होता लेकिन इनको कला केन्द्र खोलने की सूझ रही है। फिर इन्होंने इम्प्रूमैंट ट्रस्टों के लिए दो लाख 76 हजार रूप्ये की मंजूरी चाही है। इसकी क्यों जरूरत पड़ी है इनको ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप तो बड़े पुराने पार्लियामेटेरियन हैं आप जानती हैं कि ज्वायंट पंजाब के वक्त में हमने आवाज उठाई थी कि यह जो प्रथा बना रखी है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और मार्किटिंग बोर्ड बना कर पुलिटिकल आदमियों को लगा देते हो यह अच्छी बात नहीं है। सरदार प्रताप सिंह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, जो आदमी इलैक्शन में हार जाता था वह उसको इस पद पर लगा देते थे।

लेकिन चौधरी बंसी लाल तो सरदार प्रताप सिंह से भी आगे निकल गए है। वह तो हारे हुए एम.एल.एज. को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया करते थे मगर इन्होंने जो एम.एल.एज. बन कर आए हुए हैं उनको लगाना शुरू कर दिया है। जनता ने जिन लोगों को अपने नुमायंदे चुन कर भेजा है उनको चुप कराने के लिए इन्होंने यह धन्धा बना रखा है। आज जिस तरह से हरियाणा में हालात पैदा किए गए हैं, इनमें अगर यह हिम्मत रखते है। तो उनको इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के चेयरमैन के पदों से हटाएं फिर हम देंखेगे कि वे कैसे इनके साथ रहते हैं। फिर इसके इलावा एम. एल.एज. को पब्लिक प्रौसिक्यूटर बनाया जाता है, एडवोकेट जनरल भी कांग्रेयिों को ही बनाया जाता है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके इलावा लाटरी के लिए 20 लाख रूपया मांगा जा रहा है। इन्होंने सारी कौम को जवारिया बना दिया है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः देहली में भी आप की पार्टी ने चला रखी है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं दाद देता हूं इनकी, बीमारी जब सारे देश में पड़ गई तो कौन बच सकता है इससे, लेकिन किसी गलत बात को एन्करेज करना ठीक नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि आप हरियाणा में कोई अच्छा काम शुरू करें, हम आपके साथ होंगे। पहले तो लाटरी दो महीनें के बाद खुला करती थी, फिर महीने के बाद निकालनी शुरू कर दी, अब हफते के बाद खोलनी कर देंगे और फिर हर रोज निकलनी शुरू

हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे लोगों को जुआ खेलने की आदत पड़ती है इसलिए ऐसी चीज को रोकना चाहिए। फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा एडवोकेट जनरल के लिए पैसा मांगा है। पहले तो हम केवल पुलिस वालों में ही कुरप्शन देखते थे लेकिन अब वकीलों को केसिज देने में भी कंसिड्रेशन होती है कि फलां आदमी को देना है फलां आदमी को नही देना है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक माध्यम है बोलने का इसलिए मैंने यह बातें कही हैं। हो सकता है मेरी बातें इनको कड़वी लगी हों लेकिन सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। यह माने या न माने इनकी मर्जी हे। इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि इन डिमांडज को पास नहीं किया जाना चाहिए।

Deputy Speaker: As the hon. Members are aware, guillotine is to be applied before half an hour of the normal hour of intgerruption and the Minister may also require some time to reply to the discussion, I will request the hon. members to be brief.

मेजर अमीर सिंह चौधरी (बाधड़ा): उपाध्यक्ष महोदया, आज हाउस के सामने 600.62 लाख रूपये की मांग पेश की गई है और उस पर विचार चल रहा है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी रकम की मांग दूसरी सप्लीमैंटरी खेप में लाना बड़ा ही अनुचित है। इस रकम की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार दी है कि 438.63 लाख रूपया रैबन्यू से और 161.99 लाख रूपया कैपीटल ऐंड लोनज ऐंड ऐडवांसजि से रीलेट करता है। दूसरे रूप में जो

व्याख्या की गई है उसमें लिखा है कि 28 लाख रूपया सिंकिंग ऐंड डेप्रिसिएशन फंड में जायेगा, 114.44 लाख रूपया डायवशैन फ्रीम अदर ग्रांटस का होगा और 72 लाख रूपया पेमैंटस आफ इन्ट्रस्टस चार्जिज का होगा यानी यह कुल मिला कर 214.44 लाख की रकम ऐसी है जो किताबी जमा खर्च है और यह रकम खजाने से बाहर नहीं जायेगी ऐसा इन्होंने जाहिर करने की कोशिश की है। आगे चल कर बताते हैं कि 386.18 लाख रूपया ही ऐसा है जो हमारे खजाने से बाहर निकलेगा। यह तो है इस दूसरी खेप की व्याख्या और पहली सप्लीमैंटरी खेप से यह 109.57 लाख रूपया पहले ही ले चुके हैं। इस तरह आप देखेंगे कि पिछले का बजट पास हो जाने के बाद में यह 495.75 लाख रूपया की इतनी भारी रकम हमारे से सप्लीमैंटरी मांगों के रूप में मांगते हैं। यह रकम कोई मामूली रकम नहीं है और मुझे तो, जो एक छोटी सी साबिक जींद स्टेट का रहने वाला हूं जहां पर कि कुल 33 लाख का बजट होता था, यह रकम बहुत बड़ी लगती है। बजट पास हो जाने के बाद इनती भारी रकम सप्लीमैंटरी मांगों के रूप में मांगना मैं समझता हूं महासबे के असूल के बिल्कुल खिलाफ है। यहां पर इस वक्त फाइनैंस मिनिस्टर साहिबा नहीं बैठी हैं वरना वह गुस्सा हो जाती मेरे साथ लेकिन मैं यह बात जरूर कहूंगा कि इतनी बड़ी रकम साल का बजट पास करवाने के बाद सप्लीमैंटरी मांगों के जरिये लेना इनका लैक आफ फोरथट, लैक आफ इनिशिएटिव और लैक आफ पलैनिंग है। इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? जहां तक सरकारी मशीनरी का सम्बन्ध है और जो हमारे फाइनैंस सैक्रेटरी हैं

मुझे खुशी है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला है और मैं उनको अपने पुराने अफसरों में बेहतरीन अफसर समझता हूं और मुझे ख्याल भी नहीं हो सकता कि वह इस किस्म की भारी रकम जो महासबे के असूल के खिलाफ है हमारे इस तरह ला सकते हैं न ही उनके प्रैडीसैसर मेरे ख्याल से ऐसा कर सकते हैं। गो मुझे उनके साथ नजदीक से काम करने का मौका नहीं मिला है लेकिन मैं उनसे बखूबी वाकिफ हूं और उनको मैं अच्छे अफसरों में से समझता हूं। उनसे भी मुझे ख्याल नहीं हो सकता कि वह इस किस्म की बजट के बनाने में गलती कर सकते हैं जो बजट पास करवा लेने के बाद इतनी बड़ी 600 लाख की रकम सप्लीमैंटरी मांगों के रूप में मांगने की जरूरत पड़े। फिर यह हुआ कैसे ? होने का यही कारण हो सकता है कि या तो हमारी सरकार मे अनस्टेबिलिटी हो गई होगी और या हमारे दोस्तों का उन पर बहुत दबाव बढ़ गया होगा कि या तो मेरे यहां यह सड़क बना दो, यह पुल बना दो, मोघ बना दो, नहीं तो हम भागते हैं। इन हालात में क्या करें फाइनैंस सैक्रेटरी मिनिस्टरी की बात तो मंजूर करनी ही पड़ेगी। मिनिस्टरी भी क्या करे ? उनकी भी मजबूरी है और यह उनकी ही मजबूरी नहीं हमारी भी यही मजबूरी हुआ करती थी मैं जानता हूं। (हंसी) इनकी यह मजबूरी भी होगी या यह भी होगा कि इनका यह ख्याल हो गया होगा कि पता नहीं यह हमूमत तो रोटियों पर ढीजंड है, मिनिस्टरी का क्या पता कब लुढ़क जाये, इन्दिरा जी का राज खतरे में है इसलिये बना लो जो बनता है, बना लो यह वह फीडर

और सड़कें। (विघ्न) हो सकता है मैं गलती पर होऊं लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं इनमें से कोई न कोई बात जरूर होगी नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि बजट पास करवा लोने के बाद इतनी भारी रकम सप्लीमैंटरी मांगों के रूप में लेकर हाउस में आ गय। (विघ्न) खुरशीद साहब कहेंगे कि मेजर साहब आपने भी ऐसा किया है। ठीक है किया होगा और मैं तो कहता हूं कि इस हमाम में तो सभी नंगे हैं (हंसी) आपको करना पड़ा होगा मजबूरी होती है लेकिन जहां तक महासबे का असूल है वह गलत हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरा मेरा एतराज यह है कि इन्होंने 114.44 लाख रूपये की ओवरआल सेविंग को मुजरा करने की कोशिश की है। किसी मद में हजार पांच सौ की सेविंग हो जाये तो कोई बात नहीं लेकिन यहां तो आप देखेंग कि लाखों के हिसाब से बचत की गई है। मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी रकमों के मुतालिलक बताना चाहता हूं कि किस तरह बजट में ओवरआल सेविंग हुई। डीमांड नम्बर 9 जिसके साथ स्टेट लाटरीज का ताललुक है उसमें 20 लाख की ओवरआल सेविंग हुई है। कोई आदमी जिसके सिर में दिमाग है वह क्या कभी कह सकता है कि यह ठीक बजट है जिसमें 20 लाख की सेविंग हो जायें ? क्या यह बजटिंग का सही नमूना है ? मेरे ख्याल में यह बड़ी अनक्रैडिटेबलल बात है। फिर आप देखें डिमांड नम्बर 19 जो ऐग्रीकल्चर के बारे में है उसमें 994 हजार रूपये की सेविंग होगी। कितनी अजीब बात है कि किसानों का खेताबाड़ी का महकमा हो और उसमें लाखों के हिसाब से बचत हो जबकि हालात यह हो कि किसान बीज खाद,

पानी और दूसरी बातों के लिए चिल्ला रहे हो। मैं तो समझता हूं कि या तो बजट बनाने वालों का दिमाग काम नहीं करता या डिमांड करने वालों का दिमाग नहीं करता वरना कोई वजह है कि जरायत के महकमा में आम हालात में इतनी बचत हो जाये। यही बस नहीं आप देखें कि डिमांड नम्बर 20 जो ऐनीमल हसबैंडरी की है और किसानों से ही रीलेट करती है उसमें 260680 रूपये की बचत की गई है। इससे मालूम होता है कि हमारे महकमों के आला अफसर किसानों के कामों के लिये बजट से लिया हुआ पैसा भी पूरा खर्च नहीं करते हैं वरना यह कैसे हो सकता कि इन मदों से इतनी बचत हो जाये जबकि लोग चिल्ला रहे हों। इसी तरह पब्लिक वर्कस की मद में तकरीबन दो लाख की और कैपीटल आउटले आन पब्लिक वर्कस की मद में पांच लाख से भी ज्यादा सेविंग दिखाई गई है। इसी तरह लोन ऐंड ऐडवासिंज बाइ दी स्टेट गवर्नमैंट की मद में तीन लाख की बचत दिखाई गई है। यह तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने बड़ी बड़ी रकमें ही बताई है छोटी मोटी तो और कई है। मेरा ख्याल है कि यह बजटिंग के असूल के मनाफी बात है और मैं समझता हूं कि किसी बजट में इतनी बड़ी गुंजायश होना महासबे के असूल के खिलाफ है और इसे मैं बैड बजटिंग ही कह सकता हूं कि फायनैंस डिपार्टमैंट वालों से महकमें इस तरह से पहले पैसा पास करवा कर ले जायें और फिर उसे खर्च न करें यह फाइनैंस डिपार्टमैंट पर जरूर रिफलैक्शन है। वजीर खजाना तो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो मिनिस्टर साहबान यहां पर बैठे हैं वह मेरे

ख्यालात उनके पास पहुंचाने की कृपा करेंगे कि इस किस्म की बैड बजटिंग नहीं होनी चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, तीसरा ऐतराज मेरा यह है कि कुछ रूपया इस मुतालबे मे ऐसा शामिल किया गया है जिसकी मांग उसी वक्त होनी चाहिए थी जिस वक्त वह खर्च हुआ था। यानी कुछ रूपये की मांग पहली इन्स्टालमेंट में की जा सकती थी। इसके अन्दर दर्जनों मिसालें ऐसी मिलेंगी जो कि पहली इन्स्टालमेंट के अन्दर शामिल की जा सकती थीं, लेकिन नहीं की गई। यह बड़ी सख्त किस्म की कोताही है जिसके मुताल्लिक सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

चौथा एतराज मेरा यह है, उपाध्यक्ष महोदया, कि इस मांग की शेप में कुछ इस किस्म के हैड्ज देखने को मिलेंगे जिन को हमने कभी सुना ही नहीं हैं। एक हैड के अन्दर लिखा है – 'विलेज री कंस्ट्रक्शन एंड हरिजन अप लिफ्ट'। इस हैड में सारे का सारा काम हरिजनों का है, विलेज अप–लिफ्ट का कोई काम है ही नहीं। इस किस्म के हैड के नाम रखना जिसका आपस में सम्बन्ध ही नहीं है, ठीक नहीं है। एक हैड 'नैवीगेशन' का रखा है। हरियाणा में नैवीगेशन का क्या ताल्लुक है ? सवाल पूछने पर बताते हैं कि यह हैडज के नाम तो आल इंडिया पैटर्न पर है, ठीक है होगा आल इंडिया के पैटर्न पर लेकिन हमारा इसके साथ कोई समबन्ध नहीं है, हमारा तो कभी एक आध लकड़ी का बेड़ा जमुना नगर में आता हेगा या न आता हेगा, हमें तो मालूम नहीं है। इस

किस्म के हैड नहीं होने चाहिए जिनका हरियाणा में कोई मतलब ही नहीं है। नाम ऐसा होना चाहिए जिसको सब समझ जाएं। अगर आप ऐसे हैड रख देते हैं तो आम पब्लिक का आदमी समझता ही नहीं है, वह कह देता है कि हमारी स्टेट का नहीं, किसी और स्टेट के बारे में होगा। इसलिए सरकार से दरख्वास्त हैं कि इन चीजों को आवाइड करके ठीक नाम रखने चाहिए।

इन जनरल ऐतराजों के बाद, उपाध्यक्ष महोदया, मैं अब अकेली अकेली डिमांड के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। इसमें कुछ रूपया पुलिस डिपार्टमैंट के लिए मांगा गया है। अब हमने देखना है कि आया पुलिस डिपार्टमैंट को पैसा देने की जरूरत है या नहीं। पुलिस का हमारे साथ बरताव कैसा है जिसके लिए रूपया देना ठीक है या नहीं यह देखने वाली बात है। मैंने पुलिस की हालया कारवाईयां देखी हैं जिन से मेरे दिल में बदगुमानी पैदा होती है। इन कारवाईयों को देखकर सदन को विचार करना चाहिए कि आया हम यह रूपया दें या न दें। चण्डीगढ़ के मुतालिलक जब फैसला हुआ तो मेरे जिलें में दादरी और नारनौल में काफी गड़बड़ हुई। दादरी में एक लड़का मारा गया, नारनौल में भी एक लड़का मारा गया। जब दादरी में वह लड़का मारा गया उस वक्त में ऐस्टीमेट्स और अश्योरैन्सीज कमेटियों की मीटिंग अटैंड कर रहा था। मीटिंग अटैंड करने के बाद जब बसें दोबारा चली और मैं दादरी गया तो लोगों से पूछा कि मामला क्या था ? सारे हालात को देखते हुए मैंने समझा कि झगड़े की सम्भावना ही

नहीं थी। जो कुछ हुआ वह एक सब–इन्स्पैक्टर और हौलदार के कारण हुआ। इन दोनों ने ही सारी बीमारी पैदा की थी। बीमारी पैदा करने के बाद, उपाध्यक्ष महोदया, गोली चली जिसमें एक लड़का मारा गया। अंग्रेजों के जमाने में जब गोली चलाई जाती थी तो पुलिस को यह हुक्म होता था कि गोली शरीर के नीचले हिस्से पर मारनी है, अधिकारियों की स्टैंडिग इन्स्ट्रक्शन्ज हुआ करती थी, लेकिन मैंने देखा है कि दादरी में बच्चे के सिर पर गोली मारी गई, इन्होंने बक शूटिंग किया है। गोली भी मौका देखकर शराब की दुकान के सामने चलाई और दिखाया यह गया कि गुरूद्वारे में गोली चली। इस किस्म का बोगस केस बनाया जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। इनका कोई असूल ही नहीं, असूल होता तो सैल्फ सैल्फ डिफैंस का केस बनाते जा कि कन्विसिंग हो सकता थ। इन्होंने गुरूद्वारे की आड़ लेकर उस केस को खराब कर लिया और हमको शायद 15–20 हजार रूपये फजूल के पुलिस की मैहरबानी से नुकसान के देने पड़े। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम गुरूद्वारे में ऐसा काम नहीं कर सकते थे, उस गुरूद्वारे के लिए हमने जमीन दी, उसकी मेन्टेनेंस करते हैं फिर उस गुरूद्वारे को तोड़ने के लिए हम कैसे जा सकते हैं ? वह गुरूद्वारा पंजाब गवर्नमैंट का नहीं है, हमारा है। कितनी बुरी बात है कि पुलिस छोटे छोटे बच्चों को केस बनाने के लिए ले गई और कह दिया कि वाकई गुरूद्वारा लुटा है, इंटें उखड़ी हैं। पुलिस इस किस्म की चीजें करती है जो बेबुनियाद और अनुचित है। ठीक है गोली चलानी पड़ जाया करती है। मैं इस बात के हक में हूं कि सैल्फ

डिफेंस के लिए अगर एक आध आदमी मारा भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके हक में नहीं हूं कि किसी को कुते की तरह मारा जाए। मारा कहीं और जगह, जाता है और दिखा दिया जाता है कि गुरूद्वारे में मारा गया है। दूसरा जवान कहां पर मारा गया, यह शायद मेरे दूसरे साथियों को पता नहीं है। उसको हस्पताल में ले जाकर मारा और उस पर केस बनाने के लिए पुलिस ने अपनी जीप फूंक दी। वे कहते हैं कि हमने नहीं फूंकी, पुलिस ने केस बनाने के लिए यह काम किया है। इसके इलावा पुलिस ने हस्पताल के मकान में घुस कर गोली चलाई। मैं पूछता हूं कि पुलिस हस्पताल में किस लिए गई थी, उसका हस्पताल में क्या काम था ? इसी तरह नारनौल में हुआ। अगर सरकार की इस किस्म की पुलिस हो ओर इस किस्म की वारदातें करे तो मैं समझता हूं या तो पुलिस की ट्रेंनिग में नुक्स है या इसकी री–औरिएंटेशन नहीं है। ऐसी घटनाएं तो अंग्रेजों के जमाने में व्यूरोक्रेसी में भी नहीं होती थी जो कि आज हरियाणा में हो रही हैं। मैं इस रोटी के टींड जैसी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं क अगर वह इस तरह अनुचित कारवाईयां करती जाएगी तो वह हमें बरदाश्त नहीं होगी। यह तो डैमोक्रेसी है, कल राव साहब की सरकार थी, आज बंसी लाल की सरकार है, इससे पहले कैरों साहब की सरकार थी, इस तरह वक्त बदलता रहता है लेकिन इनके डीड्ज नहीं बदलते। इसलिए सरकार को हर काम सोच समझ कर धीरज से करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पुलिस को ऐसे घटिया तरीके नहीं अपनाने चाहिए जिससे देश की फिजा खराब हो। हमने पुलिस की इस कारवाई की इन्क्वायरी करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब से मांग की है कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए लेकिन बड़े दुख की बात है कि पता नहीं किन बातों को सोचकर चीफ मिनिस्टर साहब ने जुडिशियल इन्क्वायरी करवाने से इन्कार कर दिया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अंग्रेज के टाईम में फौज को यह हुक्म था कि जब तक मजिस्ट्रेट से रिटन सर्टिफिकेट न ले लिया जाए तब तक फायरिंग नहीं होती थी लेकिन इन्होंने पागल कुते की तरह शिकार खेला। यह छोटी मोटी बात नहीं है जिसको जुडिशियल इन्क्वायरी के बिना छोड़ दिया जाए। अगर आज जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं होगी तो साल के बाद होगी, दो साल के बाद होगी लेकिन जरूर होगी। और जब होगी, तो ये डीड्ज सामने आयेंगे। इसलिए अच्छा है आज ही कर लें। मेरी वजीर साहबान से रिक्वैस्ट हैं कि वे जरूर इन्क्वायरी करा लें, आज आपकी सरकार है इसलिए कुछ न कुछ बचत हो जायेगी। जिस वक्त ये चले जायेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि जुडिशियल इन्क्वायरी तो जरूर होगी कभी न कभी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सुझाव देना चाहता हूं, मैं किसी जोश मे या तैश में आकर नहीं कहता कि I have gone grey with years. मैं अपनी सरकार को मश्वरा दूंगा, सलाह दूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि वह जुडिशियल इन्क्वायरी करवा लें, नहीं तो आप चले जायेंगे और सरकारी कर्मचारियों को फंसा जाओंगे क्योंकि सरकारी कर्मचारियों

ने तो अपनी ड्यूटी देनी है। अगर आपने अपनी ड्यूटी के अन्दर कर्मचारियों को ऐसा मौका नहीं दिया जिसमें वे अपनी वरीयत हासिल कर सकं तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जमाने के अन्दर, देश या प्रदेश में जब कोई मूवमैन्ट चलता है, कोई आन्दोलन किसी बात के लिए होता है तो बीच में से कुछ आदमी गलतियां भी कर जाते हैं। सरदार भक्त सिंह और उद्यम सिंह, आप जानती हैं, अंग्रेजों के साथ गोलियों से लड़े जो कि हमारा निशाना नहीं था मगर हम उनके शुक्र–गुजार हैं, धन्यवादी हैं और उनके प्रति हमारे मन में इज्जत की भावना है क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें दी हैं। उनके अन्दर देश को आजाद कराने के लिए एक जोश था जिसको उन्होंने अपने ढंग से इस्तेमाल किया। हो सकता है कि चंडीगढ के मामले को लेकर हरियाणा से प्रेम रखने वाले कुछ बच्चों ने और नौजवानों ने इस प्रकार की गलतियां की हों, मगर उनके तथा उनके वालदेन के ऊपर केस बनना, उनकी गिरफ्तारियां करना और मरे हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित न करना मैं समझता हूं ठीक बात नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपने ढंग से हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ी है और जानें दी हैं। मैं तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन आदमियों में से हूं जो मिल्टरी आपरेशन्ज में भी शत्रु के सफेद झंडा दिखाने पर स्टेलमेट का आर्डर देकर उसे डैड बोडीज और जख्मी ले जाने देते हैं और उसकी दवाईयां खत्म हो जाने पर अपनी दवाईयां दे दिया करते

है। सिविल के तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ कायदे और होते हैं। तशदद करना तो मेरे असूल के खिलाफ है मगर मैं गवर्नमैंअ के इस मौजूदा एटीच्यूड का भी विरोधी हूं। पीछे जैसे मैं दादरी गया तो लोगों ने मुझे बताया कि छोटे छोटे बच्चे छाती के ऊपर के बटन खोल कर यह कहते थे कि यहां गोली मारो। इसमें माश्र्ज्ञल और नान मार्शल रेस की बात नहीं थी बल्कि छतीस की छतीस जातियों के लोग ऐसा कहते सुने गए हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां मुझे इन बातों का अफसोस है वहां एक बात की खुशी भी है कि हमारे यहां एस.डी.एम. और डिप्टी कतिश्नर ने बड़ी खुशअसलूबी से मामले को हैन्डल किया और कम से कम नुकसान होने दिया। मुझे तो यह खदशा था कि अगर कही दादरी और मेरे जिले के दूसरे हिस्सों मे खून खराबा शुरू हो गया तो वह बहुत हद तक बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों ही नौजवान अफसर थे। मैं उन्हें मप्लीमैन्टस पे करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर दादरी के अन्दर वह एस.डी.एम. न होता, वह मौके की नजाकत को न समझ पाता तो कम से कम 50–60 के करीब आदमी मारे गए होते। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर ने बड़ी खुश अस5लूबी से मामले को हैन्डल किया। यह हैं कायदे जिनके मुताबिक डैमोक्रेसी के अन्दर काम होना चाहिए। मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह अंग्रजों वाले ख्यालात में न फिरें। अंग्रेज तो ऐसे टाईम पर सौ दफा सोचकर कदम उठाता था मगर इस सरकार ने बिना सोचे समझे सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून डाला। यमुनानगर में चील गोली के

बारे में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। वहां दो आदमी पुलिस की गोली से मारे गए। कितने अफसोस की बात हैं ? हमने आज तक संसार में लाखों गोलियां चलती सुनी और चलाई भी मगर इस तरह की बात न कभी सुनी और न देखी कि दो बार गोली को चालाया तो सड़क पर गया हो और वह दोनों की दोनों दो आदमियों को निशाना बनाकर मौत का मुजीब बनें। डिपटी स्पीकर साहिबा, गोली चलाने वालों के लिए यह बड़ी एलीमैन्टरी सी बात है कि सीधी गोली का एन्गल कुछ और होता है ओर जमीन से भड़क कर लगने वाली गोली का अन्गल कुछ और होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस वालों ने फट से स्टेटमैन्ट दे दी कि गोली जो थी वह सड़क के ऊपर लगी और वहां से भड़क कर उन्हें लग गई। मैं इन चीजों को, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कनडैम करता हूं और जो जवानों ने तशदद किया उसे भी एप्रूव नहीं करूंगा लेकिन जिस भावना के साथ उन्होंने हरियाणा के लिए कुर्बानी की उसके लिए मैं सिर झुकांऊगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इरीगेशन का मसला सबसे अहम है। इस सप्लीमैंन्टरी बजट के अन्दर इसके लिए सबसे बड़ी रकम मांगी गई है और मांगनी भी चाहिए क्योंकि हमारी कृषि प्रधान स्टेट है लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि पानी कहां से आएगा ? आज बता दिया पोसवाल साहब ने कि यह तो नौन पैरेनियल होगा लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो पैरनियल और नोन पैरेनयल नहरें पहले बनी हुई है जब उनके अन्दर ही पानी नहीं

आता तो नई नहरों के अन्दर कहां से आ जाएगा ? मुझे खुशी है कि जुई के अन्दर नहर बनाई जा रही है लेकिन मुझे खदशाहै कि पानी कहां से आएगा जबकि पहले वाली नहरों में ही पानी नहीं आ रहा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, दादरी लिफ्ट साहिबा, दादरी लिफ्ट स्कीम के ऊपर 24–25 लाख रूपया खर्च हुआ पड़ा है और कैंरो साहब के टाईम से वह स्कीम शुरू हुई थी लेकिन आज वह लटकती फिर रही है। चौधरी रणबी सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। ये उन दिनों इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर थे। इन्होंने उस वक्त कहा था कि हम एरिड एरिया को बढ़िया सरसब्ज एरिया बनाएंगे। हमें यह सुनकर बड़ी खुशी हुई थी कि चलो हमारे एक मित्र के हाथों हमारा एरिया सर–सब्ज बनेगा। लेकिन आज मुझे एक सवाल के जवाब में उतर मिला है कि अभी तक गवर्नमैंट फैसला नहीं कर पाई है कि आया इस फीडर के बंद किया जाएगा या नहीं। यह मामला अभी सोच के अन्दर है। क्या किसी जगह 24 लाख रूपया खर्च करके आप वापिस जाना चाहते हैं ? क्या हम इजाजत दे पाएंगे कि 24 लाख रूपया खर्च करने के बाद आप कह दें कि यह काम फिजिबल नहीं है ? हरगिज नहीं। फाइनैन्स मिनिस्टर साहिबा, आप इन इंजीनियर्ज के चक्कर मतें न पड़िए। इस चक्कर में पड़ने से बहुत इमप्लीकेशन्ज पैदा हो जाएंगी। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरे कमरे में आ जाना। मेरी पोजीशन तो यह है कि मुझे चाहे कमरे में बुला लो, बाहर बुला लो या अन्दर बुला लो, मैं वहीं समझ लूंगा लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि कमरे में पानी कहां से आएगा ? वहां तो ये चाय पिला देंगे और शायद

पेड़े–सेड़े भी खिला देंगे लेकिन पानी नहीं आएगा कमरे के अन्दर। इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी तो इनसे यही विनम्र प्रार्थना है कि पहले इनको पुराने प्राजैक्टस के ऊपर काम करना चाहिए, फिर दूसरे नए प्रोजैक्ट हाथ मै लेने चाहिए। आज पोजीशन यह है कि रेवाड़ी लिफ्ट प्रोजैक्ट आधे में पड़ा है, सोहाना लिफ्ट प्रोजैक्ट फांसी टंगा हुआ है और दादरी लिफ्ट प्रोजैक्ट इज हैन्गिंग फायर मगर इन्होंने इनको पूरा करने की बजाय जूई प्रोजैक्ट शुरू कर दिया। इससे तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह प्रोजैक्ट ाके ीाी छोड़कर झेझू फीडर या कोई दूसरा प्रोजैक्ट शुरू कर देंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। यह इंजीनियर्ज का काम है कि वे पूरी प्लानिंग करें। उसके बगैर अगर चलेंगे तो उसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। हम तो कह सकते हैं कि काम यहां की बजाय वहां और वहां की बजाय यहां होना चाहिए मगर इंजीनियर्ज का काम है कि वह मश्वरा दें कि साहब यह पानी ले जाना गलत है जबकि आगे वाली नहरों को हम पानी नहीं दे सकते। मैं तो कुमिटमैंन्ट नहीं कर सकता, आप कर लें तो आपकी मर्जी।

उपाध्यक्षाः मेजर साहब, आपको आधा घंटा बोलते हुए हो गया। कितना टाइम और लेगे क्योंकि और भी मैम्बर्ज बोलना चाहते है?

मेजर अमीर सिंह चौधरीः अगर आप मुझे हुक्म दें तो मै अभी बैठ जाऊंगा लेकिन अभी तो मुझे बहुत सी बातें कहनी है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मै मजेदार और काम की बातें कहूंगा तब तो मुझे बोलने और अगर रेपिटिशन करूंगा तो भले ही रोक देनाख मै उसी वक्त बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्षः बातें तो आपकी काम की होती है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः अच्छी बातें तो फिर सुननी चाहिए।

उपाध्यक्षः आप मेजर साहब बारह बजे तक बोल लीजिए।

मेजर अमीर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा मै कोशिश करूंगा कि आपने मुझ 10 मिनट का टाईम दिया है उससे पहले ही अपना भाषण समाप्त कर दूं। अर्थात 9 मिनट के अन्दही ही। हां यह जरूर है हक 15 मिनट भी लग जाये तो मै आपेस माफी चाहूंगा क्येंकि मुझे झूठाा तो नही बनना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मै जमींदारों की भलाई की बातें कर रहा था आपने वह सारा सिलसिला ही तोड़ दिया क्येांकि किसी चलती हुई ट्रेनको रोक देने के पश्चात उसकों दुबारा स्पीड पकड़ने में कुछ समय लगता है। उपाध्यक्ष महोदया आबपाशी बहुत जरूरी चीज है। आबपाशी के लिए जब तम पूरे साधन नही अपनाये जायेंगे तक तक इस हरियाणा का कल्याण नही होगा। आज महेन्द्रगढ़ का जिला खाने को आता है इसका कारण यह है कि वहां पर उस एरिया में आबपाशी के कोई साधन ही सरकार की और से नही आनाये गये

है। अब एक महीने के पश्चात वहां पर निकलने को रूह नही करती है वहां पर आये मौसम के अन्दर कभी हैजा बनारहताहै, कही कुछ बना रहता है वहां जब तक पानी के साधन नही अपनाये जोयगे तब तक कल्याण नही हो सकता। वहां पर आज से 15 साल पहले दादरी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम आरम्भ की गयी थी परन्तु आज तक वह ज्यों की त्येां की खटाई में पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, यह बात किसी भी सरकार और उस सरकार के इंजीनियर्ज के लिए क्रेडेटबल नही हो सकती। यदि 24 लाख रूपया खर्च करने के पश्चात यह विचार करें कि उसकों बन्द किया जाये या आगे को वह स्कीम ने चलायी जाये। बड़ी हैरानी की बात है कि 15 सालों के अन्दर यह सरकार यह फैसला नही कर पायी कि उसकां चालू रखे या बन्दे करें। क्या 24 लाख रूपया खर्च करने के पश्चात हम इस कदम को वापिस मोड़ने देंगे? मै तो कहूंगा कि ऐसा तो सरकार के लिए सोचना या कहना ही बेकार है।

उपाध्यक्ष महोदया मैने पहले भी एक मौके पर बहिन ओम प्रभा जी से कहा था कि यह जो हिसार और करनाल में बन्दोबस्त का काम है इसकों मत करेां परन्तु इन्होने उसकों छेड़ दिया। मैने तो उसी समय कहा था कि ये काम राष्ट्रपति शासन में हुअ करते है। ये काम हमारे टाईम में नही हो सकते है क्योंकि उनको तो वोट नही लेने होते और हमें जनता से वोट लेने होते है इसलिए हम और आप इस काम को नही कर सकते है चाहे

आपका राज हो या हमारा राज हो। मैने इस बात को सदन के सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया था कि डैमोक्रेसी के अन्दर आप किसी चीज को बढ़ा सकते हो, घटा नही सकते। जींद के जिले को आप तोड़ना चाहों तो तोड़ नही सकते हां, कैथल का अगर जिला बनाना चाहते हो जिला बना सकते है हो लेकिन तोड. नही सकते। डैमोक्रेसी में तो ज्यादाह हो सकता है चाहे आपका राज हो या हमारा राज हो इसमें कोई अन्दर नही। इसलिए यह सोचना कि बन्दोबस्त कर पायेंगे, यह बिल्कुल गलत है। इस सरकार ने 13.16 लाख रूपया जाया करने के पश्चात् आज उस बन्दोबस्त को बन्द कर दिया। उस समय हमारी नही मानी। अगर आप हमारी अपोजीशन वालों की नही मातने हो तो मै मित्तल साहब से रिक्वैस्ट करता हूं, उनकी ही सुनायी कर लिया करों, वे ही आपकों समझा देगे। साढे तेरह लाख रूपये को इस सरकार ने मिट्टी में मिला दिया और अब फिर वह मुरबाबन्दी शुरू कर दी। मुरबाबन्दी की उपाध्यक्ष महोदया यह हालत है मेरे अपने महेन्द्रगढ़ जिले के अन्दर 20 गांव ऐसे है जिनके आज तम कब्जा बदल नही हुए। इन बातों को आज 14–15 साल हो गये। एक आदमी दूसरे आदमी का मुजारा बना बैठा है और उनकी रिदावरी भी होती है परन्तु यह पता नही लगता कि किस तरीके से गिरदावरी होती है। उन जमीदारों को न कोई कर्ज मिलता है और न ही एक गांव से दूसरे में जाने के लिए रास्ते मिल हुए है। इधर हरिजनों के बसाने के लिए भी कोई जगह नही और यहां कहते है कि हरिजनों की बडत्री सहूलियते दे रहे है। जब पूछा जाता है तो जवाब मिलता है

कि यह इलाका रेतीला है, यह पहाड़ी है, यह दिया वाला है। इस प्रकार की दलीले दी जाती है। रास्ते की तो दरिया वालों को भी जरूरत होती हैं जो दरिया वाले है उनमें हरिजनों को भी बसाने के लिए जगह चाहिए। गांवों की दूसरी जरूरते है जैसे पंचायत फार्म है यह भी पंचायतों की आमदनी के लिए जरूरी हैं जब तम मुरबा–बन्दी नही करेगे तब तक ये सब चीजे कहां से होगीत्र इसलिए मुरबा–बन्दी तो करनी ही पडत्रेगी। अगर कोई नही भी कराना चाहतात ळै तो भी करनी ही पड.ेगी। इसके बगैर तो बिल्कुल काम नही चालेगा। मैने अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर से पूछा कि ऐसे हालात क्यों बने हुए है। उन्हौन बताया कि एक ए. सी.ओ. साहब ऐसे है उनकी मैने भी शिकायत कर ली, एस.डी.एम. साहब ने भी शिकायत कर ली, पर पता नही चलता, वह तो ऊपर से ही छुट्टी ले आताहै दामोदर दा जी मेरे पैप्सू के अपने अफसर है रेवेन्यू के महकमें के बड़े काबिल अफसर है। रेवेनयू डिपार्टमैंट में तो उनकी बराबर को मै किसी अफसर को नही समझता क्योंकि रेवेन्यू के बारें में उनकों बहुत ज्यादा ज्ञान है। बड़े संजीदा किस्म के अफसर है परन्तु वे भी मुरबा–बन्दी की समस्याओं को हल नही कर पाये है पता नही इसके पीछे क्या कारण है? मुझे तो यह यकीन है बेसिकली कोई इसके अन्दर रौंग (Wrong) है। मै बहिन जी, आपकी मार्फत यह दिवेनदन करूंगा कि वे इस पर विचार करे। मुरबाबन्दी के मुताल्लिक में फिर अर्ज करूंगा कि आप हमारे कहने से नक करों परन्तु हरिजनों के नाम से ही जिनकी आप मदद करना चाहते है, कर दो। हरिजन दुखी है, गांवों की पंचायतें

दुखी है लेकिन फिर भी आप मुरबा बन्दी नही करते है। इसलिए इस ओर आप अवश्य ही कदम उठाये और जरूरी कदम उठाइये।

उपाध्यक्ष महोदया, दो लाख 16 हजार दो सौ रूपया इलैक्शन के लिए मांगा गया है। मुझे यह पता नही क्या खतरा आ गया है या दिल्ली की सरकार कमजोर हो गई है। जिसके कारण ये इलैक्टोरल–रोल तैयार कराये गये। जब इलैक्शन होने को होता तभी तैयार करा लेते, इतने पहले कराने की की क्या आवश्कता हो गयी है? अब तक तो मुझे कोई शक नही था परन्तु अब मुझे शक हो गया कि यह राज अब जाने वाला ही है। इससे ते यही पता लगता है कि यह राज किसी वक्त चला जाये। ये सड़के बडक्रके जो कुछ कार्यवाही कर रहे है, ये इसी खतरे को देखते हुए कर रहे है।

खान अब्दुल गफ्फार खाः हम जाने वाले नही है।

मेजर अमीरसिंह चौधरीः खान साहब यह आप नही कर सकते, यह तो मेरा अन्दाज है कुछ फैक्टस होते है, कुछ सरकमटान्शल ऐवीडैन्स होती है। सरकमटान्शल एवीडैन्स चूंकि इस तरफ की लाडी कर रही है इससे ऐसा लगता कि अब आप भागने वाले है वरना अभी से इलैक्टोरल रोल बनाने की क्या आवश्कता हो गयी थी? उपाध्यक्ष महोदया आने इस इलैक्टोरल रोल को देखा है अथवा नही मुझे तो आपका पता नही। परन्तु मैने देखा है उसमें मेरा अपना नाम कुछ है और पिता का नाम कुछ है और

गांव का नाम कुछ और ही है। जब एक एम.एल.ए. का नाम ठीक नही है तो और के नाम क्या ठीक हो सकते है? जब मैने कारण पूदा तो बताया गया ि ये साइकलोस्टाइल मशीन से सटैन्शल कटवाये है इउनसे ऐसा हो गया। जब मैने गांव की लिस्ट को देखा उसमें भी हजारों मिस्टेक और काफी कटिग्ज है। अगर आप इन लिस्टों से चुनाव करायेगे तो आपकी जीत हो चुकी। जिम्मेदार एन्यूमरेटर लगाये हुए है। उनकों सरकार ने पैसा दिया हुआ हैं कोई वजह नही कि दो लाख 16 हजार रूपया खर्च करने के बाद इलैक्टोरल रोल बकायदा न हो। आपका यह फर्ज बनता है कि ऐसे आदमियों को नोटिस में लें और उनके खिलाफ एक्शन लेने की आपकी हिम्मत होनी चहिए। एन्यूमरेटर जो आने लगाये है वे अगर गांवों और माहल्लों के ही नाम नही लिखते है या गलत नाम लिख देते है तो फिर आप उनको पैसा ही क्यों दे हो। दो लाख 16 हजार के करीब रूपया आप मांग रहे है, इसकी बजाये आप चाहे चार लाख मांग लो, लेकिन जिसके लिए पैसा मांग रहे हो वह काम तो ठीक हो। क्या जिसका वोट नही होगा वह फिर आठ आने खर्च करके फिर मेजिस्ट्रेट के सामने जायेगा कि मेरा वोट बना दो। आम और सीधे साधा आदमी तो इन सब झंझटों को नही करेगा और न ही उसकी जुर्रत ही होगी। इसलिए ये पेचीदगियां है, इनको ंदूर करों और इन्यूमरेटरल से सही काम कराओं।

उपाध्यक्ष महोदया, अब मै डिमांड नं. 19 के बारें में अर्ज करना चाहता हूं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर चाञैधरी रण सिंह मेरे

अच्छे मित्र है अैर मै समझता हूं कि वे प्रोब्लम समझने की कोशिश करते है अैर मेरी उनकी मुत्ताल्लिक बड़ी ऊंची ओपीनीयन है लेकन उनके महकमें के अन्दर कई बातों की ओर मै उनकी तवज्जोह दिलाना चाहूंगा। एक तो आपने पिछली दफा विश्वास दिलाया था और अब उसी चीज के लिए रूपयां मांगा जा रहा है। ये सायल कन्जर्वेशन के लिए वर्टे बनाते है। हमारे महेन्द्रगढ़ जिले में इन्होने लाखों रूपया खर्च कर दिया और एक कौड़ी का फायदा नही है। अब फिर 50 हजार रूपया मांग रहे है। इससे किसी किस्म का फायदा नही है, न किसान इसकों चाहते है, न ये कन्टूर के हिसार से बनाते है। तो इसका फायदा क्या है सिवाए इसके कि अफसर अपनी एग्जिस्टेस रखन चाहते है। इन आदमियों को किसी और जगह लगा दों किसान की जमीन क्यों खराब करते हो?

दूसरी चीज यह है कि अंडर ग्राउंड वाटर कोरस बना रहे है। मैने इनके आदमियों से पूछा कि क्या कर रहे हो तो बताया गया कि टयूबवैल लगा रहे है। उपाध्यक्ष महोदया, जिन किसानों ने कुंए खोदे हुए है उन कुंओं का पानी खुश्क हो गया। यह क्यो हो गया। इसका कारण यह है कि किसान कुंए खोदकर ऊपर वावेले स्ट्रेटा का पानी लैते है और टयूबवैल से नीचे वाले स्ट्रेटा का पनी लिया जाता है इनके टयूबवैल सारा पानी खीच लेते है। इनका स्टाफ लैमेन स्टाफ है और सायल कन्जर्वेशन की ट्रैनिंग ली होती है। इस काम के लिए इंजीनियर जरूर होने चाहिएं। बेसिक चीज तो इंजीनियर ही समझ सकता है। अगर मेरे सर में

दर्द है और एनासीन की गोली खा लेता हूं तो इसका मतलब यह तो नही कि डाक्टर हो गया। डाक्टर तो डाक्टर ही रहेगा। तो ये जो लैमेन स्टाफ इन्होने लगा रखा है वे चाहे अफसर है, काम करते है लेकिन इंजीनियर की जगह तो नही ले सकते। यहा तो पहले रियासतों मे होता था। हमारे महेन्द्रगढ़ के अस्पताल में डाक्टर नही था। महेन्द्रगढ़ का तहसीलदार सस्पैंड होकर पटियाला चला गया था, वह वहां से बहाल होकर आया। डाक्टर की जगह महेन्द्रगढ़ के अस्पताल में उसे लगा दिया। मैने पूछा तुम यहां कैसे तो कहने लगा कि मै डाक्टर की जगह आफीशियेट कर रहा हूं। यह रियासती घसघस खेती के महकमें में भी है मैने इनके एक आदमी से पूछा कि तुम्हारा क्या क्वालिफीकेशन है फेयर वैल (Fare Well) लगाने की तो कहने लगा बी.एस.सी. हूं। मै तो नही समझता कि एक एग्रीकल्चर का बी.एस.सी. कस तरह से इंजीनियर्ज का काम जान सकता वैसे तो मै भी थोड़ा बहुत फेयर वैल का कम कर दूंगा लेकिन मेरी नालिज लेमेन वाली नालित है। इकस काम के लिए इंजीनियर होने चाहिए। मेरे गांव में एक फार्म पर स्प्रिकलिंग इरीगेशन होती है। 5–6 होर्सपावर की मशीन की जरूरत थी इन्होने 30 होर्स पवार की मशीन ने फेंक दिया 15 मिनट में और सारी योजना फेल हो गई। मै तो कहता हूं इरीगेशन डिपार्टमैंट से इंजीनियम ले लो। उनकों डेपूटेशन के तौर पर लो और उन्हें बांधकर न रखो। हर दो साल बाद उनहें वापिस भेज दो। इस तरह अच्छे से अच्छे लोग मिल जाएंगे।

मैने इनके एक इंजीनियरसे पूछा कि तुम्हारी क्वालिफीकेशन क्या है तो कहने लगा कि एग्रीकल्चरल इंजीनियर इन टूल्ज मेकिंग। हमें क्या करना है एग्रीकल्चरल इंजीनियर इन टूल्ज मंकिंग का वह तो कसी कारखाने में होना चाहिए। हमें तो बोरिग का इंजीनियर चाहिए इंजीनियमर इन टूल्ज मंकिग को क्या पता कि बोरिग प्रेशर क्या होता है। चौधरी रणसिंह जी आपके महकमें के अन्दर यह चीज हो यह ठीक नही है। ये लोगा पाइप इस्तमाल करते है। गुजरात टाइप पाई 9 इंच का एक रूपया प्रति फुट आता है लेकिन सायल कन्जर्वैशन में ये लोग इस्तेमाल करते है। 2.10 प्रति फुट वाला 12 इंज के पाइप हमारे इरीगेशन वाले इस्तेमाल करते है। 1.50 रूपया प्रति फुट वाले और ये किसानों को लगाते है 3.31 रूपया प्रति फुट के हिसाब वाले, एक और पाइप 18 इंच का इरीगेशन वाले बनाते है उनका भाव 2.25 रूपया है लेकिन इस्तेमाल करते है 7.4 रूपये प्रति फुट वाला। एकाउन्टस वालों देख लो यह रूपया सब आपके खजाने से जाता है। मैने इनके आदमियों से पूछा इतना फर्क क्यों है तो कहने लगे कि उनके पाइप कच्चे होते है और हमारे पक्के। जब सरकारी टयूबवैल उन सस्ते पाइपों को इस्तेमाल करते है तो इतने महंगे यह लेकर क्यों किसान को बरबाद करते है।

उपाध्यक्षा: आपका टाइम खत्म हो गया अब खत्म कीजिए। इधर से तो आज किसी ने नही बोला।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः बस एक महकमा और रह गया है।

श्री मंगल सैनः उपाध्यक्ष महोदया, मेरी रिक्वैस्ट है कि इन्हे ही बोलने दे। बोलो मेजर साहब, बोलो।

उपाध्यक्षाः डाक्टर साहब, क्या आप मेरा भी काम करने लगे है।

श्री मंगल सैनः मेरी तो यह रिक्वैस्ट थी। हमारा काम रिक्वैस्ट करना है और आपका काम रूलिंग देना है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः अब आप लीजिए एनिमल हस्बैन्डरी का का महकमा। मै समझता हूंकि यह महकमा बहन जी के पास है। इनके पास शायद बकरी भी नही होगी। इन बेचारी बहन जी को एनिमल हस्बैन्डरी का क्या पता? जैसे मुझ से कोई शहर की बात पूछे तेा मुझे क्या पता शहर की बात का मुझे तो गांव की बात का पता है। मुझ फौज की बता का पता है कि गोली कैसे चलाई जाती है। कोई आदमी जमीन की बाबत जानता तो है नही उससे पूछ लो कि जमीन की किस्म कितनी होती है। क्या बताएगा? तो श्री बंसी लाल जी मै अर्ज करूं कि महकमों की तकसीम ऐसे करों जिन लोगों को उस लाइन का पता हो। अब मै असी इशू पर आते हुए एक बात की ओर तवज्जोह दिलाउंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनिमल हस्बैडरी अफसर होते है। लेकिन इन्हौने अलग–अलग रियासते ंबन रखी है। इस महकमें के अन्दर

ए.आई. का अलग महकमें है यह इते ही फिजूल है जितने कि परिवार नियोजन। बेकार रूपया खराब किया जा रहा है। ए.आई. की बता आपके सामने रखू। ये अंग्रेजी किस्म की जरसी ब्रीडिग के लिए जो काम कर रहे है उनसे पूछो कि कितने डंगर को सर्विस दी और नतीजा क्या रहा, आपकों एक बछड़ी भी नही मिलेगी। मैने एक सीमैन मैसेन्जर का डब्बा खुलवा कर देखा, बिल्कुल खाली। कहने लगा आज बुल की सेहत ठीक नही थी। मैने कहा तू काहे को आया गांव में तू भी वही रह जाता। दादरी के डाक्टर का रेफरीजेरेटर खोल कर देखा तो पया कि उसमें जूते रखे है। चौधरी साहब यह डिप्टी कमिशनर की मुकर्रर की हुई कमेटी की प्रोसीडीग्ज के अन्दर है। मेरा कहना यह है कि जैसे आपने इलाज करने वाले अलग और ए.आई. के डाक्टर अलग रखे है, इन दो दो की जरूरत नही, एक जगह पर एक ही डाक्टर रखिए। ए.आई. को इसके अन्दर मर्ज कर दीजिए। बहुत खा लिया। इस लूट को अब बन्द कर दो। अगर यह महकमा आप एफीशिऐंट नाना चाहते है तो उसे अन्दर जो फजूल के आदमी रखे हुए है वे बेकार में रखे हुए है क्योकि वे कुछ काम करते ही नही। बाकी जो डिप्टी–विप्टी वगैरा है, वे भी बिल्कुल बेकार है। इस सम्बन्ध में मै कुछ सुझाव देता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, आज हम दूध बढ़ाने की कोशिश कर रहे है लेकिन यह सरकार इसमें सफल नही हो रही है। आज हालत यह है कि जमीन को होल्डिंग छोटा होता जा रहा है और अगर इस सम्बन्ध में उनकी यही हालत रही तो कुछ दिनों बाद हम इसके लिए बैल अफोर्ड नही कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने

गऊ माता को रखना है तो जब तक आप गऊ माता का दूध नही बढ़ायेगे तब तक कुछ नही हो सकता। इसके लिए मै गुजारिश यह करूंगा कि जरसी और थरपारकार किस्म की गऊओं की तरक्की करों जरसी को हमारे हरियाणा वाले शुरू में एक्सैप्ट नही करेगे, लेकन थरपाकर का एक्सैप्ट करेगे। उसका जो बुल है, वह हरियाणा जैसा ही है। सिर्फ सलो स्पीड है और कोई फर्क नही। उसकों आप अपना लें। मैने एक बार पूछा कि हमारे महेन्द्रगढ़ में आप उस थरपारकार नसल को क्यो नही तरक्की देते, तो कहते है कि सरकारी हुक्म नही है। अगर हम गऊओं को कवर करने के लिए थरपारकार बुल चाहें तो सरकार कहां पिक्चर में आ जाती हैं इसके अन्दर सरकार भी यह नही दिल्ली वाली सरकार। यह देखो, कितने रजवाड़े बना दिये, ऐसा नही होना चाहिए हरियाणा में जब आप समझते है कि 5 एकड़ का होल्डिग हो गया, जब अब तो आपकों बछड़ी की कीमत बनानी चाहिए। मैने पालमपुर के अन्दर देखा कि वहा बछड़ी वैसे तो कोई मुक्त भी न लेकिन जा जरसी की ब्रीड वाली बछड़ी है, वह तीन–तीन सौ रूपये के अन्दर बिकती है। इस तरफ से आप इसकी उन्नति कीजिए।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदया, मै आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने और मैम्बर साहबन ने मेरी टाइम के लिए बहुत सहायता की। मै सरकार से उम्मीद रखूंगा और विशेषकर बहिन जी से दरख्वास्त कर दूं कि उनके आने से पहले बजट के सम्बन्ध में मैने बहुत टीका टिप्पणी की है, मै चाहूंगा कि आप चाहे आफिशियल

नोट वालों से पूछिए या उसे पढ़ ले, वैसे मैने आपके खिलाफ कुछ नही कहा। हो सकता है कि आप यह कर देगी कि ये तो डिवैल्पिग स्टेट है, यह तो होता ही है। हो सकता है अगर मै आपकी जगह होऊं तो मै भी यही कहूं, लेकिन डिवैल्पिग स्टैट में भी कुछ असूल होते है। दो और दो चार होते है। डिवैल्पिग स्टेट हो या बगैर डिवैल्पिग स्टेट, दो और दो चार तो रहने दीजिए, पांच न बनाइये या तीन न कीजिए। मै कहूंगा कि आप किसी मुहासबे के असूल के सथ चलिए। इस हिसाब रखने वालों की जो केताही है, उस पर भी कन्ट्रोल कीजिए तब ही अक आगे बढ़ सकेगे। फिर हरियाणा आगे बढ़ सकेगा नही तो अगर धक्कापायी हुई, जैसे अगर चौधरी रणबीर सिंह ने जोर डाला दिया तो सांघी तक सड़क बनवा दे अगर मैने जोर डाला दिया तो आप ने महेन्द्रग्रढ में सड़क बनवा दे, तो इस तरह से कमा नही चल सकेगा। आप प्लान बनाइये, मैरिट के ऊपर चलिए..... (विघन) इन्ही शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, मेजर अमीर सिंह जी ने शुरू में जो सुझाव दिये है, वे मेजर साहब के अपने नही बल्कि एस्टीमेंट कमेटी के है, पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के है जिनके अध्यक्ष बहिन चन्द्रावती जी अैर हमारे बुजुर्ग खान अब्दुल गफ्फार खां जी है। जहां तक बजट का सवल है कुछ चीजें ऐसी होती है जो अचानक आ जाती है जेसे बाढ़ है या कोई फसले फेल हो जाती है लेकिन कुछ चीजों का तो उन्हें ज्ञान है।

काम करते है और उसमें भी ऐसा पैसा ठीक वक्त पर नही मांग सकते इसलिए दोबारा मांगा जाता है। यह कोई अच्छा तरीका नही है लेकिन यह तरीका कोई आज से नही पहिले से ही चला आता है। जो भी वित्हा मंत्री इस तरीके में सुधार करने में कामयाद होगा, प्रदेश उसका धन्यावादी होगा। इसमें एक ही बात में कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी मोटी रकम है। जुई नहर की वह जो योजना चलाई थी, उसका खर्चा पहिले लिखा जा सकता था। उसके बारे में अच्छाई या बुराई के बारे में तो मै आगे नही आऊंगा। बजट कैसा होना चाहिए उसी सिलसिले में कुछ कहता हूं कि सप्लीमैन्ट्री बजट कम से कम आने चाहिएं और मजबूरी मं ही आने चाहिए। वित्त विभाग की सुस्तियों की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैन्ट की सुस्तियों की वजह से, ठीक वक्त पर मांग वित्त मंत्रालय के पास नही पहुंचती और उसके बनिा पर अगर इस सदन को फिर दोबारा एक बिल पास करना पड़ता है तथा इस तरह इस प्रदेश के ऊपर ख्वामखाह पैसे का ज्यादा बोझ पड़ता है, तो सरकार को उसकों बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, चूंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिए मै अपने हल्के के बारें में कुछ बातें कहूंगा। मेजर साहब ने दस नम्बर डिमान्ड का जिक्र करते हुए औरपुलिस की डिमान्ड का जिक्र करते हुए फायरिग के बारमें में जिक्र किया। मुझे मालूम नही कि जो भी उन्होने कहा है वह दुरूस्त है या नही, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हय सत्य है तो यह बहुत बड़ा अन्याय

हरियाणा के लोगों के साथ हुआ है। हमें उसकों रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पण्डित जवाहर लाल नेहरू के शब्द साद आते है जबकि यहां पर 75 हजार आदमी गिरफ्तार हुए थे। लाखों की तादाद में जूलस निकला था। उस वक्त कोई आदमी भी नही मरा था लेकिन गोली चली थी। पण्डित जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे ''मुझको शायद यह सोचना पड़ेगा कि पुलिस के हाथ से गोलिया और बन्दूक जो है वह छीन ली जाय और उनको लाठी दी जाये। तो अगर मेजर साहब की जो बात है, वह सत्य है तो ऐसे आदमी जिनकों प्रजातन्त्र में बन्दूक का प्रयोग कैसे करना चाहिए कब करना चाहिए, गोली कब चलानी चाहिए, यह ज्ञान नही, तो उनको नौकरी में रखने का किसी सरकार को अधिकार नही है और न ही ऐसे भाईयों को नौकरी में रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया इसके बाद डिमाड नं. 46 के सिलसिले में कुछ जिक्र करना चाहता हूं। मेजर साहब ने सड़कों की बात की है। अब तो हमें भी डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ पछतावा होता है क्योंकि जिस तरीके से काम चलता है, वह प्रशंसनीय नही है। ऐसा लगता है कि हमकों हमारे देश का ओर प्रदेश का प्यार जो था, वह कोई सही नही था। मुझे याद है कि जब मैने सिचाई और बिजली विभाग का मंत्रालय लिया, उस वक्त हमे आजाद हुए 10 वर्ष हो गये थे, 18 नहरों की खुदाई हो चुकी थी। मगर उनमें एक चुल्ली भर पानी नही चला था। मैने उसमें

पानी चलवाया हालांकि उनमें से एक भी नहर मेरे हल्के की सिंचाई नही करती थी। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश में बिजली बोर्ड को यह सिंचाई विभाग आदि को क्या घाटा होता है? यह एक सोचने की बात है। मुझे भगवान की दया से बड़े अच्छे अच्छे इन्जीनियरों के साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन एक बात मैने अजीब जो उनमे ंपाई वह यह है कि वे सैटअप के साथ बदलते है। जब मै मिनस्टिर बना तो मैने देखा कि लोकसभा के मैम्ब्र की हैसियत से मैने जो कोई चिट्ठी लिखी थी, उस पर भी एक्शन होना शुरू हो गया जबकि पहले 5 सा 10 साल में और कोई एक्शन नही लिया गया था। आज उपाध्यक्ष महोदया, मेरे 668 सवाल का जवाब दिया गया। आज से छः महीने पहले सदन की मारफत मैने निवेदन किया था कि सुन्दरपुर और खिडवाली सड़क के लिए एक लाख बत्तीस हजार रूपया लोगों की तरफ से मार्किट कमेटी ने जमा करवाया था ताकि वह सड़क बन जाए मगर अफसोस है कि आज तम उसके ऊपर कोई कार्यवाही नही हुई। उपाध्यक्ष महोदया, इसके बारमें में चीफ इन्जीनियर ने चिट्ठी लिखी थी और एक्सीयन ने उसका उत्तर दिया था जिसमें लिखा था कि एक लाख बत्तीस हजार रूपया मार्किट कमेटी ने तो दिया लेकिन जिला परिषद का नही आया। आज सवाल के जवाब में बिल्कुल कोरा ही जवाब है, सड़क का बनाना तो दूर रहा। मै जानना चाहता हूं कि जब मेरे गांव के अन्दर बारह हजार रूपया एक फर्लांग सड़क बनाने के लिये लोगो ंने जमा किया है ते क्यों उसके ऊपर तीन वर्ष बाद भी एक इंच मिट्टी नही पड़ी। उपाध्यक्ष

महोदया, मेरा एक तरीका रहा है कि सरकार के मन्जूरी के तरीके से जो काम नही होता है, उसको कभी मैने मंत्री बनने के नाते भी नही कराया। लेकिन इसके बावजूद भी अफसोस है कि तनी वर्ष से जिन कामों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल सरकार ने दे रखी है, उसके ऊपर अभी तक कोई काम नही हुआ है। मुझे मालूम नही है, किसकी हिदायत से यह काम चलता है या ये अफसर क्या समझते है? ये प्रदेश सरकार के मुलाजिम है या कसी और ढंग से चलने के आदि है, यह भी देखने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदया, मेजर अमीर सिंह, जी ने दादरी फीडर जिसके ऊपर पच्चीस लाख रूपये खर्च हुआ था, का जिक्र किया। आज के वित्त सचिव जब यह स्कीम मन्जूर हुई थी, बिजली और सिचाई के सचिव थे। आपकों यह जानकार ताज्जुब होगा कि इस में सिर्फ छः फुट की लिफ्ट लगती थी और इसके सांधी के लिये पानी नही आना था, रोहतक जिले के लिये पानी आना था, जहां से उस समय बिजली और सिचाई विभाग का मंत्री पैदा हुआ था और न ही अमृतसर में पानी जाना था, जहां का उस समय का मुख्यमंत्री था। पानी जाना था महेन्द्रगढ़ के टीबों पर। लेकिन इस पर भी अगर यह सरकार यह सोचती है कि उसकों 24 लाख रूपया खर्च होने के बाद छोड़ा जाए या लिया जाए तो यह हमारे प्रदेश के लिए बड़ी शर्म की बात है। डिप्टभ स्पीकर साहिबा, महेन्द्रगढ हमारे प्रदेश का हिस्सा है इकसों भी इसका हक मिलना चाहिए।

DISCUSSIONON DEMANDS FOR SUPLEMENTARY ESTIMATES

(SECOND INSTALMENTS)

उपाध्यक्ष महोदया, मै चाहता हूं कि जूई नहर जो कि हमारे मुख्य मंत्री के अहद मे बननी शुरू हुई है, वह उनक समय में ही पूरी हो जाए, वरना मुझे आशंका है कि जितना रूपया उसके ऊपर लगा, वह सरकार का जाया होगा और उसके अन्दर कोई पानी नही बहेगा। इसलिए मै आपकी और सदन की मारफत उनसे कहना चाहता हूं कि वे इस बात क बारमें सर्तक रहे। अगर यह काम पूरा नही हुआ, तो यही जो भाई हमारे बड़े इन्जीनियर और सलाहकार है, जो आज कहते है कि 24 लाख रूपये की नहर बन गई ये ही दूसरी सरकार आने पर इसे नही चलायेगे और कहेगे कि साहिब गलत हो गया क्योंकि पिछली सरकार दवाब से करा गयी थी उपाध्यक्ष महोदया, इसलिए सरकार को घाटा होता है प्रजातन्त्र में सरकार को एक तरीके से चलना चाहिये, एक तरीके से नहरों को चलाना चाहिये। सरकारे आती है, जाती है, राव बीरेन्द्र सिंह भी मुख्य मंत्री हुए, पंडित भगवत दयाल भी हुए। चौधरी बंसी लाल भी है और पहले भी कई हुए। कम से कम 50 मंत्रीगण हरियाणा के आए और गए। आवागमन संसार का कायदा है और जब आवागमन सरकार का कायदा है तो खासतौर पर उन भाईयों को ख्याल रखना चाहिए जो पच्चीस साल तक नौकरी करने के बाद पैशन की ख्वाहिश रखते है।

लेकिन होता इसके विपरीत है। मै तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा पहले अर्ज किया, दरख्वास्त से काम करवाता हूं। जब मै लोकसभा का मैम्बर था तब भी दरख्वास्त भेजा करता था और अभी भी जबकि मै सदन का मैम्बर हूं, ऐसा ही करता हूं पिछली दफा सदन में मैने दरख्वास्त की थी कि 1,32,000 रूपये का गमन हो गया है लकिन उसका कोई उत्तर नही है कि वे रूपये कहां गये? सड़क बनाना या न बाना दूसरी बात है। लेकिन सदाकत से इन्कार करना इस सदन की बेइजती है।

उपाध्यक्ष महोदया, सैक्रेट्ररी जिला परिषद, रोहतक का मुकदमा था, मैने चिट्ठी लिखी मगर नही मानी गई लेकिन अब सरकार के खिलाफ डिग्री हो गई और वह जीत गया। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदया, हरिजन कल्याण फण्ड का यहां जिक्र है (विघन)

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आपका टाइम हो गया है, अगर हाउस एक्सटेंड करना है, तो आप टाइम ले सकते है। मैने जो डिमान्टज पास करवानी है, उसके लिये मैने आधा घण्टा रखना है। आधे घण्टे के लिए मैने गिलोटिन लगाना है, क्योकि फाइनैस मिनिस्टर ने भी बोलना है।

मेजर अमीर सिंह चौधरीः डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, क्या हुक्म है।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आप 4 मिनट और बाल सकते है।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, नहरों की सफाई की यहां बढ़ी कहानी सुनाई गई। मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, हकीकत यह है कि जमुना नहर के अन्दर साल में सिर्फ 60 दिन इतना पानी चलता है जो 10,000 क्यूसिक, जोकि नहर की कपेसिटी है, उससे अधिक होता है लकिन उस वक तभी इंजीनियर महोदया कहते है कि उसकों बन्द कर दिया जाए उन दिनों में जिन दिनों यमुना में 50 हजार क्यूसिक से पानी अधिक है क्योंकि यमुना मे रेत ज्यादा है। अगर उसको बहा दिया जाए तो वह नहर भी अन्ट सकती है और बन्छर भी हो सकती है। उन साठ दिनों को छोड़कर इरीगेशन मिनिस्टर साहब या सिंचाई विभाग पता करके साबित कर दें कि कभी छः हजार क्यूसिक स ज्यादा पानी हमारे हिस्से में आया तो मै सारी बातें उनकी कबूल कर सकता हूं। दो महीने के अलावा कभी 6,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी नही बहता। उपाध्यक्ष महोदया, सही बात का पता न कर के यह जो स्वप्न देखे जाते है और मन्त्रियों से और अपने ढंग से जो कार्यवाही करवाई जाती है, यह कोई अच्छी बात नही है, अच्छा तरीका नही है।

इकसे अलावा उपाध्यक्ष महोदया, मै फैमिन रिलिफ के सिलसिले में बात करनाचाहता हूं। यह वित्त मंत्री महोदया का महकमा है हमारे दामड़ गांव में पिछली दफा खराब लिखा गया

और उगाई मुलतवी कर दी गई लेकिन अब वहां पर बाढ़ आ गई। पिछली उगाई तो अभी तक मुलतवी कर दी गई लेकिन अब वहां पर बाढ़ आ गई। पिछली उगाई तो अभी तक वसूल नही हुई और अब आगे की उगाई का भी पता नही क्या होगा। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा ये कुछ कारण है जिनकी वजह से सरकार को घाटा रहता है।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आप अपना भाषण खत्म करें, वरना हाउस को एक्सटैन्ट करना पड़ेगा।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, डिमाड नं. 19 के तहत रोहतक जिले क अन्दर दवाई छिड़की गई। मुझे खुशी है कि वहां फसल तो बच गई, लेकिन वहां, जो शूगर फैक्ट्रिया है, उन फैक्ट्रियों में, 10 मील के अन्दर अन्दर पड़ने वाले गांवों का गन्ना नही लिया जाता हैं अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे अफसोस है कि वे फैक्ट्रियां कैसे अच्छे ढंग से चलेगी और किस तरह से वहां काम होगा। अगर कोई सरकार इक्नौमिक फील्ड में भी किसी को आनी नही बना सकती तो वह अच्छे ढंग से नही चलेगी। (विघन)

उपाध्यक्षाः आज खत्म कीजिए, इसके बात वित्त मंत्री महोदया ने भी बोलना है।

चौधरी रणबीर सिंहः बहुत अच्छा जी, अगर आपकी आज्ञा है तो मै इतना कहकर ही बैठ जाता हूं।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, सप्लीमेंट्री ऐस्टीमेंट्स पर आज जो बहस चल रही है उसमें कुछ मैम्बर साहबान ने बहुत अच्दे सुझाव दिए है। और अपने इलके की तकलीफात का इजहार किया है। यह सही बात है कि सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेंटस 6 करोड़ से ऊपर के है। और इस परयह नुक्ताचीनी की गइ है कि इतनी बड़ी रकम सप्लीमैटरी ऐस्टीमैट्स के जरिए हाउस से नही मांगनी चाहिए थी। डिप्टी स्पीकर साहिबाा, जब हमारा पिछला बजट पास हुआतो उस और आज के दमम्यान कुछ ऐसा खर्चा करना पड़ा जो हमारी स्टेट के डिवैल्पमैंट के जिए जरूरी था। उसके बाद ही हमने नैशनलेलाइजेशन आफ ट्रांस्पोर्ट का फैसला किया और फरवरी मे जो कहत पड़ा था वह आगे भी कंटीन्यूट रहा जिसक`लिये आगे भी इंतजाम करना पड़ा।

मेजर अमीर सिह चौधरीः कैथल में था फैमिन?

श्रीमती ओमप्रभा जैनः नही फैमिन वहा नही था।

(अध्यक्ष पदासीन हुए)

इस तरह स्पीकर साहब, स्टेट की डिवैल्पमेंट और जरूरियात को देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि लोगों के लिए और खासकर किसानों के लिए सरकार सुविधाए उपलब्ध करे। साथ ही इरीगेशन के लिए भी चैनल्ज बनानी थी, और पिछले साल हमने महंगाई भताा बढ़ायाथा और ये स्केल रिवाइज किए थे, उससे जो सरकार पर बोझा पड़ा उसको भी शामिल

करना पड़ा था। स्पीकर साहब, एक बात मै हाउस के नोटिस में लाना चाहतती हूं कि इस 6 करोड़ और 62 लाख की रकम में से 214 लाख रूपया बुक ऐडजेस्टमेंट है यह बुक ऐडजेस्टमेंट फाइनेंस में हुआ करती है और कुछ पैसा डिप्रिशिएशन फंड में ट्रांस्फर करना होता है। तो नेट बोझ जो हमारे सप्लीमैटरी ऐस्टीमेंट्स पर पड़ा है वह 384 लाख का है। एक करोड़ 9 लाख की इजाजत पिछले बजट में ली थी ओर उसे बाद 4 करोड़ 95 लाख खर्च किया है जो कि लोगों की भलाई के लिए और जमाम फकिसलिटिज को इम्प्रूव कराने के लिए लगा है।

स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने यह गौर नही किया कि कैनाल सिस्टमें डिसिलटिग करने की भी जरूरत है और न ही टयूबवैल के बारमें में पिछली सरकार ने कभी सोचा कि हरियाणा के लिए कुछ किया जाना चाहिए और सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए मगर यह जनता कीसरकारथी इसनेयह महसूस किया कि प्रावीजन करना चाहिए और जनाब स्पीकर साहब हमें यह कहते हुए मान होता है कि हमने आने स्टेट की बेहतरी क लिए रूपया खर्च किया। हालांकि हमारी इकानामी अलाऊ नही करती थी, मगर जो काम जरूरी थे वह हर हालत में करने लाजमी थे। हमने वैस्टर्न जमाना कैनाल की डिवैल्पमैंट के लिए और टयूवैल्ज लगाने और उनकी मेन्टेनंसे और आगमेंटेषन के लिए रूपया खर्च किया। मै यहां पर बड़े गौरव से कहना चाहूंगी कि हमारे इतिहास में यह खास महत्व की बात हुई कि जिन इलाकों में सूखा पड़ता है वहां

परसरकार ने पानी ले जाने के लिए एक कैनाल बनाई है। और 3–4 महीनों के अन्दर वहां पर पानी पहुंच जाएगा अैर वह इलाका सर सब्ज हो कर हरियाणा की प्रोडक्शन बढ़ाने में मददगार होगा, और खुद के लिए भी प्रास्पर होगा। जूई कैनाल पर काफी रूपया खर्च हुआ है मगर यह जरूरी था।

स्पीकर साहब, पिछले बजट के बाद हमारे यहां कई इलीाकें कमें फ्लड्ज भी बहुत आए उसकों रोकने के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ है। ड्राट मे, और फैमिन रिलीफ में जितनी ऐसिस्टेंस इस साल गई है। उतनी पहले कभी नही दी गई।

इसी तरह से हमारी सड़कों पर बहुत ज्यादा काम हुआ है और 830 किलों मीटर के करीब सड़के मुकम्बल हुई। सरकार को कभी यह मशा नही रहा कि सड़के बने और अधूरी पड़ी रहें इसलिए काम तेजी के साथ हुआ ओर उसके लिए लाजिमी था कि खर्च करना पड़ता।

चौधरी रणबीर सिंहः जनाब यह अच्छा है कि सरकार नेय यह फैसला किया कि जा काम अधूरा पड़ा है उसे पूरा करे मगर रोहतक में भी काम पूरा किया जाए (विधन)

श्रीमती ओमप्रभा जैनः जनाब स्पीकर साहब, सड़कों के बारमें मे जो लाइबिलिटी हमने अंडरटेक की हुई है उसकी लागत 5 करोड़ सेभी अधिक की पड़ेगी और उसकों हमें पूरा करना हैं सड़कों पर काम करते हुए जो लेवन का वेजिज मिलती थी–वह

बहुत कम कोई 1 या डेढ़ रूपयारोज थी वह हमने वेजिज का भी मान मंहगाई के कारण बढ़ाया और ढाई रूपये रोज तक दिया गया। इससे सरकार पर जहां खर्च पड़ा वहां लोगों को मदद भी काफी मिली।

1 करोड़ 63 लाख रूपया मेन्टैनैस आफ टयूबवैल पर रखा और 1 करोड़ 61 लाख नए लगवाने पर खर्च किया। 72 लाख के करीब सड़कों पर लगाया। यह कुछ मेजर खर्च थे, बाकी के छोटै मोटे खर्च है। आपकों यह जानकार खुशी होगी कि हमने एक वूल ग्रेडिग सैंटर लोहारू में लगाना है, जिससे हरियाणा के अन्दर वूल प्रोडक्शन में नया चैप्टर खुलेगा और वूल मार्किट पैदा होगी। स्पीकर साहब हमें इस बात का फखर होना चाहिए बावजूद इस बात के कि हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है अगर इस का हिन्दूस्तान की दूसरी स्टेटों से मुकाबला किया जाए तो यह पहले नम्बर वाललीं स्टेट्स में से एक है। बावजूद इस बात के कि हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है अगर इसका हिन्दूस्तान की दूसरी स्टेटों से मुकाबला किया जाए तो यह पहले नम्बर वाली स्टेट्स में से एक है। बावजूद इस बात के हि में सैटर से ज्यादा मदद नही मिली हम आने रिसोसिर्ज पर खडत्रे है। अज्ञेर हम आनी स्टेट का उन्नत करना चाहते है। जहां रोशनी नही है वहां पर रोशनी पहुंचाई जा रही है, जहां सड़के नही थी वहां पर सड़कों को प्रबन्ध किया जा रहा है। अैर जहां पानी की कमी थी वहां पर पानी मुहैया किया जा रहा है। स्पीकर साहब, इस तरह से हम

पिछले 22 सालों की बैकवर्डनैस को दूर करना चाहते है। तो मै समझती हूं कि इतने बड़े कामों के लिए 6 करोड़ की रकमें कोई बहुत बड़ी नही है ओर हाउस को इसकी मंजूरी दे देनी चाहिए। आप का धन्यवाद

Mr. Speaker: Now, I will apply guillotine and put the various Demands to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 1

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,30,831 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 9-Land Revenue.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 3

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,17,780 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of 11-Taxes of Vehicles.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 6

That a supplementary sum not exceeding Rs. 19,770 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 14- stamps

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is-

DISCUSSION ON DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY ESTIMATES

(SECOND INSTALLMENT)

Demand No. 8

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,16,220 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 18-Parliament, State Union Territory Legislatures.

The motion was carried

Demand No. 9

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 19-General Administration

Demand No. 10

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,68,007 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 21-Administrationof Justice.

The motions were carried.

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 19

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 31-Agriculture.

Demand No. 20

That a supplementary sum not exceeding Rs. 19,770 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 33- Animal Husbandry.

The motion were carried.

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 25

That a supplementary sum not exceeding Rs. 38,46510 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 39-Miscellaneous, Social And Development Organisations.

Demand No. 26

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,25,190 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 42-Multipurpose River Schemes.

Demand No. 27

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,63,04,010 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 43 & 44_Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Commercial and Non-commercial)

The motions were carried.

Mr. Speaker: Questions-

Demand No. 29

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 50-Publice Works.

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 32

That a supplementary sum not exceeding Rs. 41,50,280 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending

31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 57-Road and water Transport schemes.

Demand No. 33

That a supplementary sum not exceeding Rs. 72,00,000 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 64-Famine Relief.

The motions were carried

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 36

That a supplementary sum not exceeding Rs. 709,795 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 68-Stationery and printing.

Demand No. 37

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,000 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 70-forests.

Demand No. 38

That a supplementary sum not exceeding Rs. 53,98,350 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending

31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 71-Miscellaneous.

Demand No. 39

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,350 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 76-Other miscellaneous compensation and Assignments.

The motions were carried.

Mr. Speaker: Question is-

Demand No. 45

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,61,98,970 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 99-Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

Demand No. 46

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Government to defray the Charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect, 1970 in respect of 103-Capital outlay on Public works.

The motions were carried

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1970 in respect of Loans and Advances by the State Government.

The motion was carried.

Obituary Reference

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, मै एक कंडोलैस का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। अभी अभी पता लगा है कि श्री मुहम्मद यासीन खां जो कि पंजाब में हाउस के मैम्बर होते थे स्वर्गवास हो गए है। इसलिए मै सदन से प्रार्थना करता हूं कि यहां पर शोक प्रस्ताव पास करके उसको कापी उनके घर वालों को भेज कर उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए।

खान अब्दुल गफ्फार खां (नग्गल): स्पीकर साहब, निहायत रंज और अफसोस की बात है कि हमारे साथी और एक निहायत पुराने लीडर आज हम से हमेशा के लिए जुदा हो गए है। मै चौधरी साहब को बहुत मुद्दत से जानता था। वह अपने इलाके की बेहतरी के लिए बहुत कोशिश करते रहे। चौधरी साहब ने मेवात के लिए जितना काम किया मेरे ख्याल में उतना शायद किसी और न किया हो। वह एक निहायत दलेर लीडर थे और यहां तक कि उसक वक्त जब कि अंग्रेज गवर्नर हुआ करता थ वह उन से भी दलेरी के साथ बात करने से झिझकते नही थे। उनका हमसे जुदा हो जाना हमारा एक बहुत भारी नैशनल लौस है जोकि नाकाबले तलाफी हैं हमारी दुआ है कि अल्हा ताला उनकों जन्नत

नसीब करें और हम लोगों को और उनके तमाम रिश्तेदारों को इस बात की तौफीक अदा फरमाए कि हम उनके सदमें को बर्दास्त कर सके और उनके नक्शे कदम पर चलते रहे।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): स्पीकर साहब, चौधरी मुहम्मद यासीन खां जब पाकिस्तान नही बना था उस वक्त भी हरियाणा के इलाके की तरफ से पंजाब की असैबली के मैम्बर होते थे। वह सन् 1952 में और 1957 मे ंभी असैम्बली के मैम्बर रहे। वह एक बहुत ऊंचे ख्याल के इन्सान थे और उनके अन्दर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई थी। सन् 1947 के अन्दर जब कुछ भाई हिन्दू और मुसलमान के नाम पर खून की होली खेल रहे थे उस वक्त यह एक जरनैल की तरह उठे और राष्ट्रपिता गांधी को मेवात के इलाके में ले गए और मै ता`कहता हूं कि आज जो मेवात हमारे सूबे के हिस्सेदार है यह उनकी कोशिश का ही नतीजा है। इतनी बहादुर कौम को यहां रखने में चौधरी साहब का बहुत बड़ा हाथ था, महात्मा गांधी का भी था लेकिन इनका भी बहुत था। मेवात में उनकों राजा के नाम से याद किया जाता था। दुनिया से हरेक ने चले जाना है, हमने भी एक दिन जाना है आज वह भी हमसे को जुदा हो गए है। स्पीकर साहब, जैसे खान साहब ने कहा उनके स्वर्गवास हो जाने से दिल को बड़ी चोट पहुंची हैं मै भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और उनका स्वर्गवास मे ंवास हो और हमको और उनके घर वालों

को भगवान हौसला दे कि हम उनके सदमें को बर्दाशत कर सके। जय हिन्द।

चौधरी नेकी राम (नरवाणा): स्पीकर साहब, चेधरी मुहम्मद यासीन खां की मौत का बड़ा अफसोस है। यहां पर यह बात कही गई कि वह मेवों के बहुत बड़े लीटर थे लेकिन मै कहता हूं वह केवल उनके लीडर ही नही थे वह किसानों के भी बहुत बड़े लीडर थे। अंग्रेजों के जमाने में जो उन्होने किसानों की सेवा की उसको भुलाया नही जा सकता।

और इसमें कोई शक नही है कि हमारे इतने बडत्रे और बजुर्ग लीडर की मौत से हरियाणा को नाकाबले तिलाफी नुक्सान हुआ है। मै भगवान से प्रार्थना करत हूं कि ईश्वर उनकों स्वर्ग में स्थान दे और हमें उनके लवाहकीम से पूरी पूरी हमदर्दी है।

श्री अध्यक्षः मुझे भी चौधरी मुहम्मद यासीन खां के स्वर्गवास होने का बड़ा दु:ख है और जो ख्यालात यहां पर पेश किये गये है मै उनसे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे याद है कि 1947 में मुण्े भी कुछ मौका मिला था ि मै गुड़गांव के ला एंण्ड आर्डर का इन्चार्ज था। मुझे यह भी याद है और जो कुछ हुआ वह सब को मालूम है और मेरा ख्याल है कि उन सबा बातों के कहने की यहां जरूरत नही लेकिन मै यह बातना चाहता हूं कि उन दिनों ताउडू के मकाम पर एक बड़ी भारी पंचायत हुई जिसमे कई हजार बुजुर्ग भाई इकट्ठे हुये और मुझे अब तक याद है कि उस पंचायत के

कामयाब कराने में यासीन साहब का बड़ा भारी हाथ था जिसके कारण खून खराबा बंद हुआ और बहुत सारे भाईयों का जानी और दूसरा नुक्सान जो हो सकता था वह बच गया। मै मैम्बर साहबान से अपील करूंगा कि हम उनकी याद में दो मिनट के लिये मौन खडे हो जाये।

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased)

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2-00 P.M. on Monday, the 23rd February, 1970.

12.51 P.M.

(The Sabha then adjourned till 2-00 P.M. on Monday, the 23rd February, 1970)